राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 9 अंक 49

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, बुधवार, 30 जुलाई, 2025

www.jagran.com

पृष्ठ 14

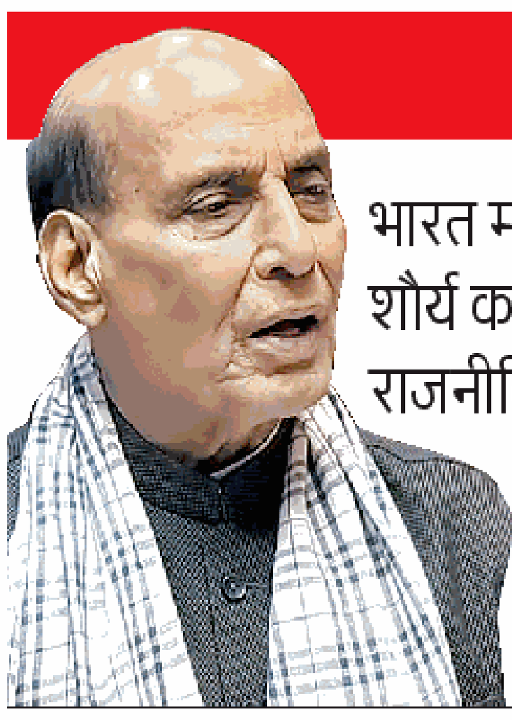

भारत माता की मांग में शौर्य का सिंदूर, न डालें राजनीति की धूल

›› 3

जागरण विशेष

जो कभी था नशे का कैदी, वो अब दिला रहा नशे से मुक्ति

गुरदासपुर : कभी नशे की गिरफ्त में फंसे गुरदासपुर के पंकज महाजन अब स्वयं नशामुक्ति के लिए युवाओं की प्रेरणा बन कर उभरे हैं। ● पेज-7

संपादकीय

युवाओं की प्रतीक्षा करती राजनीति: राजनीतिक दलों और उम्रदराज नेताओं के बीच स्व-नियमन की कोई राह तलाशी जाए, जिसमें वरिष्ठ नेताओं के अनुभव के साथ ही युवाओं की ऊर्जा एवं नए सोच को भी राजनीति में सही जगह मिले। **राहुल वर्मा** का आलेख।

एडीएम को अंग्रेजी बोलना जरूरी क्यों है : यह उत्तराखंड ही नहीं, देश का दुर्भाग्य है कि किसी अधिकारी का अंग्रेजी न बोल पाना उसकी अक्षमता समझी गई। **राजीव सचान** का दृष्टिकोण। ● पेज 8

विमर्श

गंभीर चुनौती बनता भीड़ प्रबंधन: यदि हमने अब भी पिछली त्रासदियों से सबक नहीं लिया, तो भगदड़ की घटनाएं होती रहेंगी। **डा. मोनिका राज** का विश्लेषण।

व्यापारिक संबंधों में नया अध्याय : भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापार समझौता दोनों के रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी संबंधों को मजबूती देगा। **डा. सुशील कुमार सिंह** का आकलन। ● पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग

सेहत भरे जीवन का

क्यों कमजोर होने लगीं बच्चों की हड्डियां

हाथों-पैरों में दर्द का समझें संकेत

● पेज-13

विश्व के किसी नेता ने भारत को आपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा

ट्रंप के दावे पर मोदी की खरी खरी, कहा- वेंस के आगाह करने पर पाक को करारा जवाब देने की कही थी बात

लोकसभा में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब

- कहा, पाकिस्तानी प्रपंच के प्रवक्ता बन गए हैं कुछ नेता, कांग्रेस वहां से आयात कर रही मुद्दे
- पहले से निर्धारित लक्ष्य को 100 प्रतिशत हासिल करने के बाद ही स्थगित हुआ आपरेशन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जिस बयान के सहारे विपक्ष कई दिनों से सरकार को घेरने की रणनीति बनाए बैठा था, मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उसे ध्वस्त कर दिया। लोकसभा में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा, 'दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को आपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। भारत ने सौ प्रतिशत लक्ष्य हासिल होने और पाकिस्तान की गुहार के बाद आपरेशन रोका।' उन्होंने पूरा ब्योरा दिया और उस वक्त सामने बैठे विपक्ष में चुप्पी थी। हालांकि उसके बाद बाहर और दूसरे सदन में भी विपक्ष का रवैया नहीं बदला।

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने नौ मई की शाम तीन-चार बार फोन किया था, लेकिन मीटिंग में व्यस्त होने के कारण एक घंटे बाद उनसे बात हो सकी थी। वेंस ने पाकिस्तान द्वारा बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी के बारे में आगाह किया था। प्रधानमंत्री के अनुसार, उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को उसी समय साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान का यह इरादा है, तो उसे यह बहुत महंगा पड़ेगा। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन करके आपरेशन रोकने का आग्रह किया था।

लोकसभा में मंगलवार को आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बोलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। एएनआइ

राहुल के आरोप

- भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया?
- मोदी सरकार के पास राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है।
- सेना को खुली छूट मिलनी चाहिए, पूरी आजादी होनी चाहिए।
- आइएनडीआइए के सभी नेता एकजुट होकर सरकार के साथ थे।
- आसिम मुनीर ट्रंप के साथ लंच कर है, यह न्यू नार्मल है?
- सदन में कह दीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम नहीं करवाया।

मोदी के जवाब

- दुनिया के किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से नहीं रोका था।
- अब कोई परमाणु ब्लैकमेलिंग काम नहीं करेगी।
- सेना को कार्रवाई करने की खुली छूट दी गई।
- दुर्भाग्य है दुनिया के देशों ने तो समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला।
- हमने बता दिया है, भारत पर हमला करोगे तो घुसकर मारेंगे, यह है न्यू नार्मल।
- दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से आपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा।

आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बाद ही पाकिस्तान को दी जानकारी

आपरेशन सिंदूर बीच में रोके जाने के विपक्ष के सवालों पर हैरानी जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लगभग 102 मिनट के जवाब में कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का था और छह-सात मई की रात को 22 मिनट में नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बाद यह पूरा हो गया था और इसीलिए पाकिस्तान को भी इसकी जानकारी दे दी गई। अगले ही दिन सेना की ब्रीफिंग में यह साफ किया गया कि भारत की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के किसी दुस्साहस का जवाब दिया जाएगा, जो नौ-दस मई की रात को दिया भी गया। पाकिस्तान का परमाणु ब्लैकमेल नहीं चलेगा। मोदी ने कहा, आतंकियों को ऐसी सजा मिली कि उनके सरगनाओं की रातों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान पहलगाम हमले के जरिये भारत में दंगे कराना चाहता था, उसके इस प्रयास को देश की एकता ने विफल कर दिया।

आतंकी व उनके आकाओं को रोते देखकर यहां भी रो रहे कुछ लोग पेज››3

पहलगाम का बदला पूरा : शाह

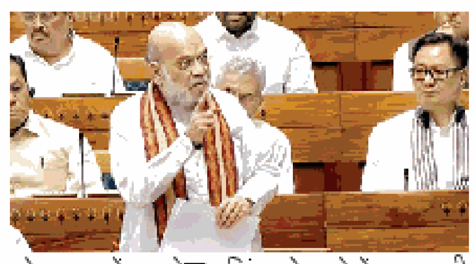

लोकसभा में आपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देते गृह मंत्री अमित शाह। एएनआइ

- बेगुनाह पर्यटकों को मारने वाले तीनों पाकिस्तानी आतंकी ढेर, दिए पाकिस्तानी होने के सुबूत
- मोदी ने किया था हमला करने वाले और उनके आकाओं दोनों को जमींदोज करने का एलान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद सुरक्षा बलों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले तीनों आतंकियों को 'आपरेशन महादेव' में ढेर कर दिया है। आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मारे गए तीनों आतंकियों- सुलेमान उर्फ फैजल जट, हमजा अफगानी और जिब्रान के पहलगाम हमले में शामिल होने के साथ ही पाकिस्तानी होने के भी सुबूत दिए। ध्यान देने की बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों और उनके आकाओं को जमींदोज करने का एलान किया था। शाह ने कहा कि अब पहलगाम का बदला पूरा हो गया।

शाह ने बताया कि इन तीनों आतंकियों के पहलगाम में हमला करने में शामिल होने और पाकिस्तानी होने की पुष्टि के लिए कई स्तरों पर जांच की गई। घटनास्थल से मिले कारतूसों व इनके पास मिली राइफलों की सीएसएफएल चंडीगढ़ में जांच कराई गई। छह फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इस बात की पुष्टि की कि पहलगाम में मिले खाली कारतूस और इन राइफलों की टेस्ट फायरिंग के कारतूस समान हैं। पहलगाम में मदद करने वालों ने भी इन तीनों आतंकियों की पहचान की। दो आतंकियों के पास से उनके पाकिस्तानी मतदाता पहचान पत्र भी मिले हैं। जाहिर है कि सभी जांचों में तय हो गया कि ये तीनों वही आतंकी थे।

हमले के दिन ही तय हुआ कि आतंकियों को नहीं भागने दिया जाएगा पाकिस्तान पेज››3

अगर बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से लोग बाहर हुए तो करेंगे हस्तक्षेप : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा- मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होने के बाद अगर उसमें गड़बड़ियां लगें तो कोर्ट को बता सकते हैं, कोर्ट उन्हें सुनेगा

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में मंगलवार को स्पष्ट हो गया कि बिहार में चल रहा मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान जारी रहेगा और चुनाव आयोग तय कार्यक्रम के मुताबिक काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और यह माना जाएगा कि वह कानून के अनुसार काम करेगी। इससे साफ है कि एसआइआर के तय कार्यक्रम के मुताबिक ही एक अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की न्यायिक निगरानी कर रहा है। अगर मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोग बाहर हो गए तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार में एसआइआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नियमित सुनवाई के लिए 12 और 13 अगस्त की तिथि तय कर दी।

ये मौखिक टिप्पणियां मंगलवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बाग्ची की पीठ ने बिहार में एसआइआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नियमित सुनवाई की रूपरेखा तय करते हुए कीं। सोमवार को कोर्ट ने मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण की जारी प्रक्रिया पर रोक लगाने और मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित करने पर रोक से इन्कार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं जिनमें एसआइआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की गई है।

कोर्ट के निर्देश पर मंगलवार को सभी पक्षकारों, याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग की ओर से वकील पेश हुए और उन्होंने बहस में लगने वाले समय की संभावित टाइमलाइन पेश की।

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था और माना जाएगा कि वह कानून के मुताबिक काम करेगी

याचियों की आशंका पर कोर्ट ने सुझाया विकल्प

सिब्बल ने जब चुनाव आयोग की ओर से पूरी जानकारी नहीं देने की बात कही तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा आयोग संवैधानिक संस्था है और यह माना जाएगा कि वह कानून के मुताबिक काम करेगी। अगर कोई गड़बड़ होती है तो याची कोर्ट आ सकते हैं, कोर्ट उन्हें सुनेगा। एक अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी, आप उसे देखकर 15 ऐसे लोगों को चिह्नित करके कोर्ट को बताइए जिन्हें मृत बताया गया है और वे लोग जीवित हैं। कोर्ट विचार करेगा।

इसी दौरान याचियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका जताई। भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक 65 लाख लोगों ने मतदाता सूची में शामिल होने के लिए गणना फार्म नहीं भरा है, ये लोग या तो जीवित नहीं हैं या फिर स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में लोगों को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

गुजरात दंगों में दोषी ठहराए जाने के 19 साल बाद सुबूतों के अभाव में तीन लोग हुए बरी

- गुजरात हाई कोर्ट ने कहा- दोषसिद्धि विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित नहीं
- फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच साल के कठोर कारावास की सुनाई थी सजा

अहमदाबाद, प्रेट्र : वर्ष 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा तीन लोगों को दोषी ठहराए जाने और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के 19 साल बाद गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनकी दोषसिद्धि विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित नहीं थी। जस्टिस गीता गोपी की पीठ ने सचिन पटेल, अशोक पटेल और अशोक गुप्ता द्वारा दायर उन अपीलों को स्वीकार किया, जिनमें आणंद के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और 29 मई, 2006 को सुनाई गई सजा को चुनौती दी गई थी।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'निचली अदालत के माननीय न्यायाधीश ने साक्ष्यों के मूल्यांकन में गलती की। दोषसिद्धि विश्वसनीय और पुष्टिकारक साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। अभियुक्तों की पहचान साबित नहीं हुई है।'

प्रतीकात्मक

गौरतलब है कि 27 फरवरी, 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगने से 59 लोग मारे गए थे, जिसके बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। जिन नौ लोगों पर मुकदमा चलाया गया था, उनमें से चार को दंगा, आगजनी, भीड़ इकट्ठा करने के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। एक अपीलकर्ता की 2009 में मृत्यु हो गई थी।

अभियोजन पक्ष ने कहा था कि तीनों दोषी उस भीड़ का हिस्सा थे जिन्होंने दुकानों को नुकसान पहुंचाया और उनमें से कुछ को आग भी लगा दी। हाई कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता गैरकानूनी भीड़ के सदस्य थे या नहीं और आगजनी में शामिल थे या नहीं, यह साबित नहीं हुआ है। उनके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य (आग लगाने और निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने) को अभियोजन पक्ष ने साबित नहीं किया है।

मालेगांव विस्फोट मामले में कल आएगा कोर्ट का फैसला

मुंबई : महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में 17 साल पहले हुए एक शक्तिशाली विस्फोट मामले में विशेष एनआइए कोर्ट 31 जुलाई को फैसला सुनाएगी। इस विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित (सेवानिवृत्त) सहित सात लोग इस मामले में आरोपित हैं। यह राजनीतिक रूप से सर्वाधिक संवेदनशील मामलों में से एक रहा है। (पेज-5)

देवघर में हादसे में छह कांवड़ियों की मौत, 27 घायल

देवघर : देवघर में चल रहे श्रावणी मेले के आनंद के बीच मंगलवार सुबह हुए एक हादसे ने छह जिंदगियां छीन लीं। बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण के बाद बासुकीनाथ जा रहे कांवड़ियों से भरी एक बस और ट्रक की टक्कर में छह कांवड़ियों की मौत हो गई और 27 घायल हो गए। दुर्घटना देवघर-हंसडीहा मार्ग पर जमुनिया चौक के निकट हुई। दुर्घटना में बस चालक की भी मौत हो गई है। (पेज-7)

नोएडा, ग्रेनो, मुंबई और बेंगलुरु में विदेशी विवि के कैंपस

नई दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय ने चार और शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में अपने परिसर खोलने की मंजूरी दी है। इनमें आस्ट्रेलिया के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी को नोएडा में, वेस्टर्न सिडनी विवि को ग्रेटर नोएडा (ग्रेनो) में, ला-ट्रोब को बेंगलुरु में और ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी को मुंबई में परिसर की अनुमति दी गई है। चार अन्य विदेशी विवि को अनुमति मिलेगी। (पेज-4)

बांग्लादेश में भीड़ ने की हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़

ढाका : बांग्लादेश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में शनिवार को एक हिंसक भीड़ ने हिंदू समुदाय के लोगों के करीब दो दर्जन घरों को तहस-नहस किया है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद युनूस के कार्यालय ने रंगपुर के गंगाचारा उपजिला में हुई हिंसा में क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के आदेश जारी किए हैं। (पेज-11)

डीजीसीए ने एअर इंडिया में की 51 सुरक्षा खामियों की पहचान

नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एअर इंडिया के विमान संचालन में 51 सुरक्षा खामियों की पहचान की है। वार्षिक सुरक्षा आडिट में यह चूकें सामने आई हैं। इनमें पुरानी प्रशिक्षण पुस्तिकाएं, पायलट प्रशिक्षण की कमी, अयोग्य सिमुलेटर, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी आदि शामिल हैं। (पेज-5)

मंडी में बादल फटने से एक परिवार के तीन लोगों की मौत

मंडी : हिमाचल में आपदा से प्रभावित सराज, करसोग व धर्मपुर के लोगों के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि मंगलवार तड़के बादल फटने से आई बाढ़ में मंडी शहर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। शहर के साथ लगते गंधर्भ जंगल में दो जगह बादल फटे। 200 से अधिक वाहन मलबे में दबने से क्षतिग्रस्त हो गए। (पेज-6)

वकीलों के सामने एसडीएम ने लगाई उठक-बैठक

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

- उप्र के शाहजहांपुर में दीवार के पास लघुशंका कर रहे युवक को किया था दंडित
- धरने पर बैठे नाराज अधिवक्ताओं ने कहा-पहले गंदे शौचालय तो साफ कराएं

दीवार के पास लघुशंका कर रहे युवक को आइएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने जैसे दंडित किया, उसी तरह उठक-बैठक लगाकर माफी भी मांग ली। मंगलवार को पुवायां तहसील में धरने पर बैठे वकीलों ने नाराजगी जताई कि शौचालय गंदे हैं, इसलिए युवक खुले में लघुशंका करने चला गया। उसे दंडित करने से पहले शौचालय तो साफ कराइए। वकीलों के सामने खड़े रिंकू सिंह माहौल को हल्का बनाने के लिए मुस्कुराकर बोले, 'यदि मेरा व्यवहार गलत लगा तो माफी मांगता हूं...' इसके बाद दोनों कान पकड़कर चार बार उठक-बैठक लगा दी।

उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले की पुवायां तहसील में एक छात्र के प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर को लेकर वकीलों व एसडीएम के बीच चार दिन से विवाद चल रहा है। उन्हें हटाने की मांग करते हुए वकील धरना दे रहे हैं। मंगलवार को डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने एसडीएम चित्रा निर्वाल को स्थानांतरित कर संयुक्त मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही को इस पद पर भेजा। दोपहर को एसडीएम का चार्ज लेने के बाद रिंकू सिंह राही तहसील परिसर में निकले तो एक युवक को दीवार के पास लघुशंका करते देख उससे उठक-बैठक लगवा दी। कुछ ही दूरी पर धरना दे रहे वकील यह घटनाक्रम देख रहे थे। बाद में रिंकू धरनास्थल पर पहुंचे तो वकीलों ने शौचालय की गंदगी का मुद्दा उठा दिया।

उप्र में शाहजहांपुर जिले की पुवायां तहसील में अधिवक्ताओं के सामने उठक-बैठक लगाते आइएएस अधिकारी रिंकू सिंह। वीडियो ग्रैब

तहसील परिसर में गंदगी करने पर दी थी कार्रवाई करने की चेतावनी पेज››6

सुप्रीम फैसला

ड्यूटी पर आते-जाते समय पर हुए हादसे भी सेवा के दौरान माने जाएंगे

शीर्ष कोर्ट ने कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 3 को किया स्पष्ट, बांबे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया फैसला

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट किया कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 3 के एक प्रविधान 'नौकरी के दौरान और उसके कारण हुई दुर्घटना' में निवास स्थान और कार्यस्थल के बीच आने-जाने के दौरान होने वाले हादसे भी शामिल होंगे। यानी ड्यूटी पर आते-जाते समय हुए हादसे भी सेवा के दौरान ही माने जाएंगे।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने माना कि इस विषय पर अब तक काफी भ्रम और अस्पष्टता बनी हुई थी। खासकर उन मामलों में जब कर्मचारी ड्यूटी पर आते या जाते समय हादसों का शिकार हो जाते हैं। पीठ ने कहा कि तथ्यों के आधार पर विभिन्न फैसलों में इस एक्ट की अलग-अलग व्याख्या की गई है। पीठ ने कहा- 'हम कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा-3 में प्रयुक्त वाक्यांश नौकरी के दौरान और उसके कारण हुई दुर्घटना की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि इसमें किसी कर्मचारी के साथ उसके निवास स्थान से ड्यूटी के लिए कार्यस्थल तक जाने या ड्यूटी के बाद कार्यस्थल से उसके निवास स्थान तक लौटने के दौरान होने वाली दुर्घटना शामिल होगी, बशर्ते दुर्घटना घटित होने की परिस्थितियों, समय, स्थान तथा रोजगार के बीच संबंध स्थापित हो।'

यह निर्णय बांबे हाई कोर्ट के दिसंबर 2011 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। हाई कोर्ट ने श्रमिक क्षतिपूर्ति आयुक्त के आदेश को रद कर दिया था, जिसमें एक व्यक्ति के परिवार को 3,26,140 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। यह व्यक्ति ड्यूटी पर जाते समय दुर्घटना में मारा गया था।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मृतक एक चीनी फैक्ट्री में चौकीदार के रूप में कार्यरत था और 22 अप्रैल 2003 को दुर्घटना के दिन उसकी ड्यूटी का समय तड़के तीन बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक था। पीठ ने कहा कि यह निर्विवाद है कि वह अपने कार्यस्थल की ओर जा रहा था और कार्यस्थल से लगभग पांच किलोमीटर पहले एक स्थान पर हुई दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी।

राष्ट्रपति के रेफरेंस पर 19 अगस्त से सुनवाई की रूपरेखा तय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ 19 अगस्त से सुनवाई शुरू करेगी। मंगलवार को कोर्ट ने राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई की रूपरेखा तय की। संविधान पीठ मामले की सुनवाई 10 सितंबर तक करेगी। शीर्ष अदालत ने सुनवाई की अवधि तय करते हुए सभी पक्षकारों से कहा है कि तय समय सारिणी का कड़ाई से पालन होगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजकर कुल 14 संवैधानिक सवालों पर राय मांगी है। राष्ट्रपति ने पूछा कि विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए जब संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट समय सीमा तय कर सकता है। कोर्ट ने रेफरेंस पर सुनवाई की रूपरेखा तय करते हुए केंद्र और सभी राज्य सरकारों से कहा कि वे 12 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल कर दें।

ओडिशा तट पर मिसाइल 'प्रलय' का सफल परीक्षण

जागरण संवाददाता, बालेश्वर

- 150 से 500 किमी तक मार करने में सक्षम है यह मिसाइल

भारत की सामरिक क्षमता को मजबूती देने वाले स्वदेशी 'प्रलय' मिसाइल के दो सफल परीक्षण 28 और 29 जुलाई को ओडिशा के डा. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किए गए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा किए गए ये परीक्षण उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण (यूजर एवैल्यूएशन ट्रायल्स) के तहत अधिकतम और न्यूनतम रेंज की पुष्टि के लिए किए गए थे। मिसाइलों ने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को भेदा और सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया।

डीआरडीओ प्रमुख डा. समीर वी. कामत ने कहा कि इन परीक्षणों के बाद मिसाइल को सेना में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है।

'प्रलय' सतह से सतह पर मार करने वाली अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 500 किमी तक है और यह 500 से 1000 किग्रा तक पारंपरिक या विशेष वारहेड्स ले जाने में सक्षम है। इसे मोबाइल लान्चर से दागा जा सकता है। यह मिसाइल सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अभियानों में गेमचेंजर साबित हो सकती है।

डा. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर मंगलवार को परीक्षण के दौरान प्रलय मिसाइल। प्रेट्र

सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अभियानों में गेमचेंजर साबित हो सकती है यह मिसाइल

****

50 लाख युवाओं को हौसलों की उड़ान नामक योजना से जोड़ा जाएगा जिसके लिए 5 करोड़ रुपये का बजट सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 30 जुलाई, 2025

आज का मौसम

बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने व बिजली चमकने की संभावना है। हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने के आसार हैं।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
30 जुलाई	31.0	24.0
31 जुलाई	31.0	25.0
नोएडा		
30 जुलाई	32.0	26.0
31 जुलाई	31.0	25.0
गुरुग्राम		
30 जुलाई	31.0	24.0
31 जुलाई	31.0	25.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

सीपीसीबी ने लिए जनकपुरी में दूषित पानी के नमूने

नई दिल्ली: जनकपुरी में दूषित पानी के नमूने के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने एनजीटी में जवाब दाखिल किया है। सीपीसीबी ने कहा कि जनकपुरी से पानी के नमूने एकत्र कर लिए गए हैं और दो दिनों के भीतर रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। सीपीसीबी ने एनजीटी से रिपोर्ट को रिकार्ड पर पेश करने के लिए समय देने की मांग की। अनुरोध को स्वीकार करते हुए एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई आठ अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। (जासं)

साक्षरता मिशन की फर्जी वेबसाइट बना की धोखाधड़ी

नई दिल्ली : सरकारी योजना का टेंडर दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से करीब 3.5 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपितों को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने 'राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन' के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर धोखाधड़ी की। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमृता गुगुलोथ के मुताबिक गिरफ्तार आरोपितों के नाम करुणाकर और अनीता उपाध्याय है। दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। (जासं)

मेट्रो की 792 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण पूरा

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो के फेज चार में निर्माणाधीन गोल्डन लाइन (तुगलकाबाद-एरोसिटी) के लिए एक और सुरंग का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यह सुरंग तुगलकाबाद से तुगलकाबाद रेलवे कालोनी के बीच स्थित है। मंगलवार को रेलवे बोर्ड के सदस्य नवीन गुलाटी और डीएमआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) ने 792 मीटर लंबी सुरंग की खोदाई का कार्य समाप्त किया। (राब्यू)

दिल्ली में रात्रि पाली में भी काम कर सकेंगी महिलाएं

कैबिनेट ▶ काम करने के लिए महिलाओं से लेनी होगी स्वीकृति, सरकार की ओर से जल्द ही एलजी को भेजा जाएगा प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

दिल्ली सरकार महिलाओं को दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रात की पाली में भी कार्य करने की छूट देगी। यह व्यवस्था महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगी साथ ही ईज आफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रविधान किए जा रहे हैं, जिनमें रात की ड्यूटी के दौरान परिवहन की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और पर्याप्त सुरक्षा गार्ड की तैनाती आदि शामिल है। अभी तक कुछ ही राज्यों में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की छूट मिली हुई है।

मुख्यमंत्री ने इस बारे में बताया कि इस विषय पर उपराज्यपाल से पहले चर्चा हो चुकी है इसलिए उनकी मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव जल्द उन्हें भेजा जाएगा। इस निर्णय को लागू करने के लिए दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1954 में छूट दी जा रही है। इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं को गर्मी में रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक और सर्दी में रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक कार्य करने की अनुमति नहीं है। अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में यह छूट पहले से है। अब राष्ट्रीय राजधानी भी इस सूची में शामिल हो जाएगी।

दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक लेतीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सौजन्य :दिल्ली सरकार

महिलाओं के हित को देखते हुए नियम होंगे सख्त, कार्यस्थल पर हों सीसीटीवी कैमरे

महिलाओं को रात्रि पाली में रखने से पहले उनकी लिखित सहमति लेना जरूरी होगा। कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके अलावा महिला जहां काम करेगी, वहां पर कंपनी को यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति बनानी होगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए रेस्ट रूम, शौचालय, लाकर आदि की सुविधा देनी होगी। नियम यह भी बनाया गया है कि महिलाओं को वेतन का भुगतान बैंक या ईसीएस से होना चाहिए। अन्य शर्तों में ईएसआइ, बोनस, भविष्य निधि आदि सभी कानूनी लाभ देना, साप्ताहिक अवकाश व ओवरटाइम का भुगतान भी शामिल है।

परियोजनाओं में देरी पर मुख्यमंत्री सख्त

विभिन्न परियोजनाओं के बीच आ रहीं अड़चनों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब खुद ऐसे मामलों को देखेंगी और तुरंत कार्रवाई करेंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को आदेश जारी कर हर महीने की परियोजनाओं से संबंधित रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए हैं। नए आदेश के तहत हर महीने की 29 तारीख से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट में विभाग के कार्यक्रमों, योजनाओं और उपलब्धियों को बताया जाएगा ताकि प्रगति का आकलन किया जा सके। इसमें उन बाधाओं का अलग से जिक्र होगा जिनके कारण परियोजना के काम में कोई अड़चने आ रही हैं।

युवाओं के हौसलों को मिलेगी 'उड़ान'

वहीं सरकार ने राजधानी के युवाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लागू की है जो दिल्ली के युवाओं को विशेष पहचान तो देगी ही और उनका नाम भी रोशन करेगी। हौसलों की उड़ान नाम की यह योजना दिल्ली के युवाओं को उनकी रचनात्मक प्रतिभा को निखारने, प्रदर्शित करने और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच बनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि पूरे देश में यह पहली और ऐतिहासिक योजना है जो दिल्ली में लागू की जा रही है। योजना के लिए इस वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। दिल्ली सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूर कर लिया गया। कला व संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली के करीब 50 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली के कोने-कोने में और खासतौर पर दिल्ली के स्लम्स में, झुग्गी बस्तियों में, अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले युवक-युवतियों के टैलेंट की पहचान करने की यह विशेष योजना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में टैलेंट हंट कार्यक्रम आयोजित होंगे, उसके बाद हर विधानसभा से टैलेंट का पूल इकट्ठा करके जोनल लेवल पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जोन और जिला स्तर के बाद यह प्रतियोगिताएं राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी। इय योजना के लिए छह प्रकार की कलाएं चुनी गई हैं, इनमें गायन, नृत्य, कविता, शिल्प कला विजुअल आर्ट, डिजिटल आर्ट और थिएटर शामिल हैं। फाइनल प्रतियोगिता का नाम मुख्यमंत्री से जुड़ा होगा। विजेताओं को नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

बैंकिंग, एनबीएफसी और गैस कनेक्शन 'लोक उपयोगी सेवाएं' घोषित

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: अब दिल्ली में बैंक, लोन कंपनी या गैस कनेक्शन से जुड़ी किसी भी परेशानी का हल जल्दी और आसानी से मिल सकेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और गैस आपूर्ति सेवाओं को 'लोक उपयोगी सेवाओं' की सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है।

इस फैसले के बाद इन सेवाओं से जुड़े विवादों को अब स्थायी लोक अदालतों में सुना जा सकेगा, जहां जल्दी, सस्ते और सरल तरीके से फैसला किया जाएगा। लोगों को बार-बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिन लोगों को बैंक से लोन, अकाउंट, सर्विस चार्ज या रिफंड से जुड़ी समस्या हो, जो ग्राहक एनबीएफसी से लिए गए लोन या किश्तों से जुड़ी शिकायतों से परेशान हों, जिन लोगों को गैस कनेक्शन, सिलेंडर डिलीवरी या बिल से जुड़ी समस्या हो... अब ये सभी केस लोक अदालत में जाकर बिना वकील के भी सुलझाए जा सकेंगे। दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने एलजी को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट में केस सालों चलते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। इसलिए इन तीन सेवाओं को 'लोक उपयोगी सेवा' घोषित किया जाए ताकि लोक अदालतों में इनका जल्दी समाधान हो। एलजी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिससे अब यह कानून का हिस्सा बन जाएगा।

एप पर हो रहा था प्रतिबंधित पाकिस्तानी चैनलों का प्रसारण

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

- जियो हाटस्टार के अधिकारी ने कंटेंट चोरी के आरोप में आइपीटीवी वर्ल्ड के मालिक पर दर्ज कराई रिपोर्ट
- शिकायतकर्ता ने प्रतिबंधित पाकिस्तानी चैनलों के प्रसारण से जताया राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा

जियो हाटस्टार की सामग्री को एप व वेबसाइट के माध्यम से अवैध रूप से बेचने व प्रतिबंधित पाकिस्तानी चैनलों के प्रसारण का मामला सामने आया है। जियो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जियो हाटस्टार) के प्रतिनिधि मोहित बजाज ने आइपीटीवी वर्ल्ड चैनल के मालिक, संचालक व डेवलपर के खिलाफ कापीराइट उल्लंघन व राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे की आशंका को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जियो हाटस्टार के प्रतिनिधि का कहना है कि उन्होंने हेमंत टंडन को व्यवसाय के लिए अधिकार दिए हैं। हेमंत टंडन ने बताया है कि जियो हाटस्टार का कंटेंट आइपीटीवी वर्ल्ड की ओर से प्रसारित किया जा रहा है। इसके लिए आइपीटीवी के पास कोई अनुमति नहीं है। जियो हाटस्टार पर प्रसारित होने वाली सभी सामग्री पर उनका एकाधिकार है। शिकायत मिलने पर उन्होंने शुल्क देकर आइपीटीवी को सब्सक्राइब किया तो पता चला कि यह कंपनी गैरकानूनी तरीके से उनके एप की सामग्री दिखा रही है। इस पर प्रतिबंधित पाकिस्तानी चैनल नूर टीवी व हदी टीवी का भी प्रसारण किया जा रहा है। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। आइपीटीवी वर्ल्ड के संचालक कई वेबसाइट और एप के जरिये गैरकानूनी कार्य कर रहे हैं। इनका आइपी एड्रेस उत्तर प्रदेश का ही है, लेकिन लिथुआनिया की कंपनी के सर्वर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइपी एड्रेस छिपाने के लिए अमेरिका की कंपनी से प्राक्सी की सेवा लेकर अलग-अलग प्लेटफार्म संचालित किए जा रहे हैं। डीसीपी निमिष पाटील ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

संसद के हर सत्र के लिए नहीं हो सकता कोई नया आवेदन: हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : सशर्त कस्टडी पैरोल के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई 31 जुलाई तक के लिए टल गई। सुनवाई के दौरान पीठ ने संकेत दिया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली रशीद की याचिका को एक अन्य पीठ के समक्ष भेजने के लिए इच्छुक हैं।

सुनवाई के दौरान पीठ ने रशीद के वकील से कहा कि संसद के हर सत्र के लिए कोई नया आवेदन नहीं हो सकता। आपने पहले भी एक संशोधन आवेदन दिया था। पीठ ने कहा कि संशोधन आवेदन पिछली पीठ के समक्ष रखना चाहिए और यह आगे के सभी सत्रों के लिए लागू होगा। पीठ ने कहा कि एक बार जब एक अन्य पीठ ने अपना निर्णय ले लिया तो यह अदालत उसी आदेश का पालन करेगी।

पीठ ने कहा कि जब एक समन्वय पीठ पहले ही इसी तरह के मुद्दे पर फैसला ले चुकी है तो इस मामले की सुनवाई करना हमारी ओर से गलत होगा।

सात राज्यों में 1800 करोड़ रुपये का चिटफंड घोटाला, सरगना दुबई भागा

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली

- दिल्ली समेत सात राज्यों के पीड़ितों ने पूर्वी दिल्ली के डीएम कार्यालय में दी हैं 10 हजार से अधिक शिकायतें
- एफडी और आरडी में निवेश करने पर दोगुनी रकम देने की गारंटी देकर लोगों के साथ की धोखाधड़ी

प्रतीकात्मक

देश की राजधानी दिल्ली में 1800 करोड़ रुपये से अधिक के चिटफंड घोटाले का मामला सामने आया है। घोटाले का आरोप ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड नामक फर्जी कंपनी पर लगा है। बताया जा रहा है कि इस सोसायटी ने देश के सात राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान में अपने कार्यालय खोले थे। इसका मुख्यालय दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में था। सातों राज्यों में जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है वे अब पूर्वी दिल्ली के डीएम कार्यालय में आकर शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, डीएम कार्यालय को अब तक 10 हजार से अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं। लोगों से धोखाधड़ी करने के बाद फर्जी सोसायटी का चेयरमैन दुबई फरार हो गया है।

पंजाब, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान के लोग तीन-चार दिन से डीएम कार्यालय में शिकायत देने के लिए आ रहे हैं। पांच बजे तक शिकायतें ली जाती हैं। अभी भी सैकड़ों लोगों को शिकायत दर्ज करवानी है। शिकायत दर्ज करवाने के लिए आए लोगों का बुरा हाल है। मंगलवार को कतार में खड़ी कई महिलाएं रोती दिखीं। उनका कहना था कि निवेश के नाम पर उनकी जिंदगी की पूरी कमाई लूट ली गई। दूसरे राज्यों से आए लोगों को रात में रुकने में भी दिक्कत होती है। उनके पास कोई ठिकाना नहीं है। लोगों ने बताया कि यह सोसायटी वर्ष 2016 से संचालित हो रही थी। उनके मुताबिक इस सोसायटी के देशभर में 250 से अधिक शाखाएं खोली गई हैं। इसने बहु-स्तरीय विपणन (एमएलएम) माडल का इस्तेमाल कर आकर्षक सावधि जमा (एफडी) और आवर्ती जमा (आरडी) योजनाओं के जरिये निवेशकों को आकर्षित किया और कुछ वर्ष में रकम दोगुनी मिलने का झूठा आश्वासन देकर ठगा। सोसायटी का पोर्टल दिसंबर 2024 से बंद है। लोग सोसायटी की शाखा में जाकर नकद रकम जमा करवाते थे। सोसायटी की ओर से मिली पासबुक में उसकी एंट्री होती थी। प्रशासन का कहना है सभी शिकायतें मिलने के बाद केंद्र सरकार को सूचना दी जाएगी। उसके बाद ही जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी।

मेधा पाटकर को दोषी करार देने के निर्णय को हाई कोर्ट ने रखा बरकरार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मानहानि से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दोषी करार देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने कहा कि वीके सक्सेना द्वारा दायर मामले में पाटकर को दोषी ठहराने के ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालतों के फैसलों में कोई अवैधता नहीं थी।

इसके साथ ही अदालत ने पाटकर को परिवीक्षा पर रिहा करने के अपीलीय अदालत के फैसले को भी बरकरार रखा। हालांकि, अदालत ने पाटकर को राहत देते हुए कहा कि वह हर तीन महीने में ट्रायल कोर्ट में पेश होने की जगह आनलाइन या फिर किसी अधिवक्ता के माध्यम से पेश हो सकती हैं। यह पूरा मामला वर्ष 2000 का है, जब नेशनल काउंसिल आफ सिविल लिबर्टीज नामक संगठन के वीके सक्सेना अध्यक्ष थे। उन्होंने पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ एक विज्ञापन प्रकाशित किया था। फिर पाटकर ने वीके सक्सेना पर कई आरोप लगाते हुए एक प्रेस नोट जारी किया था।

मुंह में हीलियम गैस भरकर सीए ने की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

गुरुग्राम की एक कंपनी में कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बंगाली मार्केट के एक होटल में मुंह में हीलियम गैस भरकर जान दे दी। मृतक की पहचान हरियाणा के करनाल निवासी धीरज कंसल (25) के रूप में हुई है। दिल्ली में हीलियम गैस से आत्महत्या का यह पहला मामला है। पुलिस को मृतक के हाथ के नीचे से और फेसबुक पर लिखा एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। धीरज जिस होटल में ठहरा था, पुलिस वहां के स्टाफ से पूछताछ कर रही है।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 28 जुलाई को बाराखंभा थाने की पुलिस को सूचना मिली कि एक होटल में ठहरा गेस्ट चेकआउट नहीं कर रहा और कमरे से दुर्गंध आ रही है। पुलिस, एफएसएल, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचीं तो पाया कि धीरज का शव बेड पर पीठ के बल पड़ा था। उसके मुंह में हीलियम सिलिंडर से जुड़ी पाइप लगी थी। पुलिस के मुताबिक, धीरज ने 20 से 28 जुलाई तक होटल में कमरा बुक किया था। कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें उसने लिखा कि अगर उसकी फेसबुक पोस्ट डिलीट हो जाए तो यह नोट उसके विचार व्यक्त करने के लिए है। नोट में लिखा है कि मेरे लिए मौत जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कृपया मेरी मौत पर दुखी न हों। आत्महत्या करना बुरा नहीं है क्योंकि मुझ पर किसी की जिम्मेदारी नहीं है और न ही कोई मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। पुलिस को जांच में पता चला कि धीरज के पिता की मृत्यु 2003 में हो गई थी और मां ने दूसरी शादी कर ली थी। कोई भाई-बहन नहीं है।

धीरज की फाइल फोटो। सौ. इंटरनेट मीडिया

इंजीनियर ने महिला मित्र को छठी मंजिल से फेंका नीचे, मौत

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली

नरेला के मनसा देवी अपार्टमेंट में रहने वाले इंजीनियर ने अपनी महिला मित्र को छठी मंजिल से नीचे फेंक दिया। मृतका के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर जब पुलिस वहां पहुंची तो महिला के सिर से खून निकल रहा था। मौके पर एफएसएल और क्राइम ब्रांच को भी बुलाया गया। पुलिस ने आरोपित इंजीनियर दीपक कुमार मिश्रा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित बक्सर जिले के गांव उधूरा का रहने वाला है। वहीं मृतका साधना सिंह, अलीगढ़ के थाना बरला स्थित आलपुर रानी गांव की रहने वाली थी।

बाहरी-उत्तरी जिला के पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि आरोपित दीपक ने पहले अपनी महिला मित्र साधना के साथ पार्टी की थी। फिर किसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और दीपक ने साधना को छठी मंजिल से नीचे फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस के आने पर आरोपित पुलिस और अन्य लोगों पर ईंट-पत्थर फेंकने लगा था। इस दौरान उसने अपने कपड़े भी उतार दिए और गाली-गलौज भी की। तभी मौजूद पुलिसकर्मी ने आरोपित को काबू कर लिया।

नरेला स्थित मंशा देवी अपार्टमेंट के इसी इमारत की छठी मंजिल से महिला मित्र को आरोपित ने नीचे फेंक दिया। सौ जागरण

डीयू में सीईएस में दाखिला शुरू, कोई भी कर सकता है आवेदन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए कम्पिटेंस एन्हांसमेंट स्कीम (सीईएस) के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत किसी भी आयु वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के कालेजों में चल रहे पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों के चयनित पेपरों में नामांकन कर सकते हैं।

नई शिक्षा नीति-2020 की भावना को साकार करते हुए यह योजना सीखने की आजादी, जीवन भर शिक्षा और व्यावसायिक कुशलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना का संचालन दिल्ली विश्वविद्यालय का इंस्टीट्यूट आफ लाइफ लांग लर्निंग (आइएलएलएल) कर रहा है जो इसका नोडल संस्थान है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो चयनित पेपर की न्यूनतम पात्रता और पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करता है, वह सीईएस के अंतर्गत पंजीकरण कर सकता है। प्रवेश सीट की उपलब्धता और विभाग/कालेज की स्वीकृति पर निर्भर करेगा। सीईएस के तहत दी जाने वाली सीटें अतिरिक्त होंगी और नियमित छात्रों की सीटों को प्रभावित नहीं करेंगी। आइएलएलएल के निदेशक प्रो. संजय राय ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी www.admission.uod.du.ac.in या www.illl.du.ac.in पर उपलब्ध ई-ब्रोशर के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी स्पष्टीकरण या सहायता के लिए अभ्यर्थी ces@illl.du.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। गौरतलब है कि सीईएस के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू हो चुकी है।

दिल्ली विश्वविद्यालय। फाइल

इस मानसून की पहली भारी वर्षा ने पूरा किया जुलाई का कोटा

रिकार्ड टूटा

रिज क्षेत्र में हुई सबसे ज्यादा 129.8 मिमी बारिश जबकि लोधी रोड पर दर्ज की गई 72.4 मिमी वर्षा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

मंगलवार को दिल्ली में इस मानसून की पहली एवं साल की तीसरी भारी वर्षा दर्ज की गई। इस वर्षा से उमस भरी गर्मी तो दूर हुई ही, तापमान में भी खासी गिरावट देखने को मिली। आलम यह रहा कि जुलाई माह का अधिकतम तापमान जहां 2023 के बाद सबसे कम रहा वहीं न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान के बीच का अंतर भी घटकर तीन डिग्री से कम रह गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी अगले दो दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा।

हल्की वर्षा तो सोमवार आधी रात के बाद भी कहीं कहीं हुई लेकिन तेज वर्षा मंगलवार सुबह से ही देखने को मिली। अधिकांश वर्षा सुबह साढ़े आठ से पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे के बीच हुई। हालांकि इसके बाद भी रुक रुककर कहीं कहीं हल्की वर्षा होती रही। रात के साढ़े आठ बजे तक राजधानी में 68.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा रिज क्षेत्र में 129.8 मिमी रिकार्ड की गई। लोधी रोड पर 72.4, पालम में 4.6, आयानगर में 23.4, भारत मंडपम में 45.6, पूसा में 37.5, पजफगढ़ में 1.5 और जनकपुरी में 4.0 मिमी वर्षा हुई।

वर्षा के कारण नार्थ कैंपस डीयू में हुए जलभराव में से कुछ इस तरह गुजरते छात्र व वाहन चालक। ध्रुव कुमार

मंगलवार की झमाझम वर्षा ने माह की ही नहीं, मानसून के इस सीजन की अभी तक की वर्षा का कोटा भी सरप्लस कर दिया। जुलाई माह की औसत वर्षा 209.7 मिमी वर्षा है जबकि मंगलवार 29 जुलाई तक यह 220.2 मिमी हो चुकी है। मानसून सीजन की वर्षा भी सरप्लस हो गई है। अब तक की सामान्य वर्षा है 259.2 मिमी जबकि हो चुकी है 327.3 मिमी। इस साल दो और 25 मई को भी क्रमशः 77 मिमी और 81.4 मिमी वर्षा हुई थी।

दूसरी तरफ इस वर्षा से तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री कम 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह जुलाई माह में 2023 के बाद सबसे कम है। आठ सितंबर 2023 के दिन यह 28.7 डिग्री रहा था। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार-बृहस्पतिवार को भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होगी और तापमान भी सामान्य से कम ही रहेगा।

नए सत्र से डीयू में पीजी की डिग्री के लिए अर्जित करने होंगे 88 क्रेडिट्स

उदय जगताप ● जागरण

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर (पीजी) में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अब डिग्री पूरी करने के लिए 88 क्रेडिट्स अर्जित करने पड़ेंगे। पहले एमएससी, एमए के अलग-अलग कोर्सों के लिए छात्रों को अलग-अलग क्रेडिट्स मिलाकर करते थे। इससे छात्रों में कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी लेकिन इसमें एकरूपता लाने के लिए नवीन सत्र से अब हर छात्र को 88 क्रेडिट्स तय कर दिए हैं।

डीयू में पीजी पाठ्यक्रम में पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क (पीजीसीएफ) लागू किया गया है। इसके तहत नया बदलाव किया गया है। छात्रों के लिए पहले अलग-अलग कोर्स में 90, 95 या 100 इस तरह पूरे क्रेडिट्स होते थे। इनमें छात्रों को क्रेडिट लाने होते थे और उसी आधार पर सीजीपीए तैयार होता था लेकिन अब इस व्यवस्था को बदलकर सभी के लिए 88 क्रेडिट कर दिया गया है। पहले सेमेस्टर में छात्र को तीन डिसिपलिन स्पेसफिक कोर (डीएससी) पेपर पढ़ने होंगे। इनके 12 क्रेडिट्स होंगे। इसके साथ ही दो डिसिपलिन स्पेसफिक इलेक्टिव (डीएसई) पढ़ने होंगे। वह एक डीएसई या एक जेनरिक इलेक्टिव कोर्स पढ़ सकते हैं। दोनों के लिए आठ क्रेडिट होंगे। कोर्स को और प्रैक्टिकल बनाने के लिए दो क्रेडिट का स्किल बेस्ड कोर्स पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है जो हैंड्स आन लर्निंग पर आधारित होगा। ऐसे एक सेमेस्टर के 22 क्रेडिट होंगे। इसी तरह दूसरा सेमेस्टर होगा। तीसरे और चौथे समेस्टर में छात्रों को पढ़ने के लिए विकल्प दिए गए हैं। ऐसे छात्र 88 क्रेडिट की डिग्री लेंगे।

****

30 जून, 2025 तक देश भर में 16,912 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। जन औषधि केंद्रों ने पिछले 11 वर्षों में लोगों के लगभग 38,000 करोड़ रुपये बचाए हैं।

'भारत माता की मांग में शौर्य का सिंदूर, न डालें राजनीति की धूल'

राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू की आपरेशन सिंदूर पर चर्चा

कहा, विपक्ष को लगता है कि यह आपरेशन करके ठीक नहीं किया तो सुझाए वैकल्पिक एक्शन प्लान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

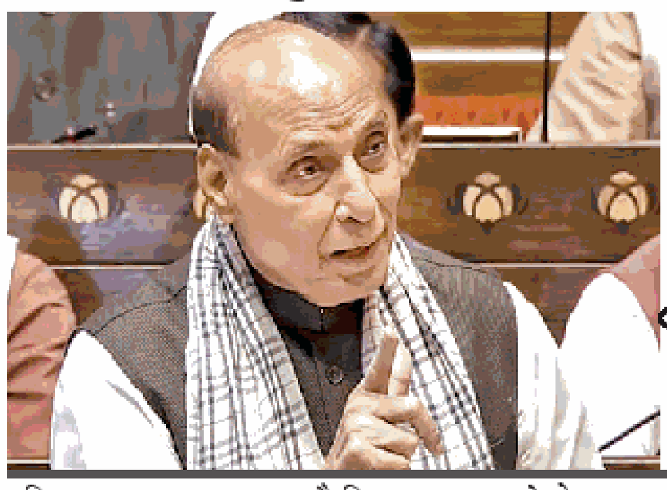

- पहचान पुनर्परिभाषित करने का एक उदाहरण है आपरेशन सिंदूर
- हमारा विजन ईंट का जवाब पत्थर से देंगे

राज्यसभा में मंगलवार को आपरेशन सिंदूर पर शुरू हुई चर्चा के दौरान बोलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रेट्र

आपरेशन सिंदूर को लेकर तरह-तरह के सवाल उठा रहे विपक्ष को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को आईना दिखाने का प्रयास किया। राज्यसभा में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आरंभ करते हुए उन्होंने इस सैन्य कार्रवाई की सफलता का दावा दोहराते हुए कहा कि राजनीति के लिए बहुत से विषय हैं, लेकिन विपक्ष को सेना के शौर्य और पराक्रम पर राजनीति करने से बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत माता की मांग में शौर्य का सिंदूर है, उस पर राजनीति की धूल मत डालिए।

रक्षा मंत्री ने सबसे पहले राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से जानकारी दी कि पहलगाम हमले से जुड़े तीन आतंकियों को सैन्य बलों ने मार गिराए हैं और हुंकार भरी, 'हम जो कहते हैं, वह करते हैं।'

उन्होंने कहा कि आपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध हमारी नीति का प्रभावशाली प्रदर्शन है। राजनाथ ने कहा कि यह हमारे इतिहास का एक कटु सत्य है कि लगभग 800 वर्षों की गुलामी के बाद यह माना जाने लगा था कि हिंदुस्तान की जनता स्वभाव से आक्रामक नहीं है, बल्कि बेहद शांतिप्रिय है। एक राष्ट्र के चरित्र के लिए यह कितना अपमानजनक था। अब हम अपनी पहचान को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं और आपरेशन सिंदूर उसी का एक उदाहरण है।

संप्रग काल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकियों ने भारत को एक साफ्ट स्टेट समझ रखा था। उनके दो-चार नौसिखिए रंगरूट आते थे और हमारे नागरिकों को हताहत करके चले जाते थे। पहले की सरकारें चुपचाप तमाशा देखती जा रही थीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने सुनिश्चित किया है कि आतंकियों के जेहन में यह बात बैठ जाए कि हमारे एक भी नागरिक को कुछ हुआ तो हम उनके पूरे ठिकाने को नेस्तनाबूत कर देंगे।

रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर विपक्ष को यह लगता है कि हमने आपरेशन सिंदूर करके ठीक नहीं किया तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वह जनता को बताएं कि उनके पास वैकल्पिक एक्शन प्लान क्या है? हमारी माताओं-बहनों का सिंदूर उजड़ गया तो क्या हम पाकिस्तान के साथ राजनयिक वार्ता करें? क्या हम पाकिस्तान को डोजियर सौंपें? क्या हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों में जाकर केवल बातें करें? जब हमारे विपक्ष के साथी सत्ता में थे तो क्या आतंकी हमले होने पर वे ऐसे ही कदम उठाते थे? कुछ लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं तो उनसे केवल बातचीत करनी चाहिए। इस कारण हमने न जाने कितने नागरिकों को खो दिया। हमारा विजन है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।

पहलगाम में आतंकी हमले के लिए कौन जिम्मेदार, जो भी हो इस्तीफा दे : खरगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान उठाए सवाल
- कहा- आतंकी हमले रोकने में चूक और विफलता को सरकार करे स्वीकार, जवाबदेही तय की जाए

राज्यसभा में मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बहस के दौरान बोलते नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे। प्रेट्र

कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार से पूछा है कि पहलगाम हमले के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जो भी दोषी हैं, पीएम मोदी को उसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और इस्तीफा लेना चाहिए। उन्होंने सरकार से आतंकी हमले रोकने में हुई चूक व विफलताओं को स्वीकार करने की भी मांग की।

खरगे ने ये सवाल मंगलवार को राज्यसभा में पहलगाम हमले व आपरेशन सिंदूर को लेकर दोपहर दो बजे के बाद शुरू हुई चर्चा के दौरान उठाए। उन्होंने यह भी पूछा कि पीएम मोदी बताएं कि हमारे जेट गिरे क्या और कितने? खरगे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सुरक्षा में हुई चूक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद स्वीकार किया कि पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई थी। सिन्हा ने कहा था कि वह घटना की सभी जिम्मेदारी लेते हैं। खरगे ने कहा कि सिन्हा की जगह गृह मंत्री को सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि किन शर्तों पर सीजफायर हुआ और पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद भी इसे क्यों स्वीकार किया गया। क्या इसमें अमेरिका ने दखल दिया। यह ऐसा था तो आपने ऐसा क्यों करने दिया।

मोदी पर टिप्पणी को लेकर खरगे-नड्डा में नोकझोंक

रास में मंगलवार को जारी बहस के दौरान बोलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। एएनआइ

खरगे की पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर भाजपा अध्यक्ष व नेता सदन जेपी नड्डा ने जवाब दिया। कहा- खरगे की टिप्पणी को मैं समझ सकता हूं। 11 सालों से उन्हें विपक्ष में बैठाए रखा है। मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है। वह पार्टी और देश के लिए गौरव का विषय हैं लेकिन आप तो पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश गौण हो जाता है और मेंटल बैलेंस खोकर इस तरीके से बात कर रहे है। हालांकि बाद में विपक्ष की आपत्ति के बाद नड्डा ने मेंटल बैलेंस शब्द की जगह भावावेश में बोलने की बात कही। इसके बाद भी नाराजगी नहीं खत्म हुई और वे हंगामा करते दिखे तो नड्डा ने कहा कि अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं आपसे माफी भी मांगता हूं।

सदन में चर्चा के दिन ही क्यों मारे गए आतंकी : अखिलेश

लोकसभा में मंगलवार को बोलते सपा सदस्य अखिलेश यादव। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले के आतंकियों के एनकाउंटर पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा कि सदन में चर्चा के दिन ही आतंकी क्यों मारे गए। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि जिस राफेल की पूजा नींबू-मिर्च से की गई थी, उनमें से कितने उड़े। उन्होंने आतंकी हमले के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग करते हुए विदेश नीति में सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया। अखिलेश ने सरकार को आगाह किया कि चीन हमारी जमीन और बाजार दोनों को निगल जाएगा। सरकार की नीतियों से चीन के व्यावसायिक हित को बढ़ावा मिल रहा है और भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने अग्निपथ को भी वापस लेने की मांग की। सीमा पर तैनात सेना को दीर्घकालिक सुरक्षा और प्रतिबद्धता की जरूरत है। अखिलेश ने पुलवामा हमले का भी उल्लेख किया।

हमले के दिन ही तय हुआ कि आतंकियों को नहीं भागने दिया जाएगा पाक

प्रथम पृष्ठ से आगे

अमित शाह ने पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को पाकिस्तान वापस भागने से रोकने और तीन महीने के अथक परिश्रम के बाद ढूंढकर खत्म करने की पूरी कहानी विस्तार से बताई। उनके अनुसार पहलगाम आतंकी हमले के दिन 22 अप्रैल को ही सुरक्षा बलों के साथ बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी स्थिति में हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान न भागने पाएं। इसके एक महीने बाद 22 मई को आइबी को दाचीगाम के जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली। इसके बाद दो महीने तक सुरक्षा बल के जवान अत्याधुनिक उपकरणों से आतंकियों के सिग्नल पकड़ने की कोशिश करते रहे। 22 जुलाई को दाचीगाम में पांच ह्यूमन असेट्स को भेजे जाने के बाद सेंसरों ने आतंकियों की मौजूदगी का पता लगा लिया था। अंततः 22 जुलाई को आइबी ने आतंकियों की पुष्टि की। इसके बाद 'आपरेशन महादेव' शुरू किया गया।

पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकियों के मारे जाने के साथ ही सरकार को घेरने का एक अहम मुद्दा खत्म हो गया। पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने एक दिन पहले ही आतंकियों के पाकिस्तान से आने पर सवाल उठाया था और कहा था कि ये आतंकी यहीं के भी हो सकते हैं। शाह ने कहा, ''अब जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान से आतंकी भेजे जा रहे हैं क्योंकि कश्मीर में कोई स्थानीय आतंकी नहीं है। अनुच्छेद-370 खत्म करने से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का माहौल खत्म हो गया है।'' उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इससे विपक्ष में भी खुशी की लहर दौड़नी चाहिए थी, लेकिन उनके चेहरे पर तो स्याही पड़ गई। उन्होंने चिदंबरम पर हमला करते हुए कहा कि पूर्व गृह मंत्री कैसे पाकिस्तान को क्लीन चिट दे सकते हैं।

पाकिस्तान को सभी तरह के आतंकवाद की जड़ बताते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस की एक गलती थी। उन्होंने आगे कहा, ''अगर उन्होंने विभाजन को नकार दिया होता, तो पाकिस्तान होता ही नहीं।'' संप्रग सरकार के दौरान हुए आंतकी हमलों की जानकारी देते हुए शाह ने कहा कि इनके जवाब में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में आतंकी हमले पर डोजियर नहीं भेजे जाते, बल्कि आतंकियों और उसके ठिकानों को जमींदोज किया जाता है। उन्होंने कांग्रेस पर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को कमजोर करने का आरोप लगाया।

हुर्रियत आतंकियों का संगठन, उनसे बात नहीं करेंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमित शाह ने कहा कि एक समय था जब हुर्रियत कान्फ्रेंस के नेताओं को वीआइपी ट्रीटमेंट मिलता था। हुर्रियत के लिए रेड कार्पेट बिछा हुआ था। मनमोहन सिंह सरकार के प्रतिनिधि उनसे बातचीत करते थे। हमने हुर्रियत के सभी घटकों पर प्रतिबंध लगा दिया और अब सभी जेल में हैं। हम हुर्रियत से बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, ''मैं नरेन्द्र मोदी सरकार की नीति दोहराना चाहता हूं- हुर्रियत आतंकी संगठनों का संगठन है। हम उनसे बात नहीं करेंगे। हम घाटी के युवाओं से बात करेंगे।'' जम्मू-कश्मीर के हालात पर शाह ने कहा कि 2004 से 2014 तक कश्मीर में 7,217 आतंकी घटनाएं हुईं और 2014 से 2025 तक ये घटनाएं 70 प्रतिशत घटकर 2,150 रह गईं। गृह मंत्री ने कहा कि 2005 से 2011 के बीच 27 आतंकी हमले हुए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्या किया, उन्होंने बस पाकिस्तान को डोजियर भेजे।

पाक के एयर डिफेंस पर हमला न करना चूक : राहुल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पीएम में इंदिरा गांधी की तरह दम तो सदन में कह दें कि ट्रंप सीजफायर कराने को लेकर झूठ बोल रहे
- नेता प्रतिपक्ष का बड़ा आरोप- राजनीतिक प्रतिबंध के कारण भारतीय सेना के विमान गिरे

लोकसभा में मंगलवार को आपरेशन सिंदूर पर जारी बहस के दौरान बोलते नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। प्रेट्र

आपरेशन सिंदूर को लेकर कई दिनों से जो सवाल सदन के बाहर खड़े किए जा रहे थे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को सदन के अंदर भी वही सवाल किए। सबसे बड़ा सवाल था कि ट्रंप के कहने पर आपरेशन रुका या नहीं और सबसे बड़ा आरोप था कि राजनीतिक प्रतिबंध के कारण भारतीय सेना के विमान गिरे। लगभग आधे घंटे का उनका भाषण इसी पर केंद्रित रहा। यह और बात है कि कुछ देर बाद ही खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से ट्रंप के मसले पर उन्हें खरा-खरा जवाब मिल गया।

मंगलवार की दोपहर प्रियंका गांधी समेत कुछ अन्य विपक्षी नेताओं के भाषण के बाद जब राहुल बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान को इसकी सूचना देने को बड़ी चूक करार दिया। उन्होंने दुश्मन की रक्षा प्रणाली पर हमला न करने के सरकार के निर्णय की भी आलोचना करते हुए कहा कि इसके चलते हमारे कुछ विमान गिरे, क्योंकि सरकार ने सेना को पूरी छूट नहीं दी। जाहिर है, भारतीय विमानों के नुकसान का कारण राजनीतिक प्रतिबंध थे।

राहुल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान पर सवाल उठाया, जिसमें एक दिन पहले कहा गया था कि आपरेशन सिंदूर की शुरुआत 1:05 बजे रात में हुई और 1:35 बजे पाकिस्तान को बता दिया गया कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है क्योंकि हम संघर्ष नहीं चाहते हैं। राहुल ने कहा कि ऐसी सूचनाएं दुश्मन को देने से सेना की रणनीति और उसकी स्वतंत्रता बाधित होती है। वैसे सरकार की ओर से एक दिन पहले भी यह स्पष्ट किया गया था कि भारत आतंकियों पर ही कार्रवाई करना चाहता था और अपनी तरफ से युद्ध को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था।

आपरेशन सिंदूर का मकसद अधूरा : प्रियंका

आपरेशन सिंदूर से जुड़ी बहस के दौरान बोलतीं कांग्रेस सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रेट्र

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपरेशन सिंदूर के मकसद को अधूरा बताते हुए कहा कि हम आतंकियों को खत्म नहीं कर पाए और हमारी कूटनीति भी नाकाम रही है। इस घटना के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की आतंक विरोधी समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। साथ ही पाकिस्तानी जनरल को जिसके हाथ खून से सने हुए थे, अमेरिकी राष्ट्रपति ने लंच पर बुला लिया।

आपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं गृह मंत्री अमित शाह के जवाब को खारिज करते हुए प्रियंका ने कहा कि गृह मंत्री ने सदन में नेहरू, इंदिरा गांधी एवं सोनिया गांधी का जिक्र किया, मगर यह नहीं बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध क्यों रोका? देश में पहली बार एक युद्ध अचानक रुक गया और इसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने। प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम हर काम का सिर्फ श्रेय लेते हैं, जिम्मेदारी नहीं।

देशहित के विरुद्ध था जवाहर लाल नेहरू का सिंधु जल समझौता : मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- लोकसभा में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने उजागर किए कई तथ्य
- पाकिस्तान को दिया था भारत की नदियों के बांध की डी-सिल्टिंग की अनुमति देने का अधिकार

आपरेशन सिंदूर पर मंगलवार को लोकसभा में हुई चर्चा में बोलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र

आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के सहारे केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करने वाली कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। एक-एक बिंदु पर विस्तार पर चर्चा करने के बीच उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह तथ्य उजागर किया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का सिंधु जल समझौता देशहित के विरुद्ध था। पाकिस्तान के इशारे पर ही नेहरू ने डी-सिल्टिंग के लिए बने गेट को पूरा-पूरा बंद कर दिया था। डी-सिल्टिंग के गेट नीचे बने होते हैं ताकि गाद निकल सके।

लोकसभा में राहुल गांधी के वक्तव्य के तुरंत बाद पीएम मोदी ने उनके द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों का जवाब दिया। मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाने वाले विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया। चूंकि, पहलगाम हमले के बाद आपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ दशकों से चला आ रहा सिंधु जल समझौता भी स्थगित कर दिया, इसलिए इस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में शामिल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने देशहित के विरुद्ध सिंधु जल समझौता किया था। देश यह जानकर चौंक जाएगा कि भारत से बहने वाली पश्चिमी नदियों का 80% जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। नहरें बनाने के लिए पाकिस्तान को करोड़ों रुपये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दिए थे। एक और महत्वपूर्ण तथ्य से पर्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बांध बनते हैं तो तो जल की गहराई बनाए रखने के लिए समय-समय पर उनकी डी-सिल्टिंग की व्यवस्था भी होती है, लेकिन सिंधु जल समझौते के तहत जवाहर लाल नेहरू ने इन नदियों पर उन बांधों की डी-सिल्टिंग की अनुमति का अधिकार भी पाकिस्तान को दे दिया था, जो भारत में बने हैं। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इस समझौते में हुई गलती का अहसास बाद में खुद नेहरू को भी हुआ था। उन्होंने उस परियोजना से जुड़े एक पूर्व अधिकारी से इस संबंध में कहा भी था।

आतंकी व उनके आकाओं को रोते देखकर यहां भी रो रहे कुछ लोग

प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात हैरानी जताई कि देश में दशकों तक शासन करने वाली पार्टी अब अपने मुद्दे भी पाकिस्तान से आयात कर रही है। उन्होंने कहा कि आपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान और कांग्रेस के रुख बिल्कुल एक जैसे हैं। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर पाकिस्तान के प्रपंच का प्रवक्ता बनने का आरोप लगाया। इसके लिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और आपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों का हवाला दिया। प्रधानमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि आतंकी और उनके आकाओं को रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस नेताओं को संसद में बोलने से इसलिए रोका गया क्योंकि उन्होंने आपरेशन सिंदूर पर दुनिया के सामने भारत का रुख पेश किया जिससे पार्टी नेतृत्व घबरा गया। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा शशि थरूर और मनीष तिवारी की ओर था। उन्होंने कहा कि वाह रे बयान बहादुरों! विरोध करने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए ही चाहिए। पूरा देश आप पर हंस रहा है। कांग्रेस को नसीहत दी कि वह एक परिवार के दबाव में पाकिस्तान को क्लीनचिट देना बंद करे। प्रधानमंत्री ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पहलगाम के तीनों आतंकियों के सोमवार को ही मारे जाने के सवाल भी हैरानी जताई। अभी तक सवाल था कि हमला करने वाले आतंकी कहां हैं, जब मारे गए तो अब ही क्यों मारे गए।

सिर्फ चीन, अजरबैजान व तुर्किये ने पाकिस्तान के पक्ष में दिया बयान : प्रधानमंत्री ने आपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के अलग-थलग पड़ने के विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में शामिल 193 देशों में से किसी भी देश ने भारत को कार्रवाई से नहीं रोका। इनमें सिर्फ तीन देश चीन, अजरबैजान और तुर्किये ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया। उन्होंने आपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के रुख को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि दुनिया के तमाम देशों से तो भारत को समर्थन मिला, लेकिन देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला।

पाक डीजीएमओ ने लगाई थी गुहार, 'बस करो, बहुत मारा... हमला रोको' : प्रधानमंत्री ने भारत की सैन्य कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे ''विजयोत्सव'' बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी तकनीकी क्षमता का परिचय दिया। पाकिस्तान के हवाई अड्डे तबाह कर दिए गए। कुछ हवाई अड्डे अभी भी आइसीयू में हैं। पाकिस्तान के विभिन्न कोनों में किए गए हमलों के बाद वह घुटनों पर आ गया। उनके डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन करके कहा, ''बस करो, बहुत मारा... हमला रोको।'' मोदी ने कहा कि तकनीक आधारित युद्ध के इस युग में भारतीय रक्षा प्रणाली ने अपनी क्षमता साबित कर दी है। पाकिस्तान द्वारा दागे गए 1,000 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गईं। आपरेशन सिंदूर ने भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग की ताकत को प्रदर्शित किया है। आपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान अब स्पष्ट रूप से समझ गया है कि भारत का जवाब हमेशा बड़ा होगा।

विपक्ष की ख्वाहिश, मोदी फंस जाए : प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, विपक्षी दल हमेशा यही उम्मीद करते थे कि मोदी फंस जाए और इस बार भी उनकी यही ख्वाहिश थी। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा बीएसएफ के एक जवान को पकड़े जाने पर उनकी सरकार के विरुद्ध चलाए गए अभियान का हवाला दिया। बाद में जवान को पाकिस्तान ने सुरक्षित लौटा दिया। 2019 के बालाकोट आपरेशन के दौरान कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ''जब हमारे पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया गया, तो पाकिस्तान जरूर खुश हुआ होगा, लेकिन यहां भी कुछ कांग्रेसी नेता खुश थे। लेकिन अभिनंदन सुरक्षित भारत लौट आए।'' पहले वे स्ट्राइक का फोटो सुबूत मांगते थे। अब वे पूछ रहे हैं कि हमने आपरेशन सिंदूर क्यों रोका।

विपक्षी नेताओं द्वारा सरकार से यह पूछे जाने पर कि उसने सुरक्षा बलों को गुलाम जम्मू-कश्मीर पुनः हासिल करने की अनुमति क्यों नहीं दी, प्रधानमंत्री ने कई घटनाओं का हवाला दिया जब पिछली कांग्रेस सरकारों ने सैन्य लाभ होने के बावजूद ऐसा नहीं किया, जैसा 1971 के युद्ध में हुआ था और कब्जा किए गए क्षेत्रों को भी पाकिस्तान को लौटा दिया था। कांग्रेस को यह जवाब भी देना चाहिए गुलाम जम्मू-कश्मीर को किसने अलग हो जाने दिया? भारत आज भी नेहरू से लेकर पिछली कांग्रेस सरकारों की गलतियों का दर्द झेल रहा है।

अभिलेखीय दस्तावेज

'इंदिरा ने निक्सन से 1971 में पाक हमले रोकने का किया था अनुरोध'

अमेरिकी अभिलेखीय दस्तावेज में इंदिरा द्वारा राष्ट्रपति निक्सन को लिखे पत्र का है उल्लेख, अमेरिका से इस्लामाबाद की आक्रामक गतिविधियों को रोकने में मदद की गुहार लगाई थी

नई दिल्ली, आइएएनएस : लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1971 में बहुचर्चित राजनीतिक इच्छाशक्ति का जिक्र किया। वहीं, इतिहासकारों ने बताया है कि दरअसल, वह युद्ध नहीं चाहती थीं और उन्होंने अमेरिका से भारत के खिलाफ इस्लामाबाद की आक्रामक गतिविधियों को रोकने में मदद की गुहार लगाई थी। अमेरिकी सरकार के एक अभिलेखीय दस्तावेज में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पांच दिसंबर, 1971 को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को लिखे गए पत्र का उल्लेख है। यह दस्तावेज दर्शाता है कि तीन दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के पश्चिमी मोर्चे पर हमला करने के दो दिन बाद उन्होंने ''खतरे की इस घड़ी'' में राष्ट्रपति निक्सन से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।

इंदिरा गांधी। फाइल

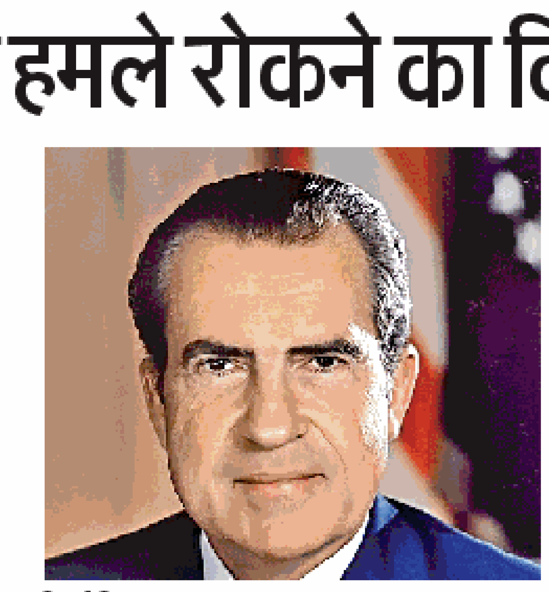

रिचर्ड निक्सन। फाइल

यह दस्तावेज न केवल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की युद्ध के प्रति अनिच्छा की पुष्टि करता है, बल्कि तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की पाकिस्तान से निपटने के लिए अमेरिका पर निर्भरता को भी उजागर करता है। मंगलवार को अमेरिकी अभिलेखों ने भाजपा नेताओं को भी बल प्रदान किया, जिन्होंने विपक्षी कांग्रेस पर यह आरोप लगाने के लिए हमला बोला था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को युद्धविराम समझौते को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था।

एक भाजपा नेता ने कहा, ''वह इंदिरा गांधी ही थीं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध से जुड़े मामलों पर अमेरिका से संपर्क किया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार कभी भी अमेरिका के किसी दबाव में नहीं आई और पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के खिलाफ स्वतंत्र और निर्णायक कार्रवाई की।'' राष्ट्रपति निक्सन को लिखे अपने पत्र में इंदिरा गांधी ने लिखा, ''सरकार और भारत की जनता आपसे आग्रह करती है कि आप पाकिस्तान को उस अनियंत्रित आक्रामकता और सैन्य दुस्साहस की नीति से तुरंत बाज आने के लिए राजी करें, जिस पर वह दुर्भाग्य से चल पड़ा है।''

राष्ट्रीय अभिलेखागार 'निक्सन प्रेसिडेंशियल मटेरियल' के दस्तावेज के अनुसार, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, ''क्या मैं महामहिम से अनुरोध कर सकती हूं कि आप पाकिस्तान सरकार पर अपने प्रभाव का प्रयोग करके भारत के विरुद्ध उनकी आक्रामक गतिविधियों को रोकें।'' इंदिरा गांधी द्वारा अमेरिका से पाकिस्तान की आक्रामकता को रोकने के अनुरोध का यह दस्तावेज उस दिन सार्वजनिक हुआ जब राहुल गांधी ने लोकसभा में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा में भाग लेते हुए मोदी सरकार पर सशस्त्र बलों को खुली छूट न देने का आरोप लगाया। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने सशस्त्र बलों को पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने से रोक दिया, युद्ध को आगे न बढ़ाने की अपनी मंशा से इस्लामाबाद को अवगत करा दिया और पाकिस्तानी रडार को निष्क्रिय किए बिना ही भारतीय लड़ाकू विमानों को युद्ध के लिए भेज दिया।

कह कर रहेंगे — माधव जोशी

****

945 मामलों में वांछित एक 'मोस्ट वांटेड' दंपती को कूचबिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दंपती खुद को बीएसएफ या सीआरपीएफ अधिकारी बताकर देशभर में बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र संचालकों को ठगते थे।

नोएडा, ग्रेनो, मुंबई और बेंगलुरु में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस

एनईपी के अमल को पांच साल पूरे होने के पर शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, एनईपी हमारे 2047 के सपने को पूरा करने का है राष्ट्रीय मिशन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों के दुनिया के दूसरे देशों में होने वाले पलायन को थामने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने चार और शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में अपने परिसर खोलने की मंजूरी दी है। इनमें आस्ट्रेलिया के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी को नोएडा में, वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय को ग्रेटर नोएडा (ग्रेनो) में, ला-ट्रोब को बेंगलुरु में और ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी को मुंबई में परिसर की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में चार अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों को भी जल्द ही अनुमति देने का फैसला लिया है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अमल के पांच साल पूरा होने के मौके पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विकसित भारत-2047 के सपने को पूरा करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारा राष्ट्रीय मिशन है। पिछले पांच वर्षों में हमने एनईपी के जरिये शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाए हैं। हालांकि हमें इससे संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि और ताकत से इसके अमल को रफ्तार देनी है। उन्होंने कहा कि भारतीयता ही एनईपी का मूल मंत्र है। वैज्ञानिक शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाओं को केंद्र में रखते हुए हम शिक्षा को राष्ट्र निर्माण के वृहद उद्देश्य से जोड़ रहे हैं।

धर्मेंद्र प्रधान। फाइल

अब तक 11 को मिली मंजूरी

यूजीसी अब तक 11 विदेशी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दे चुकी है। गुरुग्राम में साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय, बेंगलुरु में लिवरपूल विवि, मुंबई में यार्क व एबरडीन विश्वविद्यालय शामिल है। मुंबई और चेन्नई में आस्ट्रेलिया का वेस्टर्न आस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय, मुंबई में इटली का इंस्टीट्यूटो यूरोपियो डी डिजाइन, यूएसए की इलिनोइस इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, बेंगलुरु में आस्ट्रेलिया का ला-ट्रोब, ग्रेटर नोएडा में वेस्टर्न सिडनी, नोएडा में विक्टोरिया विश्वविद्यालय, मुंबई में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय को परिसर खोलने की मंजूरी दी गई है। इनमें साउथेप्टन जैसे कई विश्वविद्यालयों ने काम शुरू कर दिया है।

प्रधान की मौजूदगी में इस दौरान इन सभी विदेशी विश्वविद्यालयों को यह अनुमति दी गई। इस मौके पर प्रधान ने बताया कि अब तक 11 विदेशी विश्वविद्यालयों को परिसर खोलने की मंजूरी दी गई है। इनमें गिफ्ट सिटी (गुजरात) में मौजूद विदेशी विश्वविद्यालयों को छोड़ दें तो अब तक तीन विदेशी विश्वविद्यालयों ने देश में अपना परिसर खोल दिया है। जबकि, चार विश्वविद्यालयों को मंगलवार को सहमति पत्र सौंपे गए हैं। चार अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों को जल्द ही सहमति पत्र दे दिया जाएगा। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में दर्जनभर से अधिक राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में शिक्षाविद, कुलपति, शिक्षक आदि मौजूद थे।

चारों विदेशी विश्वविद्यालयों पर एक नजर

- **आस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी:** ग्रेटर नोएडा के कैंपस में स्नातक यानी बीए में बिजनेस एनालिटिक्स और बिजनेस मार्केटिंग के अलावा स्नातकोत्तर में नवोन्मेषण व उद्यमिता, एमबीए की पढ़ाई।
- **आस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी:** यह नोएडा में कैंपस बनाएगी। अंडर ग्रेजुएट से जुड़े बिजनेस, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए, आइटी में मास्टर के कोर्स संचालित करेगी।
- **आस्ट्रेलिया की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी:** यह बेंगलुरु में कैंपस में खोलेगी। यूजी में बिजनेस, (फाइनेंस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट), कंप्यूटर साइंस (एआइ, साफ्टवेयर इंजीनियरिंग) और जन स्वास्थ्य आदि की पढ़ाई होगी।
- **ब्रिटेन की बिस्टल यूनिवर्सिटी:** 2026 से मुंबई में अपना परिसर शुरू करेगी। प्रौद्योगिकी, नवाचार और कला क्षेत्रों में पढ़ाई कराने की तैयारी में है। यूजी और पीजी कार्यक्रमों के अलावा एआइ आदि पर भी कोर्स शुरू करेगी।

आपरेशन सिंदूर पर चर्चा से बाहर रखने पर मनीष तिवारी बोले- '... भारत की बात सुनाता हूं'

- कांग्रेस सांसद ने तिरंगे के सामने खींची गई अपनी तस्वीर के साथ फिल्म "पूरब और पश्चिम" का प्रसिद्ध गीत किया पोस्ट
- कांग्रेस ने शशि थरूर को भी नहीं दी थी वक्ताओं की सूची में जगह, इस पर थरूर ने कहा था- "मौनव्रत, मौनव्रत"

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद में आपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कांग्रेस की ओर बोलने का अवसर न दिए जाने पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मंगलवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अभिनेता मनोज कुमार की फिल्म ''पूरब और पश्चिम'' का प्रसिद्ध गीत ''भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं'', पोस्ट किया।

वैसे इस बात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थीं कि आपरेशन सिंदूर पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखने के लिए विदेश भेजे गए बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, शशि थरूर और अमर सिंह लोकसभा में पहलगाम हमले और पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर जारी बहस के दौरान अपनी पार्टी की तरफ से बोलेंगे या नहीं? हुआ भी वही, कांग्रेस ने तीनों को मौका नहीं दिया। बता दें कि थरूर ने आपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की लाइन पर लोकसभा में बोलने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने भी थरूर को पार्टी के वक्ताओं की सूची से बाहर कर दिया। बाद में जब संवाददाताओं ने इस संबंध में थरूर से संसद के बाहर सोमवार को पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था-''मौनव्रत, मौनव्रत।''

मंगलवार को मनीष तिवारी ने एक्स पर मीडिया की एक खबर का स्क्रीनशाट साझा किया, जिसका शीर्षक था-''सरकार के पक्ष में बोलेः क्यों आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने शशि थरूर और मनीष तिवारी को बोलने से रोका?'' इस खबर के स्क्रीनशाट और तिरंगे के सामने खींची गई अपनी एक तस्वीर के साथ मनीष तिवारी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा-'है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जय हिंद।' जब तिवारी से उनके पोस्ट के बारे में पूछा गया तो कहा- एक अंग्रेजी कहावत है- आप मेरी चुप्पियों को नहीं समझते तो आप मेरे शब्दों को नहीं समझेंगे।

मनीष दिवारी।

आपरेशन सिंदूर पर अपमानजनक पोस्ट करने वाली शिक्षिका को राहत नहीं

मुंबई, प्रेट्र : पुणे की एक शिक्षिका को आपरेशन सिंदूर के बाद वाट्सएप ग्रुप पर अपमानजनक संदेश और तस्वीरें पोस्ट करना भारी पड़ गया है। बांबे हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज मामले को रद करने से इन्कार कर दिया है। महिला ने वाट्सएप ग्रुप में एक पोस्ट किया था। इस वीडियो में राष्ट्रीय ध्वज जलते हुए दिख रहा था और पीएम मोदी का उपहास उड़ाया गया था।

स्कूलों की सुरक्षा जांच का राष्ट्रीय अभियान

- स्कूलों की सुरक्षा को लेकर समाचारीय अभियान आरंभ कर रहा है दैनिक जागरण
- सुरक्षा की पड़ताल करके संबंधित अधिकारियों को दी जाएगी जानकारी

जासं, नई दिल्ली: राजस्थान के एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से पिछले सप्ताह सात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। कई बच्चे घायल हो गए। स्कूल की जर्जर छत को लेकर संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत भी भेजी गई थी, लेकिन समय पर ठीक नहीं कराने या नया भवन नहीं बनाने के कारण ये दुर्घटना हुई। इस घटना के बाद देशभर में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। दैनिक जागरण अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए स्कूलों की सुरक्षा को लेकर एक राष्ट्रव्यापी समाचारीय अभियान आरंभ कर रहा है। इस अभियान के अंतर्गत स्कूलों के भवन,

कितने सुरक्षित हैं स्कूल?

क्लासरूम और शौचालयों की स्थिति से लेकर खेल के मैदान और बाउंड्रीवाल की पड़ताल की जाएगी। ये देखा जाएगा कि स्कूल की इमारत कब बनी, वह कितनी पुरानी हो चुकी है। वर्तमान में भवन किस हालत में हैं। क्लासरूम में दरवाजे खिड़कियां सही लगे हैं या नहीं। कक्षा में छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था है या नहीं। स्कूल में लड़के और लड़कियों के शौचालय अलग-अलग हैं या नहीं। छात्रों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है या नहीं। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि स्कूल की चारदीवारी है या कैंपस खुला हुआ है। स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क है या नहीं। अगर स्कूल में खेल का मैदान है तो वह किस हालत में है। छात्रों के लिए खेल की सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों की सुरक्षा है, ताकि जब अभिभावक बच्चे को स्कूल भेजें तो उनके मन में किसी तरह की आशंका नहीं रहे। वे बच्चों की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रह सकें। छात्र भी जब स्कूल जाएं तो बेखौफ होकर पढ़ाई-लिखाई कर सकें और उनके मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं हो। छात्रों और शिक्षकों का जीवन सुरक्षित रहे। इस समाचारीय अभियान में स्कूलों की सुरक्षा की पड़ताल के बाद जो कमियां पाई जाएंगी, उन्हें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि स्कूलों की खामियों पर ध्यान दें और देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के दैनिक जागरण के इस अभियान को सकारात्मक परिणाम तक पहुंचाया जा सके।

नरम हो रहा जदयू का रुख, चिराग भी हुए नरम

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना

- जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी बोले-अपराध को लेकर उनकी चिंता अस्वाभाविक नहीं

बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा (रा) के अध्यक्ष चिराग पासवान की तीखी टिप्पणी के मुद्दे पर जदयू ने टकराव के बदले समझौते का रुख अपना लिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को कहा कि आपराधिक घटनाओं पर चिराग की चिंता अस्वाभाविक नहीं है। चिराग ने भी नरमी का संकेत देते हुए कहा-मेरा लक्ष्य विधानसभा की सभी 243 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करना है। मेरे हर शब्द में उन्हें (जदयू) बगावत दिखती है। अगर मेरी बातों को पूरा सुन लेंगे तो उनकी मंशा शांत हो जाएगी।

चौधरी ने कहा कि चिराग की टिप्पणी को दूसरे अर्थ में नहीं लेना चाहिए। चिराग यह भी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य का काफी विकास हुआ है। हाल के दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं तो अपराधी पर कार्रवाई भी हो रही। बिहार के बाहर के शहरों से अपराधियों को पकड़ कर लाया गया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग ने कहा-मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। जब मैंने 243 सीट कहा था, उसके साथ ही ये भी कहा था कि हर सीट पर चिराग पासवान बनकर लड़ना होगा।

क्या एक ईमानदार सहयोगी की भूमिका यह होती है कि जितनी सीटों पर मैं चुनाव लड़ूं मात्र उन्हीं सीटों पर ध्यान दूं? जितनी सीटों पर भाजपा लड़े, उतनी ही सीटों पर प्रचार करें? जदयू वाले अपनी सीटों पर प्रचार करें? तो फिर हम कैसे सहयोगी हैं? क्या मैं 243 सीटों पर प्रचार के लिए नहीं जाऊं? कहा कि मेरा लक्ष्य सभी सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करना है।

ननों से मिला कांग्रेस व यूडीआइ का प्रतिनिधिमंडल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • रायपुर

- भाजपा ने भी भेजा केरल के महामंत्री के नेतृत्व में जांच दल
- सीपीआइ नेता वृंदा करात और एनी राजा भी पहुंचीं दुर्ग

दुर्ग रेलवे स्टेशन पर तीन आदिवासी युवतियों की मतांतरण के लिए तस्करी के आरोप में दो ननों की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में सोमवार को संसद परिसर में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को दुर्ग पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद फ्रांसिस जार्ज, एनके प्रेमचंदन, सप्तगिरि शंकर उल्का, बेनी बेहानन और कांग्रेस प्रभारी जरिता लैतफलांग शामिल थे। उन्होंने जेल में बंद आरोपित ननों से मुलाकात की और आरोप लगाया कि प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है।

प्रतिनिधिमंडल को पहले जेल के बाहर रोका गया था, लेकिन भूपेश बघेल के हस्तक्षेप के बाद उनकी मुलाकात संभव हो सकी। सांसदों ने संसद में बुधवार को इस मामले को उठाने का आश्वासन दिया। सीपीआइ नेता वृंदा करात और एनी राजा भी ननों से मिलने दुर्ग पहुंची थीं, लेकिन समय-सीमा का हवाला देकर उन्हें अगली सुबह आने को कहा गया, जिससे उन्होंने असंतोष व्यक्त किया।

इस बीच, भाजपा ने भी केरल के महामंत्री अनूप एंटनी के नेतृत्व में एक जांच दल भेजा। एंटनी ने प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही। उनका कहना था कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। उधर, गिरफ्तारी से पहले दुर्ग रेलवे स्टेशन पर ननों से मारपीट के आरोप को बजरंग दल ने खारिज किया है। संगठन की पदाधिकारी ज्योति शर्मा ने कहा कि यदि कांग्रेस के पास कोई प्रमाण है तो उसे सार्वजनिक किया जाए।

बता दें कि 25 जुलाई को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारायणपुर की तीन युवतियों को मिशनरियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इस दौरान जीआरपी ने नन प्रीति मेरी, वंदना फ्रांसिस और पास्टर सुखमन मंडावी को गिरफ्तार किया था। जांच में युवतियों को मतांतरण के लिए नौकरी का प्रलोभन देने की बात सामने आई थी।

वृंदा करात। फाइल

दोनों ननों और पास्टर की जमानत याचिका खारिज

दुर्ग में मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्विजेन्द्र नाथ ठाकुर की अदालत ने गिरफ्तार दोनों ननों और पास्टर की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने तीनों आरोपितों को आठ अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।

प्रियंका ने वो दर्द संसद में उठाया, जो हर भारतीय को महसूस होना चाहिए : एशान्या

जागरण संवाददाता, कानपुर

संसद में कांग्रेस महिला नेता प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को जब एशान्या के दर्द व आपबीती को लेकर चर्चा कर रहीं थीं तो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के स्वजन के जेहन में घटना से जुड़े जख्म ताजा हो रहे थे। शुभम की पत्नी एशान्या ने कहा कि पहली बार किसी ने देश के समक्ष पति के साथ हुई घटना को प्रमुखता से उठाया। प्रियंका ने संसद में जो भी कहा वो अक्षरशः सत्य है। घटना के समय पीड़ित परिवार मदद को गुहार लगा रहा था, लेकिन उस समय मौके पर न तो जवान थे, न स्थानीय पुलिस। प्रियंका ने वो दर्द संसद में उठाया जो हर हिंदुस्तानी को महसूस होना चाहिए। पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि स्थानीय दुकानदार भी मदद करने के बजाय बरगला रहे थे और आतंकी बारदात को झुठला रहे थे। स्थानीय दुकानदार, घोड़े वाले सभी आतंकियों से मिले थे।

एशान्या। स्वयं

पहलगाम में मृत शुभम की पत्नी से राहुल गांधी ने वीडियो काल पर कराई थी प्रियंका से बात

बीती 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में आतंकियों ने शुभम द्विवेदी की भी हत्या कर दी थी। वारदात के बाद राहुल गांधी जब शुभम के घर पहुंचे थे तो एशान्या ने आपबीती बताई थी। उसके बाद राहुल ने प्रियंका गांधी वाड्रा को वीडियो काल कर उनसे एशान्या से बात कराई थी। मंगलवार को संसद में प्रियंका ने जब एशान्या से हुई बातचीत को पूरे देश के सामने रखा तो शुभम के स्वजन ने भी कहा कि कांग्रेस सांसद ने वही बातें कहीं जो सत्य थीं। शुभम के पिता संजय, चाचा मनोज व पत्नी एशान्या के साथ सभी स्वजन ने संसद पर बोलते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को टीवी पर सुना।

श्रावस्ती में सरकारी जमीन कब्जाकर बनी मजार पर चला बुलडोजर

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती: नगर पालिका की भूमि पर कब्जा कर बनाई गई मजार को नौ घंटे तक चली कार्रवाई में आठ बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। मंगलवार सुबह प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। भिनगा-सिरसिया मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया था।

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में इमारती वन के लिए आरक्षित नगर पालिका की भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। धार्मिक आधार पर कब्जा बनाए रखने के लिए पहले यहां छोटी मजार बनाई गई, जिसके बाद चहारदीवारी उठाकर इसे भव्य रूप दिया गया। इस अतिक्रमण को चिह्नित करने के बाद नगर पालिका परिषद ने नोटिस जारी किया। किसी पक्षकार के सामने न आने पर अवैध निर्माण पर नोटिस चस्पा कर इसे हटाने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई।

चुनाव आयोग ने दिखाई सख्ती, कहा-मतदाता सूची के संशोधन कार्य में पक्षपात बर्दाश्त नहीं

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- ममता की चेतावनी के बीच आयोग का बंगाल के बीएलओ को सख्त निर्देश

चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को सख्त निर्देश देते हुए साफ कर दिया है कि मतदाता सूची के संशोधन कार्य में किसी तरह का पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अर्थ दंड भी लगाया जा सकता है। बता दें कि कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के बीएलओ को परोक्ष तौर पर आगाह करते हुए कहा था कि वह इस बात का ध्यान रखें कि वे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। लोगों को परेशानी न हो, इसका ध्यान रखें।

बंगाल में बीएलओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। उन्हें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बारे में खास तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। आयोग की ओर से बीएलओ को जारी निर्देश में कहा गया है कि उन्हें आयोग के अधीन काम करना होगा। आयोग के सारे निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा।

बांग्लादेशी दंपती का राजफाश: उत्तर 24 परगना जिले के हासनाबाद इलाके में फर्जी मतदाता परिचय पत्र व अन्य दस्तावेज बनवाकर पिछले छह साल से रह रहे बांग्लादेशी दंपती का पता चला है। मामला सामने आने के बाद से दोनों गायब हैं। उनके नाम अकबर अली गाजी व फरहाना गाजी हैं। दोनों के बांग्लादेश की मतदाता सूची में भी नाम बताया जा रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग बंगाल की मतदाता सूची में फर्जी लोगों के नाम शामिल कराने के मामले में दोषी पाए गए वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के दो अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।

प्रतीकात्मक

ममता डराने की कर रहीं कोशिश

बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में बीएलओ को डरा-धमकाकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से ममता के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

'बांग्लाभाषी प्रवासियों पर अत्याचारों पर राष्ट्रीय आयोगों ने आंखें मूंदीं'

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी प्रवासी लोगों पर कथित अत्याचारों पर आंखें मूंद लेने का आरोप लगाया। बीरभूम जिले में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक में ममता ने सवाल उठाया कि विभिन्न केंद्रीय आयोग बंगाल में किसी को छिपकली भी काट ले तो तुरंत कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है या उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, तो वे चुप रहते हैं। मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों में रह रहे बंगाल के प्रवासी कामगारों से घर लौटने का आग्रह किया।

सुवेंदु ने ममता पर फर्जी वीडियो साझा करने का आरोप लगाया : भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दिल्ली पुलिस द्वारा एक बांग्ला भाषी महिला और उसके बच्चे की पिटाई करने का फर्जी वीडियो पोस्ट करने का भी आरोप लगाया और इसे भ्रामक बताया। ममता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सुवेंदु ने कहा कि मुख्यमंत्री को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस बीच सुवेंदु के छोटे भाई और कांथी से लोकसभा सांसद सौमेंदु अधिकारी ने फर्जी वीडियो पोस्ट करने के मामले में ममता के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम थाने में पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई।

ममता बनर्जी। फाइल

ममता ने बंगालियों के उत्पीड़न पर चुप्पी को लेकर राष्ट्रीय आयोगों की आलोचना की

टाइम बम की तरह है असम और बंगाल में जनसांख्यिकी परिवर्तन : आरएन रवि

गांधीनगर, प्रेट्र : तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने असम और बंगाल सहित देश के कुछ हिस्सों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसे टाइम बम बताते हुए समाधान खोजने का आग्रह किया। महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में भाषा संबंधी विवादों के बीच कहा कि भाषा के नाम पर कटुता रखना भारत के चरित्र या संस्कृति में नहीं है। उन्होंने कहा कि यह देश हमेशा बाहरी आक्रमणों से लड़ने में कामयाब रहा है। लेकिन, जब आंतरिक मामलों की बात आती है तो अतीत में क्या हुआ था हमें इसे भी देखना चाहिए। 1947 में आंतरिक कलह के कारण भारत का विभाजन हुआ था। एक विचारधारा का पालन करने वाले लोगों ने घोषणा की कि वे हमारे साथ नहीं रहना चाहते। वह शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 के शुभारंभ के अवसर पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू), गांधीनगर में छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित कर रहे थे।

गुजरात में अल्पसंख्यक सदस्य के बिना भी बनी रहेगी समान नागरिक संहिता समिति

- समिति में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व न होने के आधार पर दायर की थी याचिका
- गुजरात हाई कोर्ट ने ठुकराई याचिका, विस्तृत आदेश बाद में जारी होगा

अहमदाबाद, प्रेट्र : गुजरात में अल्पसंख्यक सदस्य के बिना भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) समिति बनी रहेगी। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई पांच सदस्यीय यूसीसी समिति में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व न होने के खिलाफ याचिका गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता का आकलन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। जस्टिस नीरल एस. मेहता की एकल पीठ ने अब्दुल वहाब सोपारीवाला की याचिका खारिज की। विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा।

इस वर्ष चार फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी की आवश्यकता का आकलन करने तथा इसके लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने लिए समिति के गठन की घोषणा की थी। समिति की संरचना को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस समिति में अल्पसंख्यक समुदायों का एक भी सदस्य नहीं है।

इसमें कहा गया है कि प्रत्येक समुदाय और संबंधित हितधारकों के उचित प्रतिनिधित्व न होना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 15 (भेदभाव का निषेध) और 25 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

याचिका में अनुरोध किया गया था कि हाई कोर्ट सरकार को समिति में सुधार के लिए नए सदस्यों को शामिल करने का निर्देश दे जिनमें कानूनों के जानकार और सभी संबंधित समुदायों के प्रतिनिधि हों। याचिका में यह भी कहा गया कि समान नागरिकता संहिता लागू करने से पहले सरकार सभी धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के साथ परामर्श करे। यह भी कहा गया कि गुजरात में समान नागरिक संहिता संबंधी समिति के गठन हेतु कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई।

लड़के व लड़कियों के संबंधों में पवित्रता नहीं बची : संत प्रेमानंद

जागरण संवाददाता, वृंदावन

- बोले, चार लड़कों से मिलने वाली कैसे पति को समर्पित होंगी, इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित

संत प्रेमानंद ने कहा है कि मुगलकाल में अपना सम्मान बचाने के लिए हमारे यहां की स्त्रियों ने जान दे दी परंतु अब लड़के और लड़कियों के संबंधों की पवित्रता समाज के लिए चुनौती बन गई है। संत के अनुसार सौ में दो-चार कन्याएं ही ऐसी होंगी, जो पवित्र जीवन रखकर पुरुष को समर्पित होंगी, यही हाल लड़कों का है। जो पहले ही चार जगह संबंध बना चुके, वह एक-दूसरे के प्रति कैसे समर्पित होंगे? उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप को तो समाज के लिए जहर बताया। वहीं, संत के इस बयान को लड़कियों के विरोध में मान संत विरोध कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख व पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी संत के बयान की निंदा की है।

प्रसारित वीडियो में एक महिला श्रद्धालु ने शादी के बाद टूटते रिश्तों को लेकर प्रश्न उठाया था। कहा था कि बच्चे चाहे अपनी पसंद की लड़की से शादी करें या फिर माता-पिता की पसंद से, दोनों ही परिस्थितियों में परिणाम अच्छे नहीं दिख रहे। उत्तर में संत प्रेमानंद कहते हैं कि आजकल बच्चों के चरित्र पवित्र नहीं हैं। लड़कियों का एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप और तीसरे से व्यवहार और यह आदत हो जाती है। हमें जब चार होटल की आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का खाना अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह कोई युवक जब चार लड़कियों से संबंध रखता है तो वह पत्नी के प्रति वफादार कैसे रहेगा। इसका जिम्मेदार मोबाइल फोन है। बच्चे-बच्चियां किसी तरह से पवित्र मिल जाएं, तो भगवान का वरदान समझना चाहिए। बचपन में जो गलती हो गई उसकी बात छोड़ो। लेकिन, शादी होने के बाद सुधार होना चाहिए। इस वीडियो पर श्रीराधा केलिकुंज आश्रम का पक्ष जानने के लिए संत के अनुयायी नवल नागरी दास को कई बार काल की गई, वाट्सएप संदेश दिया, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

वीडियो पर संत समाज की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के सेवायत आचार्य प्रह्लादवल्लभ गोस्वामी ने कहा कि इससे महिला विरोधी मानसिकता नजर आती है, इन्हें अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। वहीं, सुभासपा प्रमुख ने कहा कि संत प्रेमानंद क्या लड़कियों की जांच करते हैं, उनके पास कोई जांच करने की मशीन है क्या? हम उनकी बातों से बिलकुल सहमत नहीं हैं। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं। भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी कभी दिवंगत इंदिरा गांधी के पास थी, मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं। यह महिलाओं की ही ताकत है।

संत प्रेमानंद।

लड़कियों के साथ लड़कों के चरित्र पर भी उठाए सवाल, मोबाइल संस्कृति दोषी

****

1800 करोड़ रुपये से अधिक के चिटफंड घोटाले का मामला सामने आया है दिल्ली में। आरोपित सोसायटी ने सात राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान में अपने कार्यालय खोले थे।

आज रवाना होगा निसार, उल्टी गिनती शुरू

पृथ्वी की बेहतर निगरानी की भारत को मिलेगी शक्ति, पूरी धरती पर नजर रखेगा नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार

श्रीहरिकोटा, प्रेट्र : पृथ्वी पर नजर रखने वाला सेटेलाइट नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) बुधवार को लांच किया जाएगा। इसरो का जीएसएलवी-एफ16 राकेट बुधवार शाम 5.40 बजे निसार के साथ श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरेगा और सेटेलाइट को सूर्य-समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करेगा। इस महत्वाकांक्षी मिशन के लिए 27.30 घंटे की उल्टी गिनती मंगलवार मंगलवार दोपहर 2.10 बजे शुरू हुई।

इंटरनेट मीडिया पर जारी अपडेट में इसरो ने कहा, जीएसएलवी-एफ16, निसार को कक्षा में ले जाने के लिए तैयार है। अंतिम तैयारियां चल रही हैं। लांचिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जीएसएलवी-एफ16 भारत के भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान की 18वीं उड़ान है। यह मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 102वां प्रक्षेपण होगा। यह सूर्य-समकालिक ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला जीएसएलवी राकेट का पहला मिशन भी है। हालांकि इसरो ने अतीत में रिसोर्ससेट और रीसेट सहित पृथ्वी पर नजर रखने वाले उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है, लेकिन इन उपग्रहों से एकत्रित डाटा भारतीय क्षेत्र तक ही सीमित था। इसरो और नासा मिलकर पहली बार ऐसा सेटेलाइट लांच कर रहे हैं जो पूरी धरती पर नजर रखेगा।

श्रीहरिकोटा में मंगलवार को प्रक्षेपण के लिए तैयार नासा-इसरो का संयुक्त सेटेलाइट निसार। एएनआइ

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन कह चुके हैं कि निसार हर मौसम में 24 घंटे पृथ्वी फोटो खींच सकता है। यह भूस्खलन का पता लगा सकता है, आपदा प्रबंधन में मदद कर सकता है और जलवायु परिवर्तन पर भी नजर रख सकता है। इस सेटेलाइट से भारत, अमेरिका और पूरे विश्व को लाभ होगा। यह पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस साल दिसंबर में व्योममित्र नामक मानव राबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके सफल होने के बाद अगले साल दो अन्य मानवरहित मिशन भी लांच किए जाएंगे। इस सफलता के बाद गगनयान मिशन मार्च 2027 में लांच किया जाएगा। गगनयान मिशन में पृथ्वी की 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में तीन अंतरिक्षयात्रियों को भेजा जाएगा।

धरती के इंच-इंच का हाल बताएगा निसार, किसानों को होगा फायदा

धरती में लगातार बदलाव हो रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तट रेखाएं पीछे हटती हैं, और ये परिवर्तन इतने धीमे होते हैं कि आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आज 30 जुलाई को नासा-इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार (एसएआर) उपग्रह निसार, इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उड़ान भरेगा। यह हर 12 दिनों में पृथ्वी की सतह को स्कैन करेगा और कुछ सेंटीमीटर जितने छोटे बदलावों को भी रिकार्ड करेगा। आइए जानते हैं निसार की विशेषताएं:

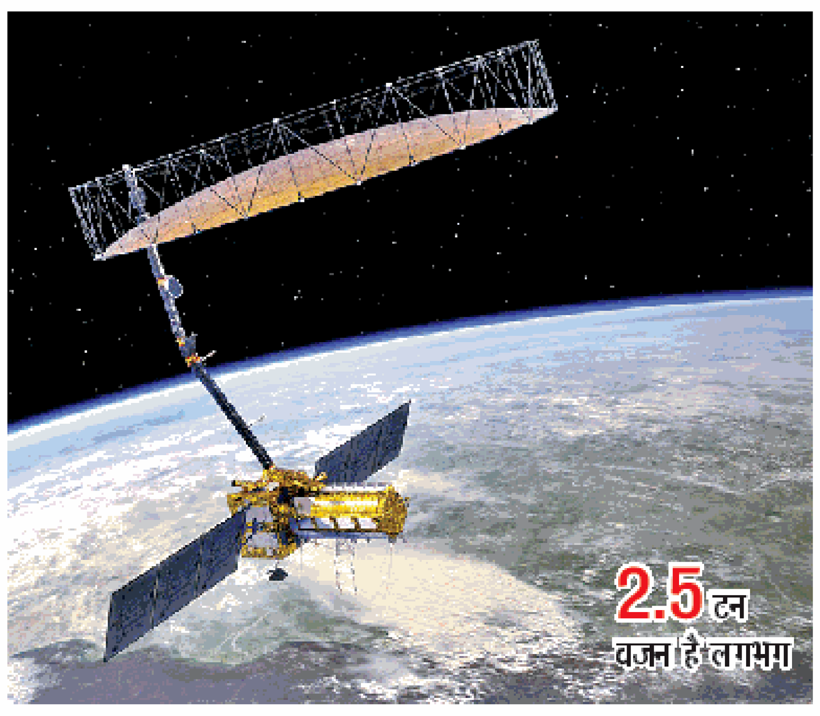

748 किमी पृथ्वी के ऊपर एक से दूसरे ध्रुव तक परिक्रमा करेगा

12 दिन का होगा निसार का स्कैन चक्र

240 किमी का क्षेत्र करेगा एक बार में कवर

3 वर्ष है निसार का नियोजित जीवनकाल

80 टेराबाइट डाटा प्रतिदिन उपलब्ध कराएगा। डाटा से भर जाएगी 150 हार्ड ड्राइव

पृथ्वी की बदलती सतह का कहानीकार

विज्ञानी पाल रोसेन ने निसार को पृथ्वी की बदलती सतह का कहानीकार बताया है। यह उपग्रह विभिन्न मौसमों में भूमि, बर्फ, जल और वनस्पतियों की गति को कैद करेगा, जिससे भूकंप विज्ञानियों, जलवायु विज्ञानियों, कृषिविदों, संरक्षणवादियों और अन्य के लिए महत्वपूर्ण डाटा उपलब्ध होगा। यह जानकारी सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध होगी। इससे बाढ़, तटरेखा के कटाव की चेतावनी समय पर मिल सकेगी। खाद्य सुरक्षा बेहतर होगी और जहाजों पर भी नजर रखी जा सकेगी। निसार हमें यह जानने में मदद करेगा कि ग्लेशियल झीलें कैसे विकसित होती हैं, जो जीएलओएफ (ग्लेशियल झील के फटने से आने वाली बाढ़) के जोखिम को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा। किसानों के लिए, यह पैदावार का पूर्वानुमान लगाने और फसल के नुकसान का आकलन करने में मदद करेगा। यह तेल रिसाव के दौरान भी सहायता करेगा।

दिन-रात पृथ्वी का निरीक्षण करेगा दोहरा रडार सिस्टम

निसार, नासा के एल-बैंड और इसरो के एस-बैंड नामक दोहरे रडार सिस्टम से लैस है, जो बादलों के पार देख सकता है और दिन-रात पृथ्वी का निरीक्षण कर सकता है। यह हर 12 दिनों में हिमालय, कैलिफोर्निया के समुद्र तटों, अमेजन वर्षावनों और पंजाब के खेतों को स्कैन करेगा। लंबी तरंगदैर्ध्य वाली एल-बैंड वनस्पतियों को भेदती है और चट्टानों व पेड़ों के तनों जैसी संरचनाओं के साथ इंटरैक्ट करती है। छोटी एस-बैंड पत्तियों और ऊपरी मिट्टी जैसे सतही विवरणों को पकड़ती है। ये विज्ञानियों को एक ही भूदृश्य को दो अलग-अलग लेंसों से देखने की सुविधा देगी, जिससे संरचना और परिवर्तन का पता चल सकेगा। नासा के विज्ञानी पाल रोसेन ने कहा कि यह हमें पृथ्वी की सतह को गतिमान फ्रेमों की एक श्रृंखला की तरह पढ़ने की सुविधा देगा। एसएआर का उपयोग करके, हम जमीन के विस्थापन को मिलीमीटर की सटीकता तक माप सकते हैं।

> यह अमेरिका और भारत के बीच पृथ्वी का इतने विस्तृत तरीके से अवलोकन करने वाला पहला मिशन होगा।
>
> **निकोला फाक्स**, नासा विज्ञान मिशन निदेशालय की एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर

1978 से जुड़ी हैं जड़ें

निसार की जड़ें 1978 में हुए एक सफल प्रक्षेपण से जुड़ी हैं, जब नासा ने सीसैट को कक्षा में स्थापित किया था। यह दुनिया का पहला एसएआर उपग्रह था। यह मिशन केवल 105 दिनों तक चला, लेकिन इस उपग्रह के आंकड़ों ने पृथ्वी अवलोकन को नया रूप दिया। अब, सीसैट के लगभग 50 साल बाद, निसार को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा।

जागरण रिसर्च

एक रात में एक ही घंटे के भीतर चार मुठभेड़, पांच बदमाशों को लगी गोली

- प्रतापगढ़ में देर रात पुलिस ने अपराधियों पर की बड़ी कार्रवाई
- सामूहिक दुष्कर्म, लूट, छिनैती में वांछित कुल छह बदमाश गिरफ्तार

प्रतापगढ़ के जेठवारा के पास सोमवार रात मुठभेड़ के दौरान मौजूद पुलिस टीम। सौ. मीडियासेल

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सोमवार रात पुलिस टीमों ने अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की। एक घंटे के भीतर चार जगहों पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इनमें पांच बदमाशों को गोली लगी। इनमें किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपित भी शामिल हैं। अन्य तीन आरोपित लूट, छिनैती और जानलेवा हमले में वांछित थे। पूरी कार्रवाई में कुछ छह बदमाश पकड़े गए। घायल बदमाशों को राजा प्रताप बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जिले के जेठवारा क्षेत्र की एक किशोरी 21 जून को बाबूगंज बाजार में बैंक आफ बड़ौदा की उप शाखा पर पैसा निकालने गई थी। वापस लौटते समय दो युवकों ने घर पहुंचाने के बहाने गाड़ी में बैठाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। इसके बाद उसे प्रसारित कर देने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते रहे। डरी-सहमी किशोरी ने यह बात सोमवार को स्वजन को तब बताई, जब आरोपित उसके घर तक पहुंच गए। इसके बाद पिता ने रियाज अहमद और आतिफ हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी। सोमवार रात खटवारा जेठवारा के पास दोनों आरोपित बाइक से आते दिखे। पुलिस ने रोकना चाहा तो फायर करने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दुष्कर्म के आरोपितों के पैर में गोली लग गई और वे गिर पड़े। आधे घंटे बाद 3:30 बजे दूसरी मुठभेड़ महेशगंज क्षेत्र में हुई। यहां पर छिनैती में वांछित अंशु दुबे को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी। उसने 30 जून को जनसेवा केंद्र संचालक राज कुमार कैथवास से तमंचे के बल पर 10 हजार नकद और लैपटाप लूटा था। उस पर प्रतापगढ़, प्रयागराज और भदोही में मुकदमे दर्ज हैं। इसके करीब 15 मिनट बाद ही सांगीपुर में हुई मुठभेड़ में प्रयागराज का शातिर बदमाश छैला बाबू सरोज पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। उसके खिलाफ प्रयागराज के कई थानों में केस दर्ज हैं। वह सांगीपुर में वारदात करने की तैयारी में था। चौथी मुठभेड़ करीब दस मिनट बाद फतनपुर में हुई, जिसमें अंतरजनपदीय बदमाश रवि सिंह उर्फ बंटी पुलिस की गोली से घायल हुआ। उस पर प्रतापगढ़ व प्रयागराज में 12 केस दर्ज हैं। उसका एक साथी बदमाश आकाश उर्फ रचित सिंह भी पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार के अनुसार कानून-व्यवस्था में खलल डालने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। जनता को चाहिए कि वह किसी सूचना या वारदात होने पर छिपाए नहीं। डरें भी नहीं। पुलिस को बताएं।

छह हाई कोर्ट को मिलेंगे नए जज

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली हाई कोर्ट समेत देश के छह उच्च न्यायालयों को नए जज मिलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कई वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालयों में जज बनाने की सिफारिश की है। तीन सदस्यीय कोलेजियम की बैठक में न्यायिक अधिकारी विमल कुमार यादव को दिल्ली हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कोलेजियम ने दो अतिरिक्त जजों - जस्टिस पार्थ सारथी सेन और जस्टिस अपूर्बा सिन्हा रे - को कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थायी जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। कलकत्ता हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज जस्टिस प्रसेनजीत बिस्वास, जस्टिस उदय कुमार, जस्टिस अजय कुमार गुप्ता, जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य, जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

मालेगांव विस्फोट मामले में कल आएगा कोर्ट का फैसला

राज्य ब्यूरो, जागरण • मुंबई

महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में 17 साल पहले हुए एक शक्तिशाली विस्फोट मामले में विशेष एनआइए कोर्ट 31 जुलाई को फैसला सुनाएगी। इस विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे।

पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित (सेवानिवृत्त) सहित सात लोग इस मामले में आरोपित हैं। यह राजनीतिक रूप से सर्वाधिक संवेदनशील मामलों में से एक रहा है, क्योंकि इसमें 'हिंदू आतंकवाद' और 'भगवा आतंकवाद' जैसे शब्दों का पहली बार प्रयोग किया गया। विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने सभी आरोपितों को 31 जुलाई को अदालत में पेश होने को कहा है।

विशेष अदालत में आने वाले इस फैसले के कारण परिसर की अन्य अदालतों को उस दिन अन्य मामलों की सुनवाई स्थगित रखने या वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करने को कहा गया है। 29 सितंबर 2008 को रमजान महीने के दौरान रात करीब 9.35 बजे हुए मालेगांव के भीखू चौक पर एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे। यह स्थान मुंबई से लगभग 291 किलोमीटर दूर है।

अदालत ने 19 अप्रैल को इस मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था और आरोपितों को फैसले के लिए आठ मई को पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि, विशेष न्यायाधीश लाहोटी ने फैसला सुनाने के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की है।

खडसे के दामाद की पुलिस हिरासत दो दिन और बढ़ी

राज्य ब्यूरो, जागरण • मुंबई: पुणे सत्र न्यायालय ने राकांपा एमएलसी एकनाथ खडसे के दामाद डा. प्रांजल खेवलकर सहित पांच आरोपितों की पुलिस हिरासत दो दिन और बढ़ा दी है। दो महिला आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन सभी को रविवार तड़के पुणे के एक पाश इलाके खराडी के एक बिजनेस होटल में हो रही रेव पार्टी से गिरफ्तार किया गया था। पेशे से डाक्टर प्रांजल खेवलकर राकांपा (शरदचंद्र पवार) की महिला विंग प्रमुख रोहिणी खडसे के पति एवं केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे के नंदोई हैं। पुलिस के अनुसार रेव पार्टी में आरोपितों के पास से उच्च गुणवत्ता वाली कोकेन, मरीजुआना, हुक्का और शराब बरामद हुई थी।

पुलिस का दावा है कि पार्टी में सेक्स वर्कर्स भी शामिल थीं। क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त निखिल पिंगले के अनुसार सभी आरोपितों को गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था।

धोबी दे रहा था सरकारी अस्पताल के आक्सीजन प्लांट पर ड्यूटी

जागरण संवाददाता, जालंधर

- जालंधर में तीन मरीजों की मौत के मामले में जांच में सामने आई जानकारी

सिविल अस्पताल जालंधर में तीन दिन पहले आक्सीजन प्लांट अचानक बंद होने से तीन मरीजों की मौत के मामले में जांच के दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जांच में पता चला है कि अस्पताल के आक्सीजन प्लांट पर आठ महीने से अस्पताल में तैनात धोबी दीपक की ड्यूटी लगाई जा रही थी। बड़ी बात यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दीपक की ड्यूटी अस्पताल प्रबंधन के कहने पर लगाई जाती थी। जिस आक्सीजन प्लांट से मरीजों को आक्सीजन दी जा रही थी, उसकी सात महीने से सर्विस भी नहीं हुई थी। नियमानुसार प्लांट की सर्विस तीन महीने के भीतर करवानी होती है।

छानबीन में पता चला है कि आक्सीजन प्लांट की देखरेख दो कर्मचारी कर रहे थे। एक सुपरवाइज व एक टेक्नीशियन। रविवार को टेक्नीशियन छुट्टी पर था और धोबी दीपक की ड्यूटी प्लांट पर लगाई गई थी। वहीं, एक महीने से आक्सीजन प्लांट के सेंसर भी बंद पड़े थे। प्लांट में काम करने वाले टेक्नीशियन व सुपरवाइजर ने अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी तक नहीं दी थी।

मेडिकल सुपरिटेंडेंट डा. राजकुमार ने बताया कि आक्सीजन प्लांट में खराबी आने के 10 मिनट बाद ही दूसरा प्लांट शुरू कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि ट्रामा सेंटर के आइसीयू में पांच मरीज दाखिल थे। रविवार रात आक्सीजन की सप्लाई बंद होने पर स्टाफ ने आक्सीजन कंसंट्रेटर से मरीजों को आक्सीजन की सप्लाई देने का प्रयास किया लेकिन तीन मरीजों को नहीं बचाया जा सका।

बिहार में पहली बार सफाई आयोग, कर्मियों के अधिकारों का होगा संरक्षण

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। बैठक में कुल 41 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। यहां जल्द ही सरकार पांच डेयरी प्लांट की स्थापना करेगी। इनपर करीब 317 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। यह आयोग सफाई कार्य में जुड़े समाज के वंचित वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने एवं उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही उनके अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा के लिए काम करेगा। आयोग इन कर्मियों के कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान और निगरानी का काम भी करेगा। मंत्रिमंडल ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना में संशोधन कर दिया है। पत्रकार पेंशन की राशि छह से बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक कर दी गई है।

निमिषा मामले में गलत जानकारी साझा कर रहे हैं कुछ लोग : सूत्र

नई दिल्ली, एएनआइ : यमन में हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के संबंध में कुछ लोगों द्वारा प्रसारित की जा रही जानकारी गलत है और मामले की वर्तमान स्थिति को नहीं दर्शाती है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को इस आशय की जानकारी दी। मुफ्ती कंथापुरम एपी अबुबकर मुसलियार के कार्यालय ने दावा किया था कि 'निमिषा प्रिया की मृत्युदंड की सजा, जिसे पहले निलंबित कर दिया गया था, अब रद कर दी गई है। सना में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में पहले अस्थायी रूप से निलंबित की गई मृत्युदंड की सजा को पूरी तरह से रद करने का निर्णय लिया गया।''

22 जुलाई को ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक और जाने-माने ईसाई धर्मप्रचारक डा. केए पाल ने भी यमन की राजधानी सना से एक वीडियो संदेश में दावा किया था कि यमनी और भारतीय नेताओं के कई दिनों के प्रयासों के बाद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी रद कर दी गई है। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की कृपा से उसे रिहा कर दिया जाएगा और भारत ले जाया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने राजनयिकों को भेजने और निमिषा को पेशेवर तरीके से सुरक्षित रूप से वापस ले जाने की तैयारी की है।

- मुफ्ती कंथापुरम अबुबकर मुसलियार ने दावा किया कि उसकी मृत्युदंड की सजा रद कर दी गई है

मूल रूप से केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली निमिषा को 2020 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या का दोषी ठहराया गया था और तब से वह वहीं जेल में है।

रैनिटिडीन में कैंसरकारी केमिकल की संभावित मौजूदगी की करें निगरानी : डीसीजीआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : रैनिटिडीन दवा में कैंसरकारी केमिकल की मौजूदगी को लेकर चिंताओं के बीच दवा नियामक डीसीजीआइ ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के दवा नियंत्रकों से कहा है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में दवा निर्माताओं को इस दवा में संभावित कैंसरकारी केमिकल- एन-नाइट्रोससोडिमिथाइलाएमिन - की निगरानी करने के लिए कहें।

रैनिटिडीन का उपयोग पेट में बनने वाले गैस की मात्रा कम करने के लिए किया जाता है। यह दवा एसिड रिफ्लक्स और पेट या आंतों के अल्सर के उपचार में भी किया जाता है।

भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआइ) ने 24 जुलाई को जारी पत्र में बताया कि एन-नाइट्रोससोडिमिथाइलाएमिन (एनडीएमए) की उपस्थिति के कारण रैनिटिडीन की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। इसे लेकर समय-समय पर विभिन्न उपाय किए गए हैं।

- दवा नियामक ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के दवा नियंत्रकों से कहा

प्रतीकात्मक

पिछले वर्ष दिसंबर में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट स वर्ष अप्रैल में 92वीं दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की बैठक में पेश किया गया। डीटीएबी ने सिफारिश की कि बड़ी समिति का गठन किया जाना चाहिए जो रैनिटिडीन के सभी पहलुओं पर गौर करेगी।

यह सुझाव भी दिया गया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) एनडीएमए की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए रैनिटिडीन दवा की सुरक्षा का आकलन करने के लिए अध्ययन कर सकता है। दवा निर्माताओं को एपीआइ/फार्मूलेशन में एनडीएमए स्तरों की निगरानी करनी चाहिए तथा दवा की समय अवधि (शेल्फ लाइफ) कम करने जैसे जोखिम आधारित उपाय भी करने चाहिए। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित निर्माताओं को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित दिए जाएं।

हरियाणा में पहली अगस्त से ही बढ़ेंगे कलेक्टर रेट

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

हरियाणा में बढ़े कलेक्टर रेट पहली अगस्त से ही लागू होंगे। सभी मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को गुरुवार तक हितधारकों से मिली शिकायतें और आपत्तियां निपटाने को कहा गया है। नया कलेक्टर रेट लागू होते ही जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे घर बनाना भी महंगा होगा।

इससे पहले बुधवार को कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेश जारी हुए थे। वित्तायुक्त राजस्व डा. सुमिता मिश्रा ने कहा था कि सरकार ने नए कलेक्टर रेट लागू करने का फैसला जरूर लिया है, लेकिन इसे अंतिम रूप देने से पहले तय प्रक्रिया अपनानी होगी। इसमें कलेक्टर रेट की सूची को सार्वजनिक करना, उस पर आमजन से आपत्तियां और सुझाव मंगवाना जैसे चरण शामिल हैं। अभी यह सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि नियमों के मुताबिक इसे कम से कम एक महीने पहले सार्वजनिक कर आपत्तियां मांगी जाती हैं। इसी प्रक्रिया की अनुपालन के अभाव में एक अगस्त से कलेक्टर रेट लागू करना संभव नहीं दिख रहा। इसके बाद कयास थे कि बढ़ा कलेक्टर रेट अभी लागू नहीं होगा। मंगलवार को वित्तायुक्त राजस्व कार्यालय की ओर से जारी नए आदेशों में स्पष्ट कर दिया गया है कि बढ़ी दरें पहली अगस्त से ही लागू होंगी। नए कलेक्टर रेट के लिए विभिन्न स्थानों पर पांच से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।

- मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को गुरुवार तक निपटानी होंगी शिकायतें और आपत्तियां

बिहार में थाने पर हमला, पथराव में छह पुलिसकर्मी घायल

जासं, कुमारखंड (मधेपुरा): भूमि विवाद से संबंधित आवेदन पर चार दिन बाद भी कार्रवाई नहीं किए जाने से आक्रोशित लोगों ने बिहार के मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाने पर जमकर उपद्रव किया। 20-25 की संख्या में थाने पहुंचे लोगों ने पहले तो पुलिस पदाधिकारियों से बहस की, फिर हाथापाई करने लगे। इस दौरान उपद्रवियों ने थानेदार पंकज कुमार को पीट दिया। उपद्रवियों ने थानेदार के बचाव में आए पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, जिसमें छह पुलिसकर्मी घायल हो गए। थाने में उपद्रव की जानकारी तत्काल जिला मुख्यालय को दी गई। आसपास के तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। एक पक्ष के द्वारा थाने पहुंचकर उपद्रव किया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एअर इंडिया में की 51 सुरक्षा खामियों की पहचान

नई दिल्ली, आइएएनएस : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एअर इंडिया के विमान संचालन में 51 सुरक्षा खामियों की पहचान की है। वार्षिक सुरक्षा आडिट में यह चूकें सामने आई हैं। इनमें पुरानी प्रशिक्षण पुस्तिकाएं, पायलट प्रशिक्षण की कमी, अयोग्य सिमुलेटर, उड़ान रोस्टर का प्रबंधन कर रहे प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, बिखरे हुए प्रशिक्षण रिकार्ड और कम दृश्यता संचालन के लिए अनुमोदनों में अनियमितताएं आदि शामिल हैं। इन 51 खामियों में से सात को डीजीसीए ने 'लेवल-वन'' यानी सबसे गंभीर श्रेणी में रखा है और इन्हें 30 जुलाई तक सुधारने का अल्टीमेटम दिया गया है। शेष 44 कमियां ऐसी हैं जिन्हें 23 अगस्त तक दूर करना आवश्यक है।

डीजीसीए ने एअर इंडिया से सभी सुरक्षा प्रोटोकाल के अनुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। यह कार्रवाई ऐसे समय की गई है जब हाल ही में सामने आया था कि एअर इंडिया का एक विमान बिना इमरजेंसी स्लाइड के निरीक्षण के उड़ान भर रहा था। यह स्लाइड विमान की इमरजेंसी लैंडिंग या निकासी के समय सबसे अहम सुरक्षा उपकरणों में से एक होती है। 23 जुलाई को डीजीसीए ने विभिन्न उल्लंघनों के लिए एअरलाइन को तीन शो-काज नोटिस जारी किए थे और इसमें 15 दिनों के भीतर उत्तर देने का समय दिया गया था।

- सात चूकों को डीजीसीए ने "लेवल-वन" यानी सबसे गंभीर श्रेणी में रखा है और इन्हें 30 जुलाई तक सुधारने का एअर इंडिया को अल्टीमेटम दिया

प्रतीकात्मक

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में बताया कि नियामक संस्था यानी डीजीसीए देशभर में समय-समय पर नियमित निगरानी, स्पाट चेक और नाइट इंस्पेक्शन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइंस सुरक्षा और रखरखाव मानकों का पालन कर रही हैं। इनके उल्लंघन की सूरत में नियमानुसार कार्रवाई की जाती है, जिसमें जुर्माना, चेतावनी या लाइसेंस निलंबन तक शामिल हैं।

महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए इंटरनेट मीडिया दिशानिर्देश जारी

मुंबई, प्रेट्र: महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कस दी है। वे इंटरनेट मीडिया पर सरकार की योजनाओं के बाबत टीका-टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर वालों के खिलाफ सरकार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। सोमवार को इस संबंध में सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक दिशानिर्देश जारी की है।

दिशानिर्देश के बारे में सरकार ने हवाला दिया है कि इससे सरकारी बाबुओं के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। कामों में गोपनीयता रहेगी और वे पहले से ज्यादा जवाबदेह होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी परिपत्र में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी अपने निजी और अधिकारिक इंटरनेट मीडिया अकाउंट को अलग रखेंगे। इंटरनेट मीडिया पर सरकारी नीति या सरकार के काम को लेकर प्रतिकूल टिप्पणी या आलोचना करने पर पूरी तरह से रोक है। वरिष्ठ अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी गोपनीय सरकारी दस्तावेज या आधिकारिक जानकारी को साझा करना, अपलोड करना या फारवर्ड करने पर पाबंदी लगाई है। उन्हें अपने काम या सफल योजनाओं की जानकारी देने की छूट होगी, लेकिन वे अपनी खुद की प्रशंसा नहीं की सकेंगे। साथ ही आपत्तिजनक, घृणास्पद या मानहानिकारक सामग्री को साझा करना, अपलोड करना या फारवर्ड करना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। नियमावली के अनुसार व्यक्तिगत इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल की फोटो को छोड़कर सरकारी पदनाम, लोगो, वर्दी, गणवेश या सरकारी संपत्ति का उपयोग फोटो, रील या वीडियो में नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

- इंटरनेट मीडिया पर सरकार की योजनाओं के बाबत टीका-टिप्पणी नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के घर में युवती ने खुद को मारी गोली, मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना : मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट थानांतर्गत चौबेपुर में मंगलवार को एक युवती ने पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी के घर में आत्महत्या कर ली। युवती ने पूर्व विधायक की लाइसेंसी पिस्टल से खुद को दाहिनी कनपटी में गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मृतका सुमन निषाद, जो चित्रकूट की निवासी थी, अपनी मां के साथ विधायक के घर में काम करती थी। गोली चलने की आवाज सुनकर घर में मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में भी आत्महत्या का ही मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि सुमन की हाल ही में शादी तय हुई थी और उसके बाद से वह मानसिक तनाव में थी। युवती के पिता की पूर्व में करंट से मौत हो चुकी है।

****

2.5 किलोग्राम का सोने का शंख व चक्र दान किया है चेन्नई की एक कंपनी ने मंगलवार को श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) तिरुपति स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का आधिकारिक संरक्षक है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 30 जुलाई, 2025

मंडी में बादल फटने से तीन की मौत

हिमाचल के मंडी में बारिश से फिर तबाही, पूर्व पार्षद का बेटा, बहू व पोते आए बाढ़ की चपेट में

200 से अधिक वाहन मलबे में दबने से हुए क्षतिग्रस्त, नेशनल हाईवे पर यातायात हुआ बाधित

जागरण संवाददाता, मंडी

हिमाचल में आपदा से प्रभावित सराज, करसोग व धर्मपुर के लोगों के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि मंगलवार तड़के बादल फटने से आई बाढ़ में मंडी शहर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। शहर के साथ लगते गंदर्भ जंगल में दो जगह बादल फटे,जिससे भारी नुकसान हुआ है। 200 से अधिक वाहन मलबे में दबने से क्षतिग्रस्त हो गए। विक्टोरिया पुल व बिंद्रावणी नाला के पास बंद हुआ पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 10 घंटे बाद बहाल हुआ। चार मील व जोगणी नाला के पास बाधित मनाली-कीरतपुर फोरलेन 15 घंटे बाद बहाल हुआ।

मंडी में सोमवार देर रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच तेज वर्षा आरंभ हो गई। मंगलवार तड़के गंदर्भ जंगल में जोनल अस्पताल के ऊपर की ओर पहाड़ी पर बादल फटने से भारी मात्रा में मलबा और पानी सैण मोहल्ला और पैलेस कालोनी की ओर आया। मलबा इतना अधिक था कि घरों में घुस गया। लोगों ने भागकर जान बचाई। मंडी-रिवालसर मार्ग, जेल रोड और जोनल अस्पताल मार्ग पर भी मलबा आ गया। नगर परिषद की पूर्व पार्षद कृष्णा देवी का बेटा बलवीर(45), बड़ी बहू सपना(47) और उनका बेटा अमनप्रीत बाहर आटोरिक्शा को निकालते समय बाढ़ में बह गए। तीनों के शव बरामद हो गए हैं। बड़ा बेटा दर्शन भी बाढ़ की चपेट में आया वह जोनल अस्पताल में उपचाराधीन हैं। आपदा के बाद स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला और फंसे लोगों को निकाला। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित डीसी, एडीसी और एडीएम भी सुबह ही मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य आरंभ किया।

मंडी में मंगलवार को बादल फटने के बाद मलबे में दबे वाहन और राहत एवं बचावकार्य में जुटे जवान। प्रेट्र

मप्र में नदियां उफान पर, शिवपुरी में 30 बच्चों को बचाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में लगातार वर्षा ने जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। नर्मदा, चंबल, सिंध, पार्वती और क्वारी नदियां उफान पर हैं। ओंकारेश्वर डैम के 14 गेट खोलने पड़े, जबकि नर्मदापुरम में तवा बांध के नौ गेट खोले गए। शिवपुरी के बदरवास क्षेत्र में एक निजी स्कूल की बस उफनते नाले में बह गई, लेकिन ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर 30 बच्चों को सुरक्षित निकाला। सागर के देवरी में एक गर्भवती महिला भी बह गई।

राजस्थान में वर्षा से जनजीवन अस्त-व्यस्त, 11 जिलों के स्कूलों में अवकाश घोषित

जासं, जयपुर: राजस्थान में भारी बारिश के चलते एक दर्जन से अधिक जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त है। कोटा बैराज, बीसलपुर, नवनेरा और गरडदा बांध से पानी की निकासी की जा रही है, जिस कारण निचले क्षेत्र में बसे गांव डूब गए हैं। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। परवन नदी में उफान के कारण बारां-झालावाड़ राजमार्ग बंद है। बूंदी के 20 से अधिक गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उधर, उदयपुर के पीपला गांव में सोमवार रात सरकारी स्कूल के दो कमरे भड़भड़ाकर गिर गए। धौलपुर की पार्वती नदी में एक दंपती के शव मिले हैं। वे दवा लेने बाइक पर निकले थे। चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी में भी दो युवकों के शव मिले हैं।

सार्वजनिक स्थलों पर किरपान के अधिकार के लिए एसजीपीसी पहुंची कोर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सिखों के किरपान पहनने और साथ ले जाने का मौलिक अधिकार पूरी तरह से लागू करने की मांग की है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला दिया गया है जो नागरिकों को अपने धर्म के पालन व प्रचार का अधिकार देता है।

याचिका की पृष्ठभूमि 23 जून 2024 को जोधपुर में घटी एक घटना है, जहां एक अमृतधारी सिख और पेशे से वकील युवक को राजस्थान न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में केवल इसलिए शामिल नहीं होने दिया गया क्योंकि उसने पांच इंच का किरपान धारण किया हुआ था। परीक्षा केंद्र पर मौजूद नोडल अधिकारी ने उन्हें परीक्षा हाल में प्रवेश देने से इन्कार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि किरपान केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि सिख धर्म के पांच ककारों (केश, कड़ा, कंघा, किरपान व कछहरा) में से एक अनिवार्य धार्मिक प्रतीक है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ऐसे समान दिशा-निर्देश तैयार करें जिससे परीक्षा केंद्रों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सिखों को धार्मिक प्रतीकों के साथ बिना भेदभाव प्रवेश मिल सके।

नैनीताल हाई कोर्ट में अंग्रेजी न बोल पाने वाले एडीएम को सुप्रीम राहत

जागरण संवाददाता, नैनीताल

- कोर्ट में अंग्रेजी नहीं बोल सकने की स्वीकारोक्ति से संबंधित मामले में आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

अपर जिलाधिकारी (एडीएम) नैनीताल के अंग्रेजी नहीं बोल सकने की स्वीकारोक्ति संबंधी मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने मतदाता सूची से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव व राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांग था कि अंग्रेजी नहीं बोल सकने वाले वाले अधिकारी को क्या निर्वाचन ड्यूटी का प्रभावी नियंत्रण सौंपा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस के साथ ही हाई कोर्ट में जनहित याचिकाकर्ता आकाश बोरा सहित 53 अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। 53 लोग वे हैं, जिनको बाहरी राज्यों का निवासी होते हुए यहां की मतदाता सूची में शामिल बताया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

दरअसल, 18 जुलाई को पंचायत चुनाव में नैनीताल के समीपवर्ती बुधलाकोट ग्राम पंचायत में उड़ीसा सहित अन्य राज्यों के लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एडीएम (प्रशासन) विवेक राय तथा कैंची धाम की एसडीएम मोनिका व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे। इस दौरान कोर्ट ने एडीएम से जानकारी मांगी तो उन्होंने हिंदी में जवाब दिया था। इस पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एडीएम के अंग्रेजी नहीं बोल सकने पर हैरानी जताई थी।

राज्य निर्वाचन आयोग व मुख्य सचिव को यह जांच करने के निर्देश दिए थे कि क्या एडीएम स्तर के अधिकारी को, जिन्होंने कोर्ट में स्वीकार किया है कि वह अंग्रेजी में नहीं बोल सकते, किसी कार्यकारी पद पर प्रभावी नियंत्रण सौंपा जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस निर्णय को विशेष अनुमति याचिका(एसएलपी) दायर कर चुनौती दी गई।

पंजाब में सीमा पार से आए छह ड्रोन गिराए, दो तस्कर गिरफ्तार

जागरण टीम, अमृतसर/तरनतारन: पंजाब में सीमा पार से आए छह ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया और 1.73 किलो हेरोइन, पिस्टल के पुर्जे और खाली मैगजीन बरामद की। वहीं, तरनतारन में बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त आपरेशन चलाकर .30 बोर के विदेशी पिस्टल, दो कारतूस, दो मोबाइल फोन समेत बाइक सवार दो तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के संबंध आइएसआइ के एजेंटों से होने की आशंका है। तरनतारन के गांव डल क्षेत्र में दो तस्करों द्वारा नशे व असलहे की खेप सप्लाई करने जाने की सूचना मिली थी। बीएसएफ जवानों ने बाइक सवार दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया।

एसएसपी दीपक पारिक ने बताया कि दोनों तस्करों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपितों की पहचान अर्शदीप सिंह उर्फ निक्का, हरमनप्रीत सिंह के रूप में हुई। उधर, बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर जिले के गांव रोड़ांवाला खुर्द, धनोए कलां, भैणी राजपूतां और दाऊके में सोमवार रात को दो और मंगलवार सुबह चार ड्रोन गिराए।

जैश आतंकी सज्जाद था पुलवामा हमले में इस्तेमाल कार का मालिक

राज्य ब्यूरो, जागरण ● श्रीनगर

- लोकसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा- केंद्र सरकार कार मालिक का पता लगाने में असमर्थ रही
- एनआइए की जांच में कार का चेसिस व इंजन नंबर चला था पता, छह बार बिकी थी कार

लोकसभा में मंगलवार को पहलगाम हमले के बहाने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलवामा हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, लेकिन वह चूक गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पुलवामा हमले में आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की गई कार के मालिक का पता लगाने में असमर्थ रही, जबकि हकीकत यह है कि कार का मालिक जैश आतंकी सज्जाद अहमद बट जून 2019 में अपने एक साथी आतंकी तौसीफ के साथ सुरक्षाबल के हाथों मुठभेड़ में मारा जा चुका है।

14 फरवरी, 2019 को जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर पुलवामा के लिथपोरा में जैश-ए-मोहम्मद के एक आत्मघाती आतंकी आदिल डार ने विस्फोटकों से भरी कार से सीआरपीएफ के काफिले में टक्कर मारी थी। इस हमले में 40 सीआरपीएफ कर्मी बलिदान हो गए थे। एनआइए ने घटनास्थल से मिले कार के टुकड़ों को जमा कर फारेंसिक और आटोमोबाइल विशेषज्ञों की मदद से पता लगाया था कि हमले में इस्तेमाल कार लाल रंग की मारुति इको है। हमले में इस्तेमाल कार का चेसिस नंबर एमए3ईआरएलएफ1एस00183735 और इंजन नंबर जी12बीएन164140 है। यह 2011 माडल की कार थी और इसे सबसे पहले अनंतनाग में हीवन कालोनी निवासी जलील अहमद हक्कानी ने खरीदा था। उसके बाद यह कार छह बार बिकी और अंतिम बार त्राल के पिंगलिश के रहने वाले सज्जाद अहमद बट ने खरीदी थी।

सज्जाद अहमद बट पहले जैश के लिए बतौर ओवरग्राउंड वर्कर काम करता था। उसे जैश आतंकी तौसीफ अहमद ने भर्ती किया था। जब उसे पता चला कि कार के मालिक का पता एनआइए को चल गया है, वह अपने घर से गायब हो गया।

श्रीनगर में अभियान जारी, आतंकियों के छिपने की सूचना

राज्य ब्यूरो, जागरण ● श्रीनगर

- एनआइए की टीम ने मारे गए तीनों आतंकियों के शव की जांच की

प्रतीकात्मक

पहलगाम हमले की जांच कर रही एनआइए की टीम ने मंगलवार को श्रीनगर के दाचीगाम में आपरेशन महादेव में मारे गए तीनों पाकिस्तानी आतंकियों के शवों की जांच की और उनके डीएनए के नमूने भी लिए गए हैं। इस बीच, सुरक्षाबल ने मुठभेड़स्थल और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चला रखा है। इसमें ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। इस क्षेत्र में तीन से चार और आतंकियों के एक दल के छिपे होने की सूचना है।

दाचीगाम-हारवन में महादेव की पहाड़ी पर जंगल में सोमवार को हुई मुठभेड़ में मारे गए पाकिस्तानी आतंकियों में सुलेमानी उर्फ सुलेमान शाह, यासिर उर्फ जिब्रान और अबु हमजा अफगानी शामिल थे। यही आतंकी पहलगाम हमले के गुनहगार भी हैं। आतंकी जिब्रान बीते वर्ष सोनमर्ग सुरंग परियोजना के काम में जुटे कर्मियों पर आतंकी हमले में भी शामिल था। हमजा अफगानी के बारे में कहा जाता है कि वह अफगानिस्तान में स्थित आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग प्राप्त कर चुका था और कुछ लोगों का दावा है कि

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि एनआइए के दल ने मारे गए आतंकियों के शवों की तस्वीरें ली। आतंकियों के पास से बरामद साजो सामान की भी जांच की गई। एनआइए ने पहलगाम हमले से पहले सुलेमानी व उसके साथियों को पनाह देने वाले दो आतंकी मददगारों परवेज और बशीर को भी लाया था, लेकिन अधिकारिक तौर पर इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो पाई है। मारे गए आतंकियों के पास से बरामद उनके कम्युनिकेशन सेट के डाटा की भी जांच की जा रही है। उनके पास से कथित तौर पर दो कम्युनिकेशन सेट बरामद हुए हैं, जिनमें से एक अल्ट्रा सेट है।

'आतंकी मारे गए हैं तो मुबारकवाद'

नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष डा. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वह नहीं जानते कि पहलगाम हमले में कौन आतंकी शामिल थे। अगर वह मारे गए हैं तो मुबारकवाद। इससे यह स्पष्ट होता है कि आतंकी और उनके संरक्षक कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होंगे।

पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के 22 बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाएंगे राहुल गांधी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● जम्मू

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 22 बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, जिन्होंने आपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी में अपने माता-पिता में से एक या दोनों को खो दिया था। ये बच्चे जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिला में नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इस बीच, कांग्रेस के प्रदेश प्रधान तारिक हमीद करा मंगलवार शाम को पुंछ पहुंच गए। राहुल गांधी ने प्रभावित बच्चों की शिक्षा व सहायता को देखने का जिम्मा यूथ कांग्रेस को सौंपा है। बुधवार को पुंछ में यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में करा भाग लेंगे और गोलीबारी में मारे गए लोगों के स्वजन से मुलाकात करेंगे।

करा ने बताया कि वह पुंछ जिला में प्रभावित बच्चों के लिए नेता प्रतिपक्ष की ओर से भेजी गई वित्तीय सहायता का वितरण करेंगे। यह सहायता बच्चों की शिक्षा के लिए है, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। करा ने कहा कि राहुल गांधी ने हमसे कहा है कि वह इन बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेंगे।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने आपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान व गुलाम जम्मू-कश्मीर में आतंकी ढांचे ध्वस्त कर दिए थे। इससे बौखलाए पाक ने पुंछ में नागरिक ठिकानों पर भारी गोलीबारी और ड्रोन से हमले किए थे, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई, जिनमें 13 नागरिक थे।

श्री हरिमंदिर साहिब को फिर मिली आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी

जागरण संवाददाता, अमृतसर

- एसजीपीसी को 15 दिन में 14 बार आई धमकी की ई-मेल
- स्टेट साइबर सेल ने डाटा मुहैया करवाने वाली कंपनी से साधा संपर्क

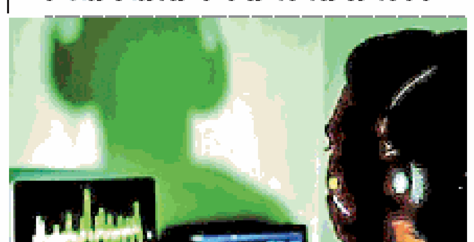

प्रतीकात्मक

अमृतसर स्थित श्री हरिमंदिर साहिब को फिर आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली है। 14 जुलाई से धमकियां मिलने का सिलसिला जारी है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) को 15 दिन में 14 बार ईमेल से धमकी मिल चुकी हैं। 22 जुलाई को मुख्यमंत्री भगवंत मान भी सुरक्षा का जायजा लेने के लिए श्री हरिमंदिर साहिब आए थे। सीएम ने कहा था कि पुलिस मुख्य आरोपित के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ईमेल भेजने वाले की लोकेशन बार-बार बदली जा रही है। आइपी एड्रेस कभी भारत के राज्यों में तो कभी विदेश में पता चल रहा है। इसे लेकर पंजाब पुलिस का स्टेट साइबर सेल डाटा मुहैया करवाने वाली कंपनी के संपर्क में है। ईमेल से संबंधित डाटा पुलिस के पास पहुंचने में एक से डेढ़ महीने तक का समय लग सकता है। एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि 14 बार धमकी की ईमेल मिलने के बाद भी पुलिस आरोपितों तक नहीं पहुंच पाई है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि जल्द मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहा आरोपित

इंटरनेट एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वाले अपराधी डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल अकसर गैर कानूनी गतिविधियों जैसे चोरी किए गए डाटा की बिक्री, साइबर हमले, गुमनाम धमकी भरा संदेश देने के लिए किया जाता है।

तहसील परिसर में गंदगी करने पर दी थी कार्रवाई की चेतावनी

प्रथम पृष्ठ से आगे

रिंकू ने कहा कि तहसील परिसर में जो भी गंदगी करेगा या अनुशासनहीनता करेगा, उस पर इसी तरह कार्रवाई होगी। उनके तेवर से नाराज वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ ही मिनट में आइएएस रिंकू ने माइक लिया और माफी मांगते हुए उठक-बैठक लगाने लगे। बार एसोसिएशन के इकाई अध्यक्ष सुभाष चंद्र शुक्ला व अन्य अधिवक्ताओं ने उन्हें ऐसा करने से रोका, जिसके बाद वह कार्यालय में चले गए। इसके बाद परिसर में साफ-सफाई भी शुरू हो गई।

2021 बैच के आइएएस रिंकू सिंह पीसीएस अधिकारी रह चुके हैं। 2009 में मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनाती के दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति में घोटाला पकड़ा तो उनपर जानलेवा हमला हुआ था। उन्हें सात गोलियां लगी थीं। एक आंख भी खराब हो गई। दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की तो फिर से गड़बड़ियां खोलना शुरू कर दीं, जिस पर उन्हें मानसिक रूप से बीमार भी बताया गया। 2018 में शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इसके बाद यूपीएससी की तैयारी की और 2021 में दिव्यांग कोटे से 683वीं रैंक मिली।

अवैध मतांतरण गिरोह के ग्रुपों और 3000 संदिग्ध नंबरों की छानबीन

जागरण संवाददाता, आगरा

- सरगना समेत गिरोह के 14 सदस्यों के मोबाइलों से मिले 15 हजार से अधिक नंबर

अवैध मतांतरण गिरोह के गिरफ्तार 14 सदस्यों से अब तक चली पूछताछ में 3000 से ज्यादा संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले हैं। इसके अलावा गिरोह के सदस्य दर्जनभर से अधिक वाट्सएप एवं अन्य मोबाइल एप ग्रुप के जरिये आपस में जुड़े थे। ग्रुप और संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच में पुलिस टीमें जुट गई हैं। वहीं, 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए 10 में से चार सदस्यों की चार दिन की और रिमांड कोर्ट ने स्वीकृत की है। इनमें गोवा से गिरफ्तार आयशा उर्फ एसबी कृष्णा व तीन अन्य शामिल हैं। बाकी छह सदस्यों को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। सरगना अब्दुल रहमान की रिमांड दो अगस्त तक है।

आगरा के सदर क्षेत्र की रहने वाली दो बेटियों को जाल में फंसा अवैध मतांतरण कराने वाले गिरोह के 10 सदस्यों को सात राज्यों से पकड़ा गया था। कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर लगातार पूछताछ में नए राजफाश हुए। चार दिन बाद दिल्ली से गिरोह का सरगना अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह गिरफ्तार हुआ। पूछताछ में कनाडा के बाद पाकिस्तानी सदस्यों की फंडिंग, देश विदेश से क्राउड फंडिंग के जरिये पैसे जुटाने की जानकारियां मिलीं। पुलिस, आइबी, एटीएस, एनआइए समेत अन्य जांच एजेंसियों की पूछताछ में कई नई जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन सदस्यों के मोबाइल में 15 हजार मोबाइल नंबर मिले, जिनमें से 3000 से ज्यादा संदिग्ध हैं।

ईडी ने छांगुर गिरोह की बेनामी संपत्तियों की भी शुरू की जांच

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : ईडी अवैध मतांतरण के लिए हो रही विदेशी फंडिंग की तह तक पहुंचने के लिए छांगुर को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। छांगुर से उसके व सहयोगियों के बैंक खातों में विदेश से आई रकम को लेकर पूछताछ की जा रही है। रकम से बलरामपुर व महाराष्ट्र में खरीदी गईं संपत्तियां को लेकर भी छांगुर से सवाल किए गए। ईडी उन लोगों की पहचान करने का प्रयास भी कर रही है, जिन्हें संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में सीधे लाभ हो रहा था। कई ऐसी संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं, जिनके छांगुर की बेनामी संपत्तियां होने का संदेह है।

श्रद्धा का महासावन

आत्मिक उत्थान का मार्ग खोलती है शिव की आराधना

श्रावण शिव आराधना का सबसे पवित्र महीना है। इस मास में प्रकृति, भक्ति और आध्यात्म का अनुपम संगम देखने को मिलता है। भक्तजन गंगा से जल भरकर शिवालयों में पहुंचते हैं और वह जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। शिव सनातन हैं। वह न आदि हैं, न अंत हैं। वे ही सृष्टि के मूल कारण हैं। ब्रह्मा को रचयिता, विष्णु को पालनकर्ता और शिव को संहारक कहा गया है, लेकिन स्कंद पुराण में वर्णन है कि ये तीनों ही माहेश्वर अंश से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात शिव ही मूल तत्व हैं। शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है शिवलिंग, जो स्वयं ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। शिव की जलहरी समस्त सृष्टि को समाहित करती है। वे ही साकार हैं, वे ही निराकार। विद्या व अविद्या, प्रकट और अप्रकट, दोनों ही शक्तियां शिव से ही प्रकट होती हैं। जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, जब जल ही जल था, तब भी शिव ही विद्यमान थे। यही कारण है कि उन्हें अनादि और अनंत कहा गया है। सावन में शिव पूजा का विशेष माहात्म्य इसलिए है, क्योंकि यह मास भक्तों को शिव की सान्निध्य प्राप्ति का अवसर देता है। जलाभिषेक, व्रत और रुद्राभिषेक के माध्यम से भक्त अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। श्रावण शिव की उपासना से स्वयं को अनुशासित कर इस जीवन और प्रकृति के आनंद को अनुभव करने की प्रेरणा देता है। सावन में की गई शिव आराधना न केवल सांसारिक कल्याण देती है, बल्कि आत्मिक उत्थान का मार्ग भी खोलती है। शिव में ही संसार है और शिव ही मोक्ष का द्वार हैं। इसलिए सावन, श्रद्धा और शिव का समागम जीवन को दिव्यता से भर देता है।

स्वामी कैलाशानंद गिरि
निरंजन पीठाधीश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर

सुकमा में मुठभेड़ में एक माओवादी ढेर, आईईडी विस्फोट में तीन जवान घायल

नईदुनिया न्यूज, सुकमा: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की गोगुंडा पहाड़ियों में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया, जबकि माओवादियों की ओर से लगाई आईईडी के विस्फोट में तीन जवान घायल हो गए। घायल जवानों में सलीम तिर्की, माड़वी मुकेश और बारसे रामा शामिल हैं। दो जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकाप्टर से रायपुर रेफर किया गया है। उधर, बीजापुर में सुरक्षा बलों ने जांगला थाना क्षेत्र के कोटमेटा, इदेर और इंगुम के जंगलों में चार माओवादी स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। सुकमा के एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि माओवादियों के शहीदी सप्ताह के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने सोमवार रात से सर्च आपरेशन शुरू किया था। एसटीएफ, सीआरपीएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम पहाड़ियों पर तैनात थी।

पोस्टमार्टम के बाद बदले टैग, शवों की हुई अदला-बदली

जागरण संवाददाता, मेरठ

मेरठ में दो परिवारों को उस समय एक और सदमा लगा जब अंतिम संस्कार से पहले पता चला कि उनसे स्वजन के शव गलत टैग लगने से आपस में बदल गए हैं। मृतक अभिनव के दोस्त ने मंगलवार को अंतिम संस्कार से पहले अंतिम दर्शन की इच्छा व्यक्त करते हुए मुंह खोला तो पता चला कि यह अमित का शव था। फिर दोनों के परिवार ने बातचीत की और एंबुलेंस से शवों को बदलकर वास्तविक जगह पहुंचाया। यह भयावह त्रुटि पलवल के पोस्टमार्टम हाउस पर हुई थी, जहां देर रात गलत टैगिंग कर दी गई। पलवल जिला नागरिक अस्पताल के एसएमओ सूबे सिंह ने बताया कि हमारे पास इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आई है और न ही ऐसा कोई मामला संज्ञान में है। यदि कोई शिकायत मिलती है तो जांच करवाई जाएगी। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी।

अमित अग्रवाल और अभिनव अग्रवाल सोमवार सुबह करीब सात बजे कार से मथुरा से पूजन सामग्री लेने गए थे। जैसे ही दोनों केजीपी एक्सप्रेसवे पर चांदहट थाना क्षेत्र में पहुंचे तो उनकी कार सड़क किनारे खड़े ट्राला में पीछे से जा घुसी। दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। सोमवार रात करीब दो बजे स्वजन पोस्टमार्टम कराने के बाद दोनों शवों को लेकर घर आ गए। पोस्टमार्टम हाउस पर शवों पर टैग गलत लगाने से दोनों शवों की अदला-बदली हो गई। मंगलवार अंतिम संस्कार से पहले मृतक अभिनव के दोस्त ने शव बदलने की जानकारी स्वजन को दी। अभिवन के स्वजन ने चेहरा खोलकर देखा तो यह शव अमित का निकला।

ओडिशा के मंत्री से 25 लाख की ठगी, एक गिरफ्तार

जासं, भुवनेश्वर: ओडिशा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा से 25 लाख रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने मंत्री को प्लाट दिलाने का झांसा देकर रकम ऐंठी थी। धनकनाल टाउन थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपित निरंजन सतपथी को मंत्री की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। शिकायत 26 जुलाई को दर्ज कराई गई थी। पात्रा ने वर्ष 2021 में प्लाट खरीदने के लिए 25 लाख रुपये अग्रिम दिए थे, लेकिन आरोपित ने जमीन नहीं दी। पुलिस के मुताबिक, सतपथी ने बाद में दो चेक दिए जो बाउंस हो गए। आरोपित ने लिखित में पैसे लौटाने का वादा भी किया, लेकिन उसे निभाया नहीं। मंत्री ने बताया कि यह लेनदेन तब हुआ था जब वे एक कंपनी में निदेशक पद पर कार्यरत थे। मंत्री ने ठगी का शिकार होने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर कार्रवाई हुई।

बिहार में अब सोनालिका ट्रैक्टर के नाम पर आवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

जासं, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)

- पूर्वी चंपारण में कोटवा में आवेदन पर दर्ज था, आवेदिका सोनालिका ट्रैक्टर, पिता स्वराज, माता कार देवी
- नवादा में डोगेश बाबू के नाम से किया गया आवेदन, डीएम ने जांच के लिए गठित की कमेटी

बिहार के पटना जिले में डाग बाबू के नाम पर आवास प्रमाण पत्र जारी होने के बाद अब पूर्वी चंपारण और नवादा जिले में भी इसी तरह के फर्जी आवास प्रमाण पत्र बनाने के प्रयास का मामला सामने आया है। आवास प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सका, इससे पहले ही मामला उजागर हो गया। दोनों जिलों के जिलाधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार का आवेदन प्राप्त होने के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है।

पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि आवेदन को निरस्त कर दिया गया है और आवेदक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर आवेदक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। थानाध्यक्ष प्रत्युष कुमार ने बताया कि आवेदन देने का मामला प्रकाश में आने के बाद उसे तुरंत निरस्त कर दिया गया है। जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार, आनलाइन आवेदन करने वाले ने आवेदिका का नाम सोनालिका ट्रैक्टर, पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर और माता का नाम कार देवी दर्ज किया है। दिलचस्प यह है कि आवेदन में आवेदक की तस्वीर के स्थान पर भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा की तस्वीर लगी हुई है।

नवादा में आवेदक के फोटोग्राफ की जगह कुत्ते की तस्वीर : नवादा जिले के सिरदला अंचल में लोक सेवाओं के अधिकार (आरटीपीएस) के तहत डोगेश बाबू नाम से एक आवासीय प्रमाणपत्र के लिए आनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन में आवेदक के फोटोग्राफ की जगह एक कुत्ते की तस्वीर अपलोड की गई है। आवेदक के पिता का नाम "डोगेश बाबू का पापा" और माता का नाम "डोगेश बाबू की मम्मी" अंकित है। नवादा के डीएम रविप्रकाश ने संज्ञान लिया है और सिरदला अंचल के प्रभारी सीओ अभिनव राज को प्राथमिकी कराने का निर्देश दिया है। मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी भी गठित की गई है।

****

10.33 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन 1 जुलाई तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत वितरित किए जा चुके हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में यह जानकारी दी।

देवघर में हादसे में छह कांवड़ियों की मौत, 27 घायल

बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के बाद बस से बासुकीनाथ जा रहे थे कांवड़िये, बस और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर

जागरण संवाददाता, देवघर

सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त बस। जागरण

- झारखंड सरकार ने की मृतकों के परिवार को एक लाख व घायलों को 20 हजार सहायता राशि देने की घोषणा

देवघर एम्स में भर्ती घायल कांवरिया का हाल जानने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डा. इरफान अंसारी, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा

देवघर में चल रहे श्रावणी मेले के आनंद के बीच मंगलवार सुबह हुए एक हादसे ने छह जिंदगियां छीन लीं। बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करने के बाद बासुकीनाथ जा रहे कांवड़ियों से भरी एक बस और ट्रक की टक्कर में छह कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 27 घायल हो गए। दुर्घटना देवघर-हंसडीहा मार्ग पर मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक के निकट हुई। दुर्घटना में बस चालक की भी मौत हो गई है।

घटना पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व राज्यपाल संतोष गंगवार ने दुख जताते हुए पीड़ित लोगों व उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। झारखंड सरकार ने मृतकों के परिवार को एक लाख रुपये तथा घायलों को 20-20 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने देवघर में अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लिया और चिकित्सकों को इलाज के लिए निर्देश दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। कांवड़िये बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के बाद बस से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित बासुकीनाथ धाम जा रहे थे। देवघर के बाद बासुकीनाथ में भी जलार्पण करने की परंपरा है। बस में सवार कावड़ियों के अनुसार चालक को लगातार झपकी आ रही थी। कुछ कांवड़ियों ने इसे लेकर रास्ते में रोका-टोका भी था। जमुनिया चौक पहुंचने के दौरान भी चालक को झपकी आई और बस की सामने से आ रहे खाली सिलिंडर लदे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर से बस का चालक सीट समेत नीचे गिर गया, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद बस बिना चालक के लगभग 200 मीटर तक दौड़ी और एक ईंट के ढेर से टकराकर रुक गई। यात्री चिल्लाते हुए जान-बचाने की गुहार लगाते रहे। चालक और तीन महिलाओं समेत कुल पांच की मौके पर और एक की अस्पताल में मौत हो गई।

न्यूज गैलरी

राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनाई जाएगी फिल्म

इंदौर: इंदौर के ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड पर फिल्म बनेगी। राजा के परिवार ने फिल्म डायरेक्टर एसपी निंबावत के साथ करार किया है। न्यायिक प्रक्रिया के बीच मंगलवार को राजा के भाई विपिन और सचिन ने घर पर पत्रकारवार्ता कर इस बारे में जानकारी दी। बता दें कि 11 मई को शादी के बाद 20 मई को राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ शिलांग में हनीमून पर गए थे। वहां राजा की 23 मई को हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से पत्नी लापता थी। शिलांग पुलिस ने गाजीपुर से सोनम को व इंदौर से उसके प्रेमी राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया था। (नईदुनिया प्रतिनिधि)

मप्र में वक्फ बोर्ड ने आय की वसूली के लिए दिया नोटिस

नईदुनिया, भोपाल: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों से अर्जित वैध और अवैध आय की वसूली के लिए कठोर कदम उठाए हैं। प्रदेशभर में एक हजार से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। हाल ही में भोपाल की एक संपत्ति से संबंधित 27 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष डा. सनवर पटेल ने बताया कि इतनी बड़ी राशि की वसूली के लिए किसी भी राज्य के वक्फ बोर्ड ने पहले कभी नोटिस नहीं दिया। यह नोटिस इदारा यतीम खाना शाहजहांनी से संबंधित है। (राब्यू)

नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपपत्र पर फैसला टला

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के प्रश्न पर फैसला फिलहाल टाल दिया है। अदालत ने इस मामले में अब सात और आठ अगस्त की तारीख तय है ताकि कुछ स्पष्टीकरणों पर बहस हो सके। इससे पहले 15 जुलाई को राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने दोनों पक्षों की अंतिम बहस के बाद मंगलवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था। (जासं)

भारत-नेपाल सीमा पर चीनी नागरिक गिरफ्तार

सिलीगुड़ी: बंगाल के सिलीगुड़ी में भारत-नेपाल सीमा पर सोमवार देर रात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। जांच के क्रम में उसके दस्तावेजों और बयानों में असंगतियां पाए जाने पर एसएसबी को संदेह हुआ। इसके बाद उससे पूछताछ की गई और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को आरोपित को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपित के पास से चीन का नागरिकता कार्ड और स्विट्जरलैंड का एक पासपोर्ट बरामद किया गया। (जासं)

बिहार में मोबाइल चोर को पकड़ ग्रामीणों ने पीटा, मौत

बहादुरगंज (किशनगंज): बिहार के किशनगंज जिले में सोमवार की रात मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक 35 वर्षीय सब्बीर आलम को ग्रामीणों ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि मृतक के स्वजन के आवेदन पर केस दर्ज कर छह लोगों को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के अनुसार डूबादांगी गांव में मोबाइल चोरी के आरोप में 35 वर्षीय सब्बीर आलम को लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। (जासं)

फर्जी टिकट कलेक्टर बन वसूली करता गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मेरठ: सिटी रेलवे स्टेशन पर फर्जी टिकट कलेक्टर बनकर बेटिकट यात्रियों व वेंडर्स से वसूली करने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित के पिता लोको पायलट थे। आरोपित कई दिनों से वसूली कर रहा था। मुख्य टिकट निरीक्षक ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कराया है। जयपुर का 38 वर्षीय मुकेश चौधरी मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर वेंडर्स को टिकट कलेक्टर बताकर वसूली कर रहा था। (जासं)

सड़क हादसे को रोकने में देश में पहली बार होगा एआइ का प्रयोग

निशांत यादव • जागरण

- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दी उप्र के पायलट प्रोजेक्ट को एनओसी

लखनऊ: सड़क दुर्घटनाओं के पीछे तकनीकी गड़बड़ियों का पता जल्द ही एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से लगाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनेगा जहां एआइ और बिग-डाटा एनालिटिक्स आधारित माड्यूल दुर्घटना के न केवल सटीक कारणों का पता लगाएगा, बल्कि दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की एआइ और बिग-डाटा एनालिटिक्स आधारित सड़क -सुरक्षा पायलट परियोजना को एनओसी प्रदान कर दी है। परिवहन विभाग ने परीक्षण के आदेश दे दिए हैं।

दरअसल, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं वाले राज्यों में से एक है। इसी वर्ष जनवरी से जून तक कुल 25,830 सड़क दुर्घटनाओं से 14,205 लोगों की मौत हुई है। दुर्घटनाएं खराब रोड इंजीनियरिंग, मौसम की गड़बड़ी, ड्राइवरों की कमी या अन्य कारणों से हुईं। इसका आज तक कोई विश्लेषण ही नहीं किया गया है। यही कारण है कि कई स्थानों पर दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है।

सही कारणों का चलेगा पता

पूर्व अपर आयुक्त प्रवर्तन व सड़क सुरक्षा पुष्पसेन सत्यार्थी ने बताया कि हादसों के बाद पहुंचे पुलिस अधिकारी की मैन्युअल तरीके से लगाई गई रिपोर्ट को ही आधार माना जाता है। ऐसे में हादसों का असल कारण पता नहीं चलता है। विदेश में हादसे कम करने के लिए एआइ का उपयोग पहले से हो रहा है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) वाले उप्र के 17 शहरों में इसे लागू किया जा सकता है। अधिक हादसों वाले दूसरे जिलों को चिह्नित कर वहां एआइ का उपयोग किया जा सकता है।

किशोरी को अगवा कर कराई शादी, तमंचा सटा दिलवाया आशीर्वाद

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नगर पंचायत पृथ्वीगंज की अध्यक्ष नीलम सरोज के देवर व सपा नेता संजय सरोज ने गुर्गों संग दूसरे गांव की किशोरी का अपहरण कर लिया। इसके बाद एक गुर्गे से मंदिर में जबरन शादी करवा दी। लड़की के माता-पिता से तमंचे के बल पर आशीर्वाद दिलवाया। पुलिस ने संजय सरोज समेत तीन नामजद व तीन अज्ञात आरोपितों पर केस दर्ज कर लिया। संजय टेरर फंडिंग के आरोप में एक दशक पहले पकड़ा गया था।

लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि संजय सरोज अपने पांच गुर्गों के साथ 11 जुलाई को उनके घर आ गया। कक्षा नौ में पढ़ने वाली 17 वर्षीय बेटी को जबरन कार में डालकर ले गया। दूसरे दिन थाने जाने के दौरान रास्ते में मुझे व मेरे पति को अगवा कर घर ले गया। वहां पर तमंचा सटाकर कहा कि चुपचाप चलकर शीतला माता मंदिर में बेटी की शादी में शामिल हो जाओ। मंदिर में संजय ने अपने गुर्गे मोहित सरोज से बेटी की जबरन शादी करा दी। तमंचे के बल पर लड़की के आशीर्वाद दिलाते हुए फोटो खींच ली और वीडियो बना लिया। कहा कि अब जाओ, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। शिकायत करने पर जान से मार देंगे। पुलिस ने लड़की की मां की तहरीर पर संजय सरोज, मोहित सरोज तथा मोहित के पिता लुरखुर सरोज पर केस दर्ज किया है।

आंध्र प्रदेश में एसबीआइ शाखा से 10 किलो सोना, 38 लाख नकदी चोरी

हिंदूपुर (आंध्र प्रदेश), प्रेट्र: आंध्र प्रदेश में एसबीआइ की शाखा से चोरों ने 10 किलो सोना और 38 लाख रुपये नकदी चोरी कर ली। पिछले चार सालों से इस शाखा में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि यह घटना श्री सत्यसाई जिले के थुमुकुंटा गांव में हुई।

हिंदूपुर के पुलिस अधिकारी केवी महेश ने कहा कि चोरी रविवार लगभग दो बजे हुई। पुलिस को घटना की जानकारी सोमवार को मिली। महेश ने बताया, हिंदूपुर मंडल के थुमुकुंटा एसबीआइ शाखा से 38 लाख रुपये नकदी और 10 किलोग्राम सोना चोरी हो गया। संदेह है कि चोर बैंक की इस शाखा में करीब दो घंटे तक रहे। बैंक की सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति को देखा गया।

पुलिस को संदेह है कि अन्य लोग बाद में आए होंगे। पुलिस इंस्पेक्टर ने तीन महीने पहले ही सुरक्षा खामियों के बारे में आगाह किया था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस बीच, पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश की जा रही है।

डिंपल यादव पर टिप्पणी करने वाले मौलाना को सपाइयों ने जड़े थप्पड़

जागरण संवाददाता, नोएडा

- एक निजी टीवी चैनल के डिबेट में पहुंचे थे मौलाना साजिद रशीदी
- मौलाना ने अज्ञात के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत, जांच शुरू

मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ मारते सपा नेता। वीडियो ग्रैब

मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी को सपा कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ जड़ दिए। मौलाना एक टीवी चैनल के स्टूडियो में मंगलवार को डिबेट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। डिबेट समाप्त होने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने दर्शक दीर्घा से उठकर मारपीट की। सपाई सांसद डिंपल यादव पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आक्रोशित थे। मारपीट का 16 सेकंड का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। मौलाना ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। सोमवार को लखनऊ के विभूतिखंड थाने में मौलाना के खिलाफ सपा नेता प्रवेश यादव मुकदमा भी दर्ज करा चुके हैं।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में मौलाना साजिद रशीदी डिबेट के बाद खड़े नजर आ रहे हैं। उनके आसपास एंकर के अलावा कुछ लोग भी हैं। दर्शक दीर्घा में बैठे तीन-चार लोग यकायक मौलाना के नजदीक जाते हैं। पहले वह बात करते हैं। मौलाना कुछ समझ पाते उससे पहले वह कई थप्पड़ उन्हें जड़ देते हैं। मारपीट करने वाले गौतमबुद्ध नगर के सपा नेता बताए जा रहे हैं। सपा पदाधिकारियों का कहना है कि मोहित नागर टीम संग टीवी चैनल के डिबेट कार्यक्रम में गए थे। वहां पर मौलाना अभद्र टिप्पणी कर रहे थे।

जिरीबाम हत्याकांड में एक महीने में चार्जशीट दाखिल करे एनआइए: हाई कोर्ट

इंफाल, प्रेट्र: मणिपुर हाई कोर्ट ने एनआइए को जिरीबाम हत्याकांड में एक महीने में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश के. सोमशेखर और जस्टिस अहंतेम बिमोल सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष नवंबर में जिरीबाम जिले में सुरक्षा शिविर पर हमले के दौरान तीन महिलाओं और तीन बच्चों का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी।

हाई कोर्ट ने कहा, आज तक दोषियों/आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। केंद्र के वकील ने सूचित किया कि एजेंसी द्वारा जांच की गई है। आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। केंद्र के वकील ने अदालत के समक्ष दो सेट सील किए हुए लिफाफे पेश किए, जिनमें जांच की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट शामिल थी। हाई कोर्ट ने कहा, चार्जशीट के संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है। अगली सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित है।

अर्थशास्त्री मेघनाद देसाई का निधन

नई दिल्ली, प्रेट्र: प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और ब्रिटेन के प्रतिष्ठित हाउस आफ लाडर्स के सदस्य मेघनाद देसाई का मंगलवार को निधन हो गया है। उन्होंने 84 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए दुख जताया है।

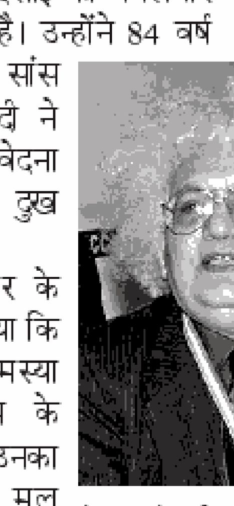

मेघनाद देसाई। फाइल/प्रेट्र

लंदन में परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण गुरुग्राम के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। मूल रूप से गुजरात में जन्मे मेघनाद देसाई ने बांबे विश्वविद्यालय से अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी करने के बाद लंदन स्कूल आफ इकोनामिक्स में अध्यापन का काम किया। उन्होंने अपने जीवन काल में एक से बढ़कर एक किताबें लिखी हैं। पीएम मोदी ने इंटरनेट मीडिया साइट एक्स पर किए पोस्ट में लिखा कि प्रतिष्ठित विचारक, लेखक और अर्थशास्त्री श्री मेघनाद देसाई के निधन से व्यथित हूं। वह सदैव भारत और भारतीय संस्कृति से जुड़े रहे। उन्होंने भारत-ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारी उन चर्चाओं को याद करूंगा, जहां उन्होंने विचार साझा किए थे। पद्म भूषण से सम्मानित देसाई ने 1965 से 2003 तक लंदन स्कूल आफ इकोनामिक्स में अर्थशास्त्र पढ़ाया। वे 1971 में लेबर पार्टी में शामिल हुए और जून 1991 में हाउस आफ लाडर्स के सदस्य बनाए गए थे। 2020 में देसाई ने ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि पार्टी अपने भीतर यहूदी विरोधी नस्लवाद से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रही थी। हाउस आफ लाडर्स में उनके साथी सदस्य रामी रेंजर ने उन्हें समुदाय का एक स्तंभ बताया, जिन्होंने अथक परिश्रम किया और ब्रिटेन के संसद भवन में गांधी स्मारक प्रतिमा की स्थापना सहित कई सराहनीय कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

सिर्फ कानूनी सलाह देने के लिए वकील को नहीं किया जाना चाहिए समन : सुप्रीम कोर्ट

- अपराध में मुवक्किल की मदद करने वाले वकील को कर सकते हैं समन
- एसजी ने जताई सहमति, एससीबीए व एससीएओआरए ने रखीं दलीलें

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर कोई व्यक्ति केवल वकील के तौर पर काम कर रहा है, तो जांच एजेंसियों को उसे जांच के दायरे में आए मुवक्किल को कानूनी सलाह देने के लिए समन नहीं करना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वकील अपराध में मुवक्किल की सहायता कर रहा है, तो उसे समन किया जा सकता है।

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने जांच के दौरान मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने या कानूनी सलाह देने के लिए जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को समन करने के बारे में स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पीठ ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-आन-रिकार्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) की दलीलें सुनीं, जिनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और अधिवक्ता विपिन नायर ने किया। शुरुआत में एससीबीए के अध्यक्ष सिंह ने मनमाने ढंग से समन जारी करने से कानूनी पेशे पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "अगर मुवक्किलों को सलाह देने पर वकीलों को नियमित रूप से समन किया जाएगा, तो संवेदनशील आपराधिक मामलों में परामर्श देने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा।" उन्होंने कहा कि सीबीआइ ने जैसे सुरक्षा उपाय अपनाए हैं, वैसे उपायों को लागू करना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव किया कि किसी वकील को समन करने की अनुमति जिले के एसपी को देनी चाहिए और उससे पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसकी जांच करनी चाहिए। पीठ ने संकेत दिया कि न्यायिक निगरानी से जांच के अतिक्रमण पर रोक लग सकती है। ईडी की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वकीलों को केवल कानूनी सलाह देने के लिए समन नहीं करने की बात से सहमति जताई। कहा कि यह पेशा खुद प्रविधान के तहत संरक्षित है। लेकिन केवल वकीलों को समन करने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति और गैर-वकीलों के लिए नहीं, इससे अनुच्छेद-14 का उल्लंघन हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी समन जारी होने से पहले ईडी निदेशक दुरुपयोग से बचने के लिए व्यक्तिगत रूप से मामले की समीक्षा कर सकते हैं। सीएओआरए के वकील ने 'वर्ग विशेषाधिकार' के सिद्धांत पर जोर दिया और मुवक्किल-वकील गोपनीयता के कानूनी सिद्धांत का हवाला दिया। पीठ ने निर्देश दिया कि एससीबीए और एससीएओआरए के लिखित सुझाव तीन दिनों के भीतर सालिसिटर जनरल और अटार्नी जनरल को भेजे जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया नीतीश हत्याकांड में सुखदेव यादव की रिहाई का आदेश

- सुखदेव यादव ने इस साल मार्च में 20 साल की सजा पूरी की
- सजा समीक्षा बोर्ड ने सुखदेव की याचिका खारिज कर दी थी

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को रिहा करने का आदेश दिया और कहा कि उसने इस साल मार्च में 20 साल की सजा पूरी कर ली है। सजा समीक्षा बोर्ड ने सुखदेव के आचरण का हवाला देते हुए माफी की याचिका खारिज कर दी थी।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सजा समीक्षा बोर्ड न्यायिक प्राधिकारी के आदेश को कैसे दबा सकता है? अगर यही रवैया रहा तो हर दोषी जेल में ही मरेगा। क्या यह कार्यपालिका का आचरण है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यादव को 20 साल की सजा पूरी होने के बाद रिहा किया जाना चाहिए था। दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने दलील दी कि 20 साल सजा के बाद स्वतः रिहाई नहीं हो सकती और उम्रकैद का मतलब है शेष जीवन तक जेल में रहना। हालांकि, सुखदेव यादव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ मृदुल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने नौ मार्च, 2025 को अपनी सजा पूरी कर ली है। उन्होंने यादव को नौ मार्च से आगे हिरासत में रखने के किसी भी वैध औचित्य से इन्कार किया और कहा कि दिल्ली सरकार ने सजा की गलत व्याख्या की है।

विकास की अंतरिम जमानत चार हफ्ते के लिए बढ़ाई गई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल की जेल की सजा काट रहे विकास यादव को उसकी बीमार मां की देखभाल के लिए दी गई अंतरिम ज़मानत चार हफ़्ते के लिए बढ़ा दी। कोर्ट ने विकास यादव से कहा कि वह इस मामले में सजा माफी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाएं। शीर्ष न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाई है।

अब्दुल्ला आजम से जुड़े दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट को पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े दो मामलों में ट्रायल जारी रखने का निर्देश दिया गया था।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अब्दुल्ला द्वारा दायर अपील पर उप्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। 23 जुलाई को हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। पहला मामला अब्दुल्ला के कथित फर्जी पासपोर्ट से संबंधित है और दूसरा मामला उनके द्वारा दो पैन कार्ड हासिल करने से जुड़ा है।

हाई कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह आवेदन मेरिट से रहित है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।" अब्दुल्ला ने हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।

जागरण विशेष

जो कभी था नशे का कैदी, अब युवाओं को दिला रहा नशे से मुक्ति

गुरदासपुर में पंकज के प्रयासों से 700 युवा नशे से हुए दूर, पुलिस ने बनाया अपना ब्रांड एंबेसडर

सुनील थानेवालिया • जागरण

गुरदासपुर: नशे की गिरफ्त में फंसे गुरदासपुर के पंकज महाजन को पुलिस ने कभी गिरफ्तार कर लिया था। अपनी इस लत के चलते उसने परिवार, सम्मान और अपनी सेहत सब खो दिया, लेकिन फिर पंकज संभले और आज वह नशा छोड़कर सैकड़ों युवाओं को नई जिंदगी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस ने उन्हें अपनी नशामुक्ति मुहिम 'मिशन निश्चय' का ब्रांड एंबेसडर भी बनाया है। इस मुहिम से जुड़कर पंकज अब तक 800 से ज्यादा सेमिनार कर चुके हैं और 700 से ज्यादा युवाओं को नशे की लत से मुक्ति भी दिलाई है।

गुरदासपुर की राम शरणम कालोनी निवासी 37 वर्षीय पंकज महाजन जब स्कूल में थे, तब पढ़ाई और अपने बेहतर भविष्य को लेकर निश्चिंत थे। हालांकि नशे के अंधेरे ने उनकी जिंदगी को इस कदर निगला कि एक समय पंकज ने अपनी बेटी के सोने के कंगन तक बेच दिए। पंकज बताते हैं कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने दोस्तों के साथ शराब पीनी शुरू कर दी थी। इसके बाद कई और प्रकार के नशे का भी वह सेवन करने लगे। नशाखोरी के लिए पैसे की कमी पड़ी तो अपनी स्कूटी तक बेच दी। धीरे-धीरे हालात ऐसे हो गए कि दिन की शुरुआत नशे से होती थी। नशा न मिले तो जीना मुश्किल लगता था।

यह कहते हुए पंकज की आंखें नम हो जाती हैं कि उसकी नशे की लत के कारण पत्नी छोड़कर चली गई और तलाक हो गया। इस बीच एक बार पुलिस ने उसे नशा करते हुए पकड़ लिया। जेल गया तो रिश्तेदारों ने भी किनारा कर लिया। शरीर इतना टूट चुका था कि नसें जवाब देने लगीं। उसने आत्महत्या के बारे में भी सोचा मगर किस्मत ने बचा लिया। इसके बाद पंकज के जीवन में नया मोड़ आया। वर्ष 2017 में पंकज ने तय किया कि अब कभी नशा नहीं करेगा। राह आसान नहीं थी, लेकिन उसने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का प्रण लिया। इस पर पुलिस ने उसे नशा छोड़ने के लिए सम्मानित किया। उस दिन उसने सोचा कि वह नशे की दलदल में फंसे अन्य लोगों को भी निकालेगा।

दोस्तों के साथ बनाया 'फ्रीडम फ्राम ड्रग्स' ग्रुप

खुद को संभालने के बाद पंकज ने तय किया कि अब वह दूसरों को बचाएगा। 14 जुलाई 2017 को अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पंकज ने 'फ्रीडम फ्राम ड्रग्स' ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का तरीका अनोखा था। बिना किसी दवाई के, नशे में फंसे युवाओं को साथ रखकर उन्हें नशे से दूर किया जाता है। अच्छे माहौल में रहकर वे धीरे-धीरे नशा छोड़ देते। आज इस ग्रुप की पंजाब में चार टीमें हैं। पंकज कहते हैं कि नशे के खिलाफ जंग में सबसे बड़ी ताकत खुद का हौसला है। अगर आप खुद से लड़ने का मन बना लें तो नशा छोड़ना कोई बड़ी चीज नहीं। पंकज ने अपनी बाजू पर अपनी जिंदगी की पूरी कहानी टैटू के रूप में गुदवा ली है। वह सेमिनारों में युवाओं को यह टैटू दिखाकर नशा छोड़ने की प्रेरणा देते हैं।

पंकज महाजन (बीच में टोपी पहने) नशामुक्ति के लिए टैटू बनवाने वाले युवकों के साथ • सौ. स्वयं

राज्यपाल ने की सराहना

पंकज महाजन अब पंजाब पुलिस अकादमी फिल्लौर में अधिकारियों को नशामुक्ति से जुड़े सेमिनार करने की ट्रेनिंग भी देते हैं। वर्ष 2023 में गुरदासपुर में तत्कालीन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उनके प्रयासों की सराहना की। तत्कालीन एसएसपी गुरदासपुर दयामा हरीश कुमार ओम ने भी पंकज की पीठ थपथपाई और उनके काम को सराहा।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

कर्नाटक में प्रोफेसर ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए किया मजबूर

- कलबुर्गी स्थित कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय की बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं से जुड़ा है मामला
- छात्राओं को मस्जिद की यात्रा के दौरान प्रोफेसर ने ऐसा करने के लिए किया विवश

कलबुर्गी, एएनआइ: कलबुर्गी स्थित कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूके) की बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं को मस्जिद की शैक्षणिक यात्रा के दौरान हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। एक प्रोफेसर पर ऐसा करने के लिए छात्राओं पर दबाव बनाने का आरोप है। सीयूके ने जांच का आदेश दिया है। इसके लिए समिति का गठन किया गया है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार आरआर बिरादर ने 26 जुलाई, 2025 को हैदराबाद स्थित लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम के महासचिव ए. संतोष से इस संबंध में शिकायत मिलने की पुष्टि की है।

रजिस्ट्रार आरआर बिरादर ने कहा कि 26 जुलाई, 2025 को मुझे हैदराबाद स्थित लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम के महासचिव ए. संतोष से कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर अब्दुल मजीद के खिलाफ शिकायत मिली। यदि सहायक प्रोफेसर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक में 2022 से ही शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनना ज्वलंत मुद्दा रहा है। 15 जुलाई को जम्मू-कश्मीर छात्र संघ ने मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को पत्र लिखकर बेंगलुरु के नर्सिंग कालेज में कश्मीरी छात्राओं संग धार्मिक भेदभाव में हस्तक्षेप करने की मांग की थी।

****

दैनिक जागरण

अनुशासन से ही जीवन की दशा-दिशा बदली जा सकती है

सुप्रीम कोर्ट का संदेह

बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना समझ नहीं आया कि यदि बड़े पैमाने पर लोग इस सूची से बाहर होते हैं तो हम हस्तक्षेप करेंगे। क्या उसे चुनाव आयोग के इरादों पर संदेह है? आखिर उसे यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि वह मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है और जरूरत पड़ी तो दखल देगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय ही चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं जताएगा तो फिर बात कैसे बनेगी? यह ठीक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं को यह जिम्मेदारी सौंप रहा है कि वे मतदाता सूची के मसौदे को देखें और यदि उसमें बड़ी संख्या में जीवित लोगों के नाम न पाएं तो उसे बताएं। ये याचिकाकर्ता तो छोटी-छोटी विसंगति को तूल देंगे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कोई भी खटखटा सकता है, लेकिन आखिर ऐसे लोगों को विशेष महत्व क्यों दिया जाना चाहिए, जो चाहते ही नहीं कि बिहार या अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों का सत्यापन हो और अवैध तरीके से वोटर बने लोगों के नाम हटाए जाएं? यह ठीक नहीं कि कुछ लोग हर छोटे-बड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाने में समर्थ रहते हैं। इनमें विपक्षी नेता भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट को तो खुलकर यह कहना चाहिए था कि चुनाव आयोग को समय-समय पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करते ही रहना चाहिए। इसका क्या मतलब कि बिहार में 2003 के बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है और बंगाल में भी 2002 के बाद ऐसा करने की तैयारी है। यह तो चुनाव आयोग की कमी है कि वह अपना काम समय पर नहीं कर रहा है। उसे तो लगातार यह देखना चाहिए कि देश में कहीं पर भी ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज न होने पाएं, जिनकी मृत्यु हो गई हो अथवा जो स्थायी रूप से अन्यत्र बस गए हों। ऐसे लोग तो वोटर हर्गिज नहीं होने चाहिए, जिनके बारे में यह साफ नहीं कि वे भारत के नागरिक हैं। मतदान का अधिकार केवल उसे ही मिलना चाहिए, जो भारत का नागरिक हो। अच्छा होगा कि चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करे। यह ठीक है कि नागरिकता की छानबीन करना चुनाव आयोग का काम नहीं, लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि भारत सरकार राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी का काम करे। विपक्षी पार्टियों का यह आरोप बड़ा ही बेतुका है कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग के जरिये एनआरसी का काम कर रही है। यह तो वह काम है, जो हर हाल में होना चाहिए। कायदे से होना तो यह चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जरूरत रेखांकित करता कि केंद्र सरकार एनआरसी की दिशा में अवश्य आगे बढ़े। भारत ऐसी धर्मशाला नहीं हो सकता, जिसमें धर्मशाला संचालक यानी सरकार की ही न चल पाए।

अच्छी पहल

बिहार पुलिस अगले महीने सिटीजन सर्विस पोर्टल लांच करने जा रही है। इससे कई सुविधाएं आनलाइन मिलने लगेंगी, लोगों की सहूलियत बढ़ेगी। आनलाइन प्राथमिकी की कापी निकालनी हो या गोपनीय तरीके से किसी अपराधी की शिकायत करनी हो, इस पोर्टल पर सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। सबसे बड़ी बात, किरायेदार और घरेलू सेवकों का सत्यापन भी इस पोर्टल पर बिना थाने गए कराया जा सकता है। यह बहुत जरूरी है और वक्त की मांग भी। खासकर, वरिष्ठ नागरिकों को इससे काफी सहूलियत होगी जो एक ही काम के लिए थाने तक दौड़ते रहने की कुव्यवस्था से तंग आ चुके हैं। नतीजा, सत्यापन के काम में लापरवाही होती है और इससे अपराध की बड़ी घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। अपराधियों की गोपनीय जानकारी देने की पहल पर संज्ञान लिया गया तो यह क्राइम कंट्रोल में काफी सहायक साबित हो सकता है। यद्यपि, पुलिस को यह ध्यान देना होगा कि वह ऐसे मामलों का संज्ञान लेकर अपराधियों को दबोचे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी हाल में सूचना देने वाले की पहचान उजागर नहीं हो। अभी तो लाख प्रयासों के बावजूद लोगों के मन में पुलिस के प्रति आशंका रहती है। आशंका यही कि कहीं पुलिस उन्हें ही न फंसा दे। सख्त कार्रवाई और तय समय में इस पोर्टल पर समाधान मिला तो निश्चित तौर पर आमजन का भरोसा बढ़ेगा। न सिर्फ क्राइम कंट्रोल होगा, बल्कि पुलिस की स्मार्ट छवि भी निखर कर सामने आएगी। बदलते समय में जब तमाम सेवाएं आधुनिक एवं स्मार्ट हो रही हैं, तब पुलिस की यह पहल सराहनीय ही कही जाएगी। आवश्यकता है कि इस योजना का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जाए, ताकि इसके उद्देश्यों की पूर्ति में सफलता प्राप्त हो सके।

सिटीजन सर्विस पोर्टल आम लोगों के लिए काफी सहायक साबित हो सकता है

युवाओं की प्रतीक्षा करती राजनीति

राहुल वर्मा

राजनीतिक दलों और उम्रदराज नेताओं के बीच स्व-नियमन की कोई राह तलाशी जाए, जिसमें वरिष्ठ नेताओं के अनुभव के साथ ही युवाओं की ऊर्जा एवं नए सोच को भी राजनीति में सही जगह मिले

अवधेश राजपूत

राजनीति को भले ही कोई 'पेशा' नहीं समझा जाता हो, लेकिन अन्य पेशेवरों की तरह इसमें भी रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति का सवाल रह-रहकर सतह पर आता रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बीते दिनों इस संबंध में एक बयान भी चर्चा में रहा था। भारत युवाओं की बड़ी आबादी वाला देश है। इस कारण स्वाभाविक रूप से राजनीति में भी युवाओं का व्यापक प्रतिनिधित्व अपेक्षित है। हालांकि कई पहलुओं के चलते यह संभव नहीं हो पा रहा है। वैसे, राजनीति में युवाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव केवल भारत में ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों में यही रुझान नजर आता है। एक अध्ययन के अनुसार प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में 10 प्रतिशत से कम ही नेता 35 साल से कम आयु के हैं। भारत में भी यही परिपाटी जारी है। 1952 से 2024 के बीच गठित हुई लोकसभा पर दृष्टि डालें तो उसकी औसत आयु लगातार बढ़ती जा रही है। इस क्रम में मौजूदा लोकसभा की औसत आयु सर्वाधिक है। यह दर्शाता है कि राजनीतिक व्यवस्था में युवाओं का समायोजन उचित अनुपात में नहीं हो पा रहा है। इसके कारणों की पड़ताल में सबसे बड़ा पहलू यही सामने आता है कि राजनीति में प्रवेश ही अक्सर अधिक आयु में मिलता है। डाक्टर, इंजीनियर या अन्य सेवाओं में जहां व्यक्ति कम आयु में ही अपना कार्य शुरू कर देता है, वहीं राजनीति में यह सफर अपेक्षाकृत देर से शुरू होता है। अक्सर 40 से 45 की आयु में व्यक्ति राजनीतिक जीवन की पहली सीढ़ी चढ़ता है। 45 से 50 की आयु में वह पार्षद, विधायक या सांसद बनता है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पद तक पहुंचने में 60-65 साल की आयु हो जाना बहुत सामान्य बात है। यही कारण है कि राजनीति में 'उम्रदराज' लोगों को भी 'युवा तुर्क' की उपमा दी जाती है। एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो किसी अन्य पेशे में होते हैं और उसके साथ ही राजनीति में संलग्न रहते हैं।

यह सही है कि संविधान ने 25 वर्ष से अधिक आयु वाले किसी भी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि चुने जाने की अर्हता निर्धारित की हुई है, पर वास्तविकता में यह संकल्पना व्यापक रूप से साकार नहीं हो सकी है। कुछ युवा नेता विधानसभा, लोकसभा और मंत्री पदों तक पहुंचे हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश या कहें कि 90 प्रतिशत ऐसे हैं जो किसी राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। ये अपनी पारिवारिक विरासत की पूंजी से ही स्वयं को स्थापित कर पाए हैं। देश में 35 साल से कम आयु के 90 प्रतिशत सांसद इसी श्रेणी में आते हैं। चुनाव लड़ने में भी युवा नेताओं की भागीदारी बेहद सीमित है। उदाहरणस्वरूप 2024 के लोकसभा चुनाव में 8,000 से अधिक प्रत्याशियों में 30 साल से कम आयु के गंभीर उम्मीदवार सौ भी नहीं थे। पार्टी संगठन में भी युवाओं को उचित समय पर जगह नहीं मिल पाती। देश की सभी मुख्य पार्टियों की युवा इकाइयों के प्रमुखों पर दृष्टि डालें तो लगभग सभी की उम्र 40 के आसपास है। प्रतिनिधित्व से इतर प्रदर्शन की बात करें तो इसे लेकर भी बहस हो सकती है कि इसमें उम्रदराज अनुभवी नेता बेहतर होते हैं या युवा नेता। इस संदर्भ में अध्ययन कुछ रुझानों को दर्शाते हैं।

युवा नेताओं की कार्यशैली में नए सोच की झलक मिलती है। वे दीर्घकालिक एजेंडे पर काम करते हैं। जोखिम लेने से भी संकोच नहीं करते। कई बार इसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी निकलते हैं। इसके उलट उम्रदराज नेता अपने अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। किसी आपदा या संकट के समय उनका अनुभव बहुत काम आता है। किसी तनाव या टकराव की स्थिति में भी वे कहीं अधिक संयम से काम लेते हैं। बजट प्राथमिकताओं की बात की जाए तो जहां युवा नेता इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं वरिष्ठ नेता कल्याणकारी योजनाओं को वरीयता देते हैं। संसदीय उपस्थिति और सक्रियता को देखें तो इसमें युवा नेता पिछड़ जाते हैं। कार्यवाही में उनकी भागीदारी और उपस्थिति दोनों ही वरिष्ठ नेताओं से कम है। यह सही है कि कार्यवाही के मामले में राजनीतिक दल अनुभव को प्राथमिकता देते हुए वरिष्ठ नेताओं को आगे करते हैं, पर युवा सांसदों को संसद में उपस्थिति होने से भला कौन रोक रहा है? संसद में 60 वर्ष से अधिक आयु के सांसदों की उपस्थिति जहां 80 प्रतिशत के आसपास है, वहीं 40 साल से कम आयु वाले सांसदों की 75 प्रतिशत से थोड़ी कम।

राजनीतिक नेतृत्व के मामले में उम्र से अधिक यह मायने रखना चाहिए कि कोई नेता महत्वपूर्ण दायित्व संभालने के लिहाज से उपयुक्त है या नहीं। चूंकि ऐसे लोगों को अहम फैसले लेने होते हैं, इसलिए उनका शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अमेरिका में जो बाइडन को दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी इसी कारण वापस लेनी पड़ी कि उनकी सेहत को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे थे। यही कारण है कि कुछ लोग यह सुझाव देते हैं कि जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया जाना चाहिए। इसके भी अपने जोखिम और सीमाएं हैं। एक तो नेता के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी का असर राजनीतिक स्थिरता से लेकर आर्थिकी पर देखने को मिल सकता है। दूसरा, इसमें निजता का भी एक पेच है, क्योंकि किसी बीमारी की स्थिति में व्यक्तिगत गरिमा का भी ध्यान रखना पड़ता है। युवाओं को बेहतर प्रतिनिधित्व देने और राजनीति को समावेशी बनाने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जैसे पदों पर अधिकतम बार चुने जाने की संख्या को नियत करने पर विचार हो सकता है। हालांकि यह भी जनता के समक्ष विकल्पों को सीमित करने वाला होगा और यह कोई व्यापक समाधान भी नहीं करेगा। बेहतर यही होगा कि इस मोर्चे पर राजनीतिक दलों के भीतर और उम्रदराज नेताओं के बीच स्व-नियमन की कोई सर्वसम्मत राह तलाशी जाए, जिसमें पुराने नेताओं के अनुभव का लाभ मिलने के साथ ही युवाओं की ऊर्जा एवं नए सोच को भी राजनीति में सही जगह मिले।

(लेखक सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

एडीएम को अंग्रेजी बोलना जरूरी क्यों है

राजीव सचान

यह उत्तराखंड ही नहीं, देश का दुर्भाग्य है कि किसी अधिकारी का अंग्रेजी न बोल पाना उसकी अक्षमता समझी गई

चर्चा में अंग्रेजी पर नैनीताल हाई कोर्ट की टिप्पणी। फाइल

उत्तराखंड में दूसरे राज्यों के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य हाई कोर्ट ने पाया कि उसके समक्ष पेश नैनीताल के एडीएम प्रशासन विवेक राय ने माना कि वे अंग्रेजी समझ तो लेते हैं, लेकिन बोलने में दिक्कत होती है। नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और आलोक माहरा की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त को यह जांचने का निर्देश दिया कि क्या अंग्रेजी न बोल पाने वाले अपर जिला मजिस्ट्रेट स्तर के किसी अधिकारी को कार्यकारी पद का प्रभावी नियंत्रण सौंपा जा सकता है? पता नहीं मुख्य सचिव क्या करेंगे। क्या वे एडीएम की अंग्रेजी बोलने की दक्षता परखेंगे या हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार उन्हें ऐसे किसी पद पर नियुक्त करेंगे, जहां अंग्रेजी बोलने की जरूरत न हो। चूंकि उत्तराखंड हिंदीभाषी राज्य है, इसलिए विवेक राय के लिए उपयुक्त पद की कमी न होगी, लेकिन यदि उन्हें अन्यत्र भेजा जाता है तो उनके मान-सम्मान को धक्का लग सकता है। लोग ऐसा कह सकते है कि ये वही अधिकारी हैं, जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते। तमाम ऐसा भी कहेंगे कि आखिर उत्तराखंड विदेश में तो है नहीं। आखिर यहां अंग्रेजी बोलने की जरूरत क्यों है? अंग्रेजी समझ आ जाए तो ठीक है। सच तो यह है कि कुछ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, न्यायविद् और भाषाविद् समेत अन्य यह सवाल उठा रहे हैं कि भारत और खासकर हिंदी भाषी राज्य में अंग्रेजी बोलना जरूरी है या अपना काम सही तरीके से करना? कुछ लोग राज्य सरकार को सलाह दे रहे हैं कि उसे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करनी चाहिए।

उत्तराखंड सरकार जो भी करे, ऐसा कहने वाले लोग अवश्य होंगे कि प्रशासनिक अधिकारी को अंग्रेजी बोलना तो आना ही चाहिए। यह बहस आगे चलती रहेगी, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विवेक राय किसी हिंदी भाषी राज्य के होंगे और उन्होंने राज्य की प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास होगी। आम धारणा है कि यह परीक्षा पास करने वाले मेधावी होते हैं। वैसे यह जरूरी नहीं कि राज्यों की प्रशासनिक सेवा संबंधी परीक्षा या फिर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले सभी लोग प्रशासनिक रूप से दक्ष ही होते हैं। जब तक इन परीक्षाओं की पात्रता के मानदंड नहीं बदलते, तब तक हमें इन्हें पास करने वालों को काबिल ही मानना होगा। विवेक राय हाई कोर्ट के समक्ष यह कह सकते थे या उनकी ओर से मुख्य सचिव अब भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा तो अंग्रेजी में देने की अनिवार्यता ही नहीं। हैरानी नहीं कि कोई यह कहने लगे कि अब उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंग्रेजी ज्ञान को अच्छे से परखा जाए। ऐसी कोई मांग होती है तब उसका विरोध भी होगा, क्योंकि उत्तराखंड की तो भाषा हिंदी ही है और यहां तैनात अधिकारियों के लिए इतना बहुत है कि उन्हें अंग्रेजी समझ आ जाए और वे कामचलाऊ अंग्रेजी बोल लें।

चूंकि अपने देश में अंग्रेजी जानना नहीं, उसे बोलना योग्यता और श्रेष्ठता का परिचायक है इसलिए उसका हौवा है-आतंक है। अपने देश में अंग्रेजी को ज्ञान, बुद्धिमत्ता और काबिलियत की भाषा माना जाता है। इसके बावजूद माना जाता है कि जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन आदि ने बिना अंग्रेजी के अद्भुत प्रगति की। कई देश ऐसे हैं, जहां अंग्रेजी जानने-बोलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां लोग यह कथित अंतरराष्ट्रीय भाषा न बोलते हैं और न समझते हैं। यह सच है कि अंग्रेजी की अपनी महत्ता है। कोई अंग्रेजी जाने और बोल भी ले तो अच्छी बात है। आम तौर पर कूटनीति, व्यापार और तकनीक की भाषा मुख्यतः अंग्रेजी है, लेकिन एआइ के जमाने में अंग्रेजी जानना-बोलना जरूरी नहीं रह गया है, क्योंकि अब तुरंत अच्छा अनुवाद हो जाता है। शायद अपने देश में इस बात को अब भी नहीं समझा जाएगा, क्योंकि यहां धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलना ही पर्याप्त नहीं। उसका लहजा भी ब्रिटिश या अमेरिकी होना चाहिए। यदि किसी का लहजा वैसा नहीं होता, जैसा कथित तौर पर होना चाहिए तो उसका मजाक उड़ता है, भले ही वह कितने ही उच्च पद पर हो या फिर कितना ही काबिल हो। ऐसा मुख्यतः केवल भारतीयों के साथ है, चीनी, जापानी या अफ्रीकी लोगों के साथ नहीं। चूंकि कई देशों की भाषाओं में त, था, ध जैसे शब्द ही नहीं, इसलिए उनका लहजा अलग होता है। पश्चिम में तो यह अलग लहजा सामान्य समझा जाता है, पर भारत में असामान्य। इंडिया दैट इज भारत में अंग्रेजी बिन सब सून। अपने देश में लोग ठसक के साथ कहते हैं कि हिंदी या फिर उनकी अपनी मातृभाषा में उनका हाथ तंग है। वे हिंदी या फिर अन्य भारतीय भाषा बोले बिना उच्च पदों पर सुशोभित होते हैं। उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होती।

यह थोथी बात है कि हिंदी अंग्रेजी के समकक्ष राजभाषा है। सच यह है कि उच्चतर अदालतों में अंग्रेजी का बोलबाला है। कहीं अनुवाद में गड़बड़ हो तो मूल अंग्रेजी ही मान्य होगा। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों के नेता हिंदी थोपने की फर्जी बात करके अपने राज्य की भाषा की अनदेखी करने के साथ अंग्रेजी के वर्चस्व को बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

ज्ञान की शक्ति

ज्ञान हमारे विवेक की कुंजी है। ज्ञान की शक्ति से हम अच्छे और बुरे का निर्धारण कर सकते हैं। अच्छाई के प्रति झुकाव और बुराई से अलगाव इसी ज्ञान के कारण संभव हो सकता है। ज्ञानवान व्यक्ति विनम्र और निष्कपट होता है। वह छल-छद्म और दंभ से दूर रहता है। ईमानदारी उसका सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है। ज्ञान का लालित्य उसे प्रज्ञावान बनाता है। उसकी बुद्धि प्रभावी एवं तीक्ष्ण होती है। ज्ञानवान व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र की उन्नति के आधार बनते हैं। उनका व्यक्तित्व प्रखर एवं सर्वजन हिताय के सोच से आप्लावित रहता है। ज्ञानवान बनना केवल पोथी पढ़ने से संभव नहीं है, अपितु इसके लिए मानस की पवित्रता, वाणी की शुद्धता एवं बुद्धि की निर्मलता होना अत्यंत आवश्यक है। पुस्तकें पढ़कर, तमाम प्रसंग रटकर और सिद्धांत बांचकर आप साक्षर अथवा स्वयं को पढ़ा-लिखा घोषित कर सकते हैं, परंतु आप ज्ञानवान तभी कहला सकते हैं जब आप अध्ययन के बाद मनन और उसके वास्तविक प्रवर्तन में सक्षम हो सकें। नीति और अनीति का भेद करना आप जान सकें। सकारात्मकता एवं नकारात्मकता में निहित भावों को महसूस कर सकें।

रावण को शास्त्रों की गहन जानकारी थी, परंतु अहंकार के चलते वह ज्ञान निरर्थक होकर रह गया। रावण का बुद्धि कौशल उसे धर्म और अधर्म में भेद करना नहीं सिखा पाया। वह संपूर्ण जीवन अनीति का आश्रय लिए रहा। वह ज्ञान के उजास को कभी अनुभव ही नहीं कर पाया। उसने ज्ञान के तेज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिससे वह अज्ञानता के दलदल में दबा रहा। इसलिए यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम विवेकपूर्ण तरीके से अपनी शिक्षा की सामर्थ्य को पहचानें। उसे अंगीकार करें। नकारात्मकता से दूर रहकर सुनीति का सामीप्य प्राप्त करें। धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। तभी हम ज्ञानवान कहला सकेंगे।

ललित शौर्य

धूल भरी आंधियों से सुरक्षा जरूरी

सुधीर कुमार

धूल भरी आंधियों में शामिल रेत और धूल के कण हर साल लगभग 70 लाख लोगों की अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं

विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा हाल ही में जारी वार्षिक 'एयरबोर्न डस्ट बुलेटिन' के अनुसार, हर साल दुनिया भर के 150 देशों की 33 करोड़ से अधिक आबादी रेत और धूल के तूफानों का सामना करती है। धूल भरी आंधी केवल एक सामान्य मौसमी परिघटना नहीं है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य, परिवहन सेवाओं और कृषि सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला कारक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, धूल भरी आंधियों में शामिल रेत और धूल के कण हर साल लगभग 70 लाख लोगों की अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। रेत और धूल के ये कण न केवल मानव स्वास्थ्य और जीवन पर असर डालते हैं, बल्कि खेतों में खड़ी फसलों के लिए भी खतरा बनते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का अनुमान है कि जिन क्षेत्रों में धूल भरे तूफानों की आवृत्ति अधिक है, वहां फसलों की पैदावार में 25 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। विशेषकर शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में मौसम में बदलाव के दौरान धूल भरी आंधियों का उठना एक सामान्य भौगोलिक घटना है। देश के रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह लगभग हर दिन की एक सामान्य घटना है। वहीं, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में धूल भरी आंधियों का चलना भी सामान्य सी बात है।

जब ये तूफान उठते हैं, तो वे मिट्टी से रेत और धूल को वायुमंडल में फैला देते हैं। इस दौरान धूलकण सैकड़ों किलोमीटर दूर तक की यात्रा करते हैं, जिससे दृश्यता कम हो जाती है और आवागमन प्रभावित होता है। प्रभावित आबादी को इस दौरान श्वसन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खुले आसमान के नीचे काम करने वाले श्रमिकों को इससे कार्य करने में कठिनाई होती है। इस प्रकार, धूल भरी आंधियां अर्थतंत्र को भी बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि धूल से होने वाली वैश्विक कल्याण हानि 1990 में 2.2 खरब डालर से बढ़कर 2013 में लगभग 3.6 खरब डालर हो गई।

मरुस्थलीकरण, अतिचारण, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, वनोन्मूलन और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण वनस्पति आवरण में गिरावट आती है, जिससे मिट्टी की पकड़ कमजोर पड़ जाती है और इसके कण तेज हवाओं में आसानी से उड़ने लगते हैं। हालांकि धूल भरी आंधी एक प्राकृतिक परिघटना है, लेकिन मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाकर उड़ने वाली रेत और धूल की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए वनीकरण को बढ़ावा, मृदा अपरदन पर रोक और पशुचारण पर नियंत्रण जैसे उपाय करने होंगे। आंधी-तूफान को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित कर इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

आतंकवाद पर दोहरे मानदंड

'गाजा संकट पर मूकदर्शक मोदी सरकार' शीर्षक से लिखे आलेख में सोनिया गांधी ने गाजा में सक्रिय आतंकी संगठन हमास की निर्दयता और क्रूरता को अनदेखा कर जिस कड़े अंदाज में मोदी सरकार को लपेटते हुए इजरायली प्रतिकार की निंदा की है, वह उनके दोहरे मानदंडों को ही दर्शाती है। चारों ओर से ताकतवर दुश्मन इस्लामिक देशों से घिरा हुआ छोटा सा यहूदी देश इजरायल यदि अपने साहस और शौर्य से इन इस्लामिक देशों के छद्म युद्ध का मुकाबला कर पा रहा है तो केवल इसलिए कि वह हमलावर दुश्मन पर सख्ती में संकोच नहीं करता। इजरायल के एक हजार से अधिक निर्दोष नागरिकों की अकारण निर्मम हत्या के बाद सैकड़ों नागरिकों को बंधक बनाकर गाजा ले जाने वाले आतंकी संगठन हमास को इस तरह का अमानवीय कृत्य करने से पूर्व इजरायल के घातक प्रतिशोध की बात भी ध्यान में रखनी चाहिए थी। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमास की क्रूरता का दंड निर्दोष फलस्तीनी नागरिकों को भी भुगतना पड़ रहा है। इजरायल में भारत जैसी सहनशीलता नहीं है, जो दशकों से पाकिस्तान द्वारा पोषित जिहादी आतंकवाद के घातक दंश को बर्दाश्त कर रहा है। हालंकि अब आतंकवाद को लेकर भारत की नीति और नियम भी बदले हैं, वह गोली का जवाब गोले से दे रहा है। भारत के 'आपरेशन सिंदूर' ने यह साबित भी कर दिखाया। इस बीच यह भी अफसोस की बात है कि पराक्रम से भरे इस अभियान के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान ऐसे रहे जो पाकिस्तान को ज्यादा रास आए। यह स्पष्ट है कि आतंकवाद के संदर्भ में अब भारत और इजरायल की नीति एक जैसी है, फर्क बस इतना है कि शांतिप्रिय भारत प्रतिकार स्वरूप केवल लक्ष्य को भेदने वाली संक्षिप्त सैन्य कार्रवाई करता है, जबकि इजरायल आर-पार की लड़ाई में सक्रिय रहता है। ऐसे में, यह मानकर मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा करना उचित नहीं है कि शांति और मानवता का पक्षधर भारत फलस्तीनी नागरिकों की रक्षा के लिए इजरायल पर दबाव नहीं बना रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों से प्रधानमंत्री मोदी ने युद्धरत देशों के राष्ट्राध्यक्षों से युद्ध को छोड़कर बुद्ध के शांति मार्ग को अपनाने की बात कही है।

डा. बीपी पाण्डेय, अलीगढ़ (उ.प्र.)

कुत्तों के आक्रामक होने का कारण

विजय गोयल का आलेख 'आवारा कुत्तों के आतंक से बेबस जनता' एक स्वाभाविक चिंता को उजागर करता है। इसमें देश के नगर निगमों के पास कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना का जिक्र भी किया गया तो साथ ही केरल में तो सरकार इन आवारा कुत्तो को यूथेनेशिया (जहर) देकर इनकी जीवन लीला समाप्त करने की तैयारी कर रही है। लेकिन इसका समाधान केवल नसबंदी या इनकी जीवन लीला समाप्त करना नहीं है। इस धरती पर सभी जीवों को स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी प्राणी या विशेष रूप कुत्तों को पकड़ना या उनकी संख्या कम करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इससे इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है। पर्यावरण खतरे में पड़ जाएगा। यह बात हमारे मन-मस्तिष्क में होनी चाहिए कि कोई भी प्राणी बिना कारण मानव पर आक्रमण नहीं करता। प्राणी व्यवहार विज्ञानियों ने इसके पीछे सामाजिक और वैज्ञानिक कारण बताए हैं। जैसे, शहरीकरण के कारण प्राणियों को रहने की जगह नहीं मिलती, जिससे वे सड़कों पर आ जाते हैं। कुत्ते, विशेषकर झुंड में रहने वाले, अपने परिवार की सुरक्षा करते हैं। यदि उन्हें अपने झुंड के सदस्यों को खतरा महसूस होता है, तो वे आक्रामक हो सकते हैं और यदि वे बीमार होते हैं तो आक्रामक होकर अपने दांतों का उपयोग कर काटते हैं। अंततः इन अबोध प्राणियों के प्रति और विशेष रूप से कुत्तों के प्रति सहानुभूति और सुरक्षा का कार्य करना आवश्यक है। इससे ये निर्दोष प्राणी मानव के आक्रोश का कारण नहीं बनेंगे। हमें उनके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। बेहतर यही होगा कि हम कोई मध्यमार्ग अपनाकर बेसहारा कुत्तों का भी सहारा बन सकें और उनके कारण किसी मानव को कोई क्षति न पहुंचे, यह भी सुनिश्चित करें।

anghvipk1955@rediffmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

56 अरब डालर है वर्तमान में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार का आकार। मुक्त व्यापार समझौता इसे बढ़ाकर 2030 तक दोगुना कर सकता है।

आजकल

गंभीर चुनौती बनता भीड़ प्रबंधन

डा. मोनिका राज
शोधार्थी

भारत को अपनी भीड़ प्रबंधन व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचाना होगा, तभी धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके लिए स्वतंत्र रणनीति या नीतिगत ढांचा विकसित किया जाए। भीड़ प्रबंधन को केवल पुलिस व्यवस्था तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे एक विशिष्ट आपदा जोखिम प्रबंधन के रूप में देखा जाए। तकनीक के उपयोग एवं नीतिगत मजबूती से ही भविष्य में भगदड़ जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है

चिंतित करती बार-बार होने वाली भगदड़ की घटनाएं। फाइल

भारत, जहां धर्म और आध्यात्मिकता जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, वहां हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु मंदिरों, मेलों और धार्मिक आयोजनों में एकत्रित होते हैं। यह भीड़ आस्था और भक्ति का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है, लेकिन कई बार यही आस्था अनियंत्रित होकर त्रासदी में बदल जाती है। हाल में हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ ने एक बार फिर हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों बार-बार ऐसी घटनाएं होती हैं और क्यों हमारा प्रशासन और समाज इससे सबक नहीं ले पाता। इससे पहले भी देश के अलग-अलग हिस्सों में इसी तरह की त्रासदियां घट चुकी हैं।

बार-बार क्यों हो रही हैं भगदड़ की घटनाएं: धार्मिक स्थलों पर भीड़ का अनुमान और उसका नियंत्रण अक्सर बेहद कमजोर साबित होता है। बावजूद इसके सुरक्षित रास्तों, अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वारों तथा मेडिकल इमरजेंसी की ठोस योजना का अभाव साफ दिखाई देता है। भीड़ के इस असंतुलन को और भयावह बना देती हैं अफवाहें, जो अक्सर भगदड़ का मुख्य कारण बनती हैं। हर ऐसी त्रासदी के बाद जांच बैठती है, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बातें होती हैं, लेकिन नतीजा लगभग हमेशा नगण्य रहता है। सख्त सजा और स्थायी सुधारात्मक उपायों के अभाव में वही गलतियां बार-बार दोहराई जाती हैं। स्थिति को और जटिल बना देती है हमारे धार्मिक स्थलों की अव्यवस्थित संरचना। अधिकांश मंदिर और तीर्थ स्थल दशकों या सदियों पुराने हैं, जिनकी वास्तुकला आधुनिक भीड़ को संभालने में सक्षम नहीं है। संकरी सीढ़ियां, बंद गलियारे और एकतरफा मार्ग की कमी ऐसे हादसों को जन्म देती है।

प्रशासनिक लापरवाही या प्रणालीगत विफलता: हर बार जब किसी धार्मिक या सार्वजनिक आयोजन में भगदड़ होती है, तो प्रशासनिक प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी होती है-हादसे के बाद जांच समिति का गठन, कुछ अधिकारियों का निलंबन और पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा, लेकिन इन औपचारिक कार्रवाइयों के बावजूद दीर्घकालिक सुधार नजर नहीं आते। इसका एक प्रमुख कारण है आयोजनों में आने वाली भीड़ का वैज्ञानिक आकलन न होना। अक्सर आयोजकों और प्रशासन को यह अंदाजा ही नहीं होता कि कितने लोग आयोजन स्थल पर पहुंच सकते हैं, जिससे क्षमता से कहीं अधिक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। दूसरी बड़ी समस्या है प्रवेश और निकासी मार्गों की कमी। अधिकतर धार्मिक स्थल संकरी गलियों या सीमित स्थानों में बने होते हैं, जहां पर्याप्त आपातकालीन निकास की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में जैसे ही भीड़ में अफरा-तफरी मचती है, लोगों के पास सुरक्षित निकलने का कोई विकल्प नहीं रहता। इसके अलावा पुलिस, स्थानीय प्रशासन और आयोजन समितियों के बीच समन्वय की गंभीर कमी भी हादसों को बढ़ावा देती है। अक्सर यह देखने को मिलता है कि अलग-अलग एजेंसियां बिना आपसी तालमेल के काम करती हैं, जिससे आपातकालीन स्थिति में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई संभव नहीं हो पाती। सुरक्षा बलों और स्वयंसेवकों को भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। न तो उनके पास आधुनिक संसाधन होते हैं और न ही संकट से निपटने की स्पष्ट रणनीति।

भीड़ नियंत्रण में आधुनिक उपकरणों की भूमिका: आज के डिजिटल युग में जब एआइ, सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन सर्विलांस और डाटा एनालिटिक्स का प्रयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है, तब भी भारत के धार्मिक आयोजनों में इन आधुनिक तकनीकों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन का उपयोग कर लाइव निगरानी से भीड़ के घनत्व को तुरंत पहचाना जा सकता है और आवश्यकतानुसार अलर्ट जारी कर दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। एआइ आधारित सिमुलेशन के माध्यम से आयोजन से पहले ही भीड़ के मूवमेंट का आभासी अध्ययन कर कमजोर बिंदुओं की पहचान की जा सकती है। डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके पिछले आयोजनों के आंकड़ों का विश्लेषण कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी विशेष अवसर पर कितने लोगों के आने की संभावना है और किस समय में भीड़ का दबाव सबसे अधिक होगा। डिजिटल टिकटिंग प्रणाली अपनाकर सीमित संख्या में ही प्रवेश पास जारी किए जा सकते हैं, जिससे क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ न जुटे।

आपदा प्रबंधन बनाम भीड़ प्रबंधन: भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू है, किंतु यह मुख्य रूप से भूकंप, बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बनाया गया था। भीड़ प्रबंधन को इस अधिनियम का हिस्सा तो माना गया है, लेकिन इसके लिए कोई स्वतंत्र रणनीति या नीतिगत ढांचा विकसित नहीं किया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि भीड़ प्रबंधन को केवल पुलिस व्यवस्था तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे एक विशिष्ट आपदा जोखिम प्रबंधन के रूप में देखा जाए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जानी चाहिए, जो धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक स्थलों के लिए समान दिशा-निर्देश प्रदान करे और जिसका पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए। आपदा प्रतिक्रिया बल जैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में भीड़ नियंत्रण विशेषज्ञों की नियुक्ति कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे आपात स्थितियों में प्रभावी ढंग से काम कर सकें। साथ ही हर बड़े धार्मिक स्थल पर स्थायी क्राउड कंट्रोल यूनिट या भीड़ प्रबंधन सेल का गठन किया जाना चाहिए, जो आयोजन से पहले और दौरान भीड़ की निगरानी, प्रवेश-निकास का प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित कर सके। इस प्रकार की नीतिगत मजबूती से ही भविष्य में भगदड़ जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

नीतिगत सुधार और जवाबदेही: सिर्फ तकनीक और मानक संचालन प्रक्रिया अपनाने से ही भगदड़ की समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक कि सरकारी एजेंसियों में स्पष्ट जवाबदेही तय न हो। अक्सर देखा जाता है कि किसी हादसे के बाद जांच समिति गठित की जाती है, रिपोर्ट तैयार होती है, लेकिन वह फाइलों में दबकर रह जाती है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। जरूरत इस बात की है कि हादसे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जा सके। इसके साथ ही जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए, भीड़ का अनुमान लगाने से लेकर मार्ग सुरक्षा और अफवाहों के नियंत्रण तक किस अधिकारी या एजेंसी की ड्यूटी होगी, यह पहले से तय होना चाहिए। अदालतों और मानवाधिकार संस्थाओं की सक्रिय निगरानी भी जरूरी है, ताकि पीड़ितों को समय पर मुआवजा और न्याय मिल सके। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देश इस दिशा में सफल माडल पेश कर चुके हैं। जापान में त्योहारों के दौरान डिजिटल एंट्री सिस्टम और आपातकालीन निकास संकेतकों का अनिवार्य रूप से उपयोग होता है, जिससे भीड़ को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। सऊदी अरब ने हज प्रबंधन में एआइ और स्मार्ट ट्रैकिंग ब्रेसलेट्स का प्रयोग कर तीर्थयात्रियों को चरणबद्ध तरीके से मार्गदर्शन प्रदान किया है, जिससे वहां की भीड़ नियंत्रण प्रणाली अत्यधिक प्रभावी हो गई है। सिंगापुर में किसी भी बड़े आयोजन से पहले जोखिम आकलन रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य है, जो संभावित खतरों की पूर्व पहचान कर सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाती है। भारत को इन देशों से सीख लेकर अपनी भीड़ प्रबंधन व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचाना होगा, तभी धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

धार्मिक आयोजनों को सुरक्षित बनाना आवश्यक

भारत जैसे आस्था प्रधान देश में धार्मिक आयोजनों को सुरक्षित बनाना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार को एक सुदृढ़ भीड़ प्रबंधन नीति बनानी चाहिए, जो न केवल नियम और दिशा-निर्देश तय करे, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की भी गारंटी दे। धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में पारंपरिक समितियों के साथ-साथ पेशेवर इवेंट मैनेजर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन योजनाओं और सुरक्षा प्रोटोकाल को बेहतर तरीके से लागू कर सकें। तकनीक का अधिकतम उपयोग भीड़ प्रबंधन में अहम भूमिका निभा सकता है। सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन मानिटरिंग, डिजिटल टिकटिंग और एआइ आधारित सिमुलेशन जैसे उपायों को नियमित रूप से अपनाया जाना चाहिए। साथ ही आपातकालीन मेडिकल सेवाओं की उपलब्धता हर आयोजन में सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि किसी अप्रत्याशित स्थिति में तुरंत उपचार मिल सके। इसके अलावा जन-जागरूकता अभियान चलाकर लोगों में अनुशासन का पालन करने और अफवाहों से बचने की आदत विकसित करनी होगी। जब तक प्रशासनिक नीतियों और जनता की सहभागिता में संतुलन नहीं बनेगा, भीड़ प्रबंधन की चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं हो पाएंगी।

हर भगदड़ के बाद जब मृतकों की चीखें और परिजनों का मातम समाचारों में आता है, तब कुछ दिनों तक चर्चा होती है, लेकिन जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाता है। यह चक्र तभी टूटेगा जब आस्था और व्यवस्था के बीच संतुलन बनेगा, तकनीक और नीति का सही उपयोग होगा और जवाबदेही तय होगी। आस्था की रक्षा केवल पूजा-पाठ से नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की जान की सुरक्षा से भी होती है। यदि हमने अब भी पिछली त्रासदियों से सबक नहीं लिया, तो आने वाले समय में भीड़ का दबाव और बढ़ेगा और भगदड़ की त्रासदी बार-बार दोहराई जाएगी।

-डा. मोनिका राज

खरी-खरी

'जिम्मेदार' की तलाश

डा. प्रदीप मिश्र

स्कूल की छत के गिरते ही, 'जिम्मेदार' की खोज शुरू हो गई। बड़ी घटनाओं में 'जिम्मेदार' कभी नहीं मिलते, पर छोटी घटनाओं में तत्काल मिल जाते हैं। यह घटना छोटी ही है। गरीबों के बच्चों की जान जाना छोटी घटना ही कहलाता है। जो बच्चे गए, वे बड़े आदमी के तो नहीं ही थे? घटनास्थल पर पहुंचे अफसरों ने बताया कि 'इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार, न तो वह ठेकेदार है, जिसने भवन बनाया। न वे अफसर हैं, जिन्होंने ठेकेदार के काम को सराहा। न वे जननायक हैं, जिन्होंने भवन का उद्घाटन किया!'

घटना हुई है तो किसी को तो जिम्मेदार बनाओ? वो शिक्षक है न। वही जिम्मेदार है। उसने शासन को नहीं बताया कि अमुक दिन और अमुक समय छत गिरेगी? वह शिक्षक दुर्घटना के समय कक्षा में मौजूद भी नहीं रहा, जबकि नियमतः उसे कमरे में मौजूद रहकर छत को गिरने से रोकना था। वैसे अगर शिक्षक कह देता कि 'छत गिरने वाली है' तो सब यही कहते कि 'क्लास नहीं लेने का नया बहाना तलाशा है मास्टर साहब ने?' फिर प्रिंसिपल शिक्षक की बात मानकर अफसरों को लिखते कि 'छत गिरने वाली है।' तो अफसर उनके खिलाफ जांच बिठा देते कि 'जर्जर भवनों की जो सूची है, उसमें आपके स्कूल का भवन नहीं है। अब आप क्या इंजीनियर हैं? आर्किटेक्ट हैं? अफसर, नेता, मंत्री, बड़े आदमी हैं? आप हैं कौन? आपकी बात क्यों मानी जाए? आपके पत्र से स्पष्ट होता है कि आप सरकारी कार्य में बाधक बन रहे हैं। क्यों न आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए?'

शिक्षक शासन को जानते थे, इसलिए भवन के जर्जर होने की सूचना सरकार को नहीं दी। सरकार 'ओके रिपोर्ट' चाहती थी, सो दुर्घटना के दिन तक सब 'ओके' रहा आया। अब जब छत गिर गई तो 'अंधेर नगरी' में किसी एक 'जिम्मेदार' का सिर तो ढूंढ़ना था, जो बैठे-बैठाए वह शिक्षक मिल गया। इस तरह उस भवन के निर्माण से गिरने तक ठेकेदार को ठेकेदारी मिली। अफसर को कमीशन, नेता को चंदा, पीड़ित को मुआवजा और शिक्षक को दंड मिला। इसे कहते हैं, डेमोक्रेटिक जस्टिस!

X पोस्ट

क्या सदन में चर्चा का अर्थ यह होता है कि हम अपने देश के सैन्य अभियान को तमाशा घोषित करें? कुछ नेता आपरेशन महादेव के समय को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्या एनकाउंटर की तारीख भी पहले से घोषित की जानी चाहिए?

अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

जिन सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से बिहार में कुत्ते को रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट दिया गया, वे अधिकारी पूरी व्यवस्था पर कलंक हैं। इनकी शिनाख्त करके इन्हें निकाल बाहर करना चाहिए।

संजय निरुपम@sanjaynirupam

मैनचेस्टर टेस्ट के बाद मैं यह कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि वाशिंगटन सुंदर को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर खिलाया जाए।

डब्ल्यूवी रमन@wvraman

ट्रंप यूक्रेन युद्ध नहीं रुकवा सकते। पुतिन उन्हें रत्ती भर भाव नहीं दे रहे। इजरायल भी गाजा में उनकी बात मानने को तैयार नहीं। ऐसे में ट्रंप के पास यही राग अलापते रहने के अलावा और कुछ खास नहीं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान की लड़ाई रुकवा दी।

स्टैनले जानी@johnstanly

शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी का खेल

रोहित कौशिक
वरिष्ठ पत्रकार

इन दिनों देश में कई संदिग्ध शिक्षा संस्थान विभिन्न प्रकार की फर्जी डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं। ऐसे मामलों की लगातार खबरें भी सामने आ रही हैं। जब भी इन संस्थानों के संदिग्ध क्रियाकलापों का पर्दाफाश होता है, तब कार्रवाई की जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ये संस्थान फिर से सक्रिय हो जाते हैं। हाल में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी में चल रहे फर्जी डिग्री के खेल का भंडाफोड़ किया। एसटीएफ ने मोनाड यूनिवर्सिटी में छापेमारी के दौरान 1372 फर्जी डिग्रियां, 262 प्रोविजनल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट समेत अन्य सामग्रियां बरामद कीं। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह गिरोह बीए, बीएड, बीए-एलएलबी, फार्मेसी, बीटेक जैसे कोर्स की फर्जी डिग्रियां बनाकर बेचता था। प्रति छात्र 50,000 से चार लाख रुपये तक की वसूली की जाती थी। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि फर्जी डिग्रियों के माध्यम से शिक्षा का मजाक बनाया जा रहा है। फर्जी विश्वविद्यालय छात्रों को ठगने का काम कर रहे हैं।

कुछ समय पहले यूजीसी ने देशभर में खुले कई फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की थी। इन विश्वविद्यालयों को किसी भी प्रकार की डिग्री देने का अधिकार नहीं है। ये विश्वविद्यालय हाल में स्थापित नहीं हुए हैं, बल्कि कई वर्षों से चल रहे हैं। सही जानकारी के अभाव में हजारों छात्र इन फर्जी विश्वविद्यालयों के जाल में फंस जाते हैं। सवाल यह उठता है कि इतने वर्षों से चल रहे इन फर्जी विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? यदि ऐसे विश्वविद्यालयों पर पहले ही कार्रवाई की जाती, तो हजारों छात्रों के भविष्य पर मंडराते खतरे को टाला जा सकता था। दरअसल ऐसे मामलों में हर कोई अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है। यूजीसी समय-समय पर विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराता रहता है, लेकिन जब यूजीसी और सरकार को फर्जी विश्वविद्यालयों की जानकारी है, तो उनके संचालकों की धरपकड़ कर इन्हें बंद क्यों नहीं कराया जाता? फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची प्रकाशित कर देने मात्र से ही यूजीसी और सरकार अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो जाते। जानकारी होते हुए भी ऐसे विश्वविद्यालयों को कार्य करते देना और उनके संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना एक बड़ा अपराध है।

फर्जी डिग्री का बढ़ता खतरा। फाइल

यह विडंबना है कि आज गली-गली में निजी शिक्षा संस्थानों की बाढ़ आ गई है। इनमें से कुछ शिक्षा संस्थानों के क्रियाकलाप संदिग्ध हैं। सवाल यह है कि शिक्षा को व्यापार बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? उदारीकरण की आंधी ने अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सरकार ने शिक्षा का निजीकरण करते हुए गर्व का अनुभव किया। इस नीति के चलते अनेक औद्योगिक घराने शिक्षा के क्षेत्र में कूद पड़े। इनकी देखा-देखी छोटे व्यापारी भी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होने लगे। शिक्षा के निजीकरण ने एक नए प्रकार के व्यापार को जन्म दिया, जिसमें मुनाफा तो पूरा था, लेकिन व्यापारी की छवि मुनाफा कमाने वाले की नहीं, बल्कि उपकार करने वाले की थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक के बाद एक सरकारें इसी नीति पर चलती रहीं। सभी सरकारों द्वारा धड़ल्ले से निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों को मान्यता दी जाती रही। सरकारें बार-बार यह बताती रहीं कि हमारे देश के हालात को देखते हुए और विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। इस हड़बड़ी में शिक्षा की गुणवत्ता की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। कई बार जानबूझकर इन विसंगतियों को नजरअंदाज किया जाता है।

आजादी के बाद शिक्षा नीति की कमजोरी को दूर करने के प्रयास किए गए, लेकिन ये प्रयास पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे नीति-निर्माता शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की हड़बड़ाहट में अपना विवेक खोकर कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं, जो शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को ठेस पहुंचा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा नीति में परिवर्तन करना है या फिर इस परिवर्तन के माध्यम से शिक्षा की कमजोरियों को दूर करना है? इस दौर में उच्च शिक्षा की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। कहने को तो शिक्षा नीति में काफी बदलाव हुए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अभी भी लीक ही पीट रहे हैं। आज अनेक शिक्षक नवाचार को बढ़ावा देकर बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि आज गुरु के रूप में अध्यापक की प्रतिष्ठा लगातार कम हो रही है। शिक्षा जगत में मौजूद इन विसंगतियों के बीच नई शिक्षा नीति में भी एक बार फिर निजी शिक्षण संस्थानों को अनेक तरीकों से पनपने का मौका दिया गया है।

अब समय आ गया है कि सरकार निजीकरण की आड़ में पनपे संदिग्ध विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों के क्रियाकलापों पर गंभीरता से ध्यान दे, ताकि हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकारमय होने से बचाया जा सके।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या पहलगाम के आतंकियों पर चिदंबरम का बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा?

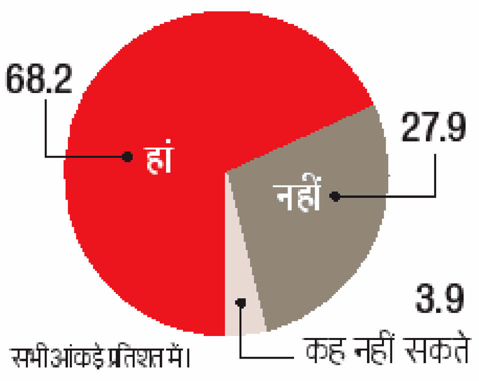

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या कांग्रेस ने शशि थरूर, मनीष तिवारी को आपरेशन सिंदूर पर बहस से दूर रखकर सही किया?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

नोबेल-नोबेल रट रहे दे दो नोबेल यार,
वरना रटते जायंगे 'चच्चा' बारम्बार।
'चच्चा' बारम्बार आत्मा भी भटकेगा,
दुनिया को तब शांति से नहीं रहने देगा!
जानबूझ हर ओर बजाते खतरे की बेल,
फिर रुकने पर युद्ध रटें वे नोबेल-नोबेल!!
– ओमप्रकाश तिवारी

मंथन

व्यापारिक संबंधों में नया अध्याय

डा. सुशील कुमार सिंह
निदेशक, वाईएस रिसर्च फाउंडेशन आफ पालिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन

भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ हालिया व्यापार समझौता दोनों देशों के रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा

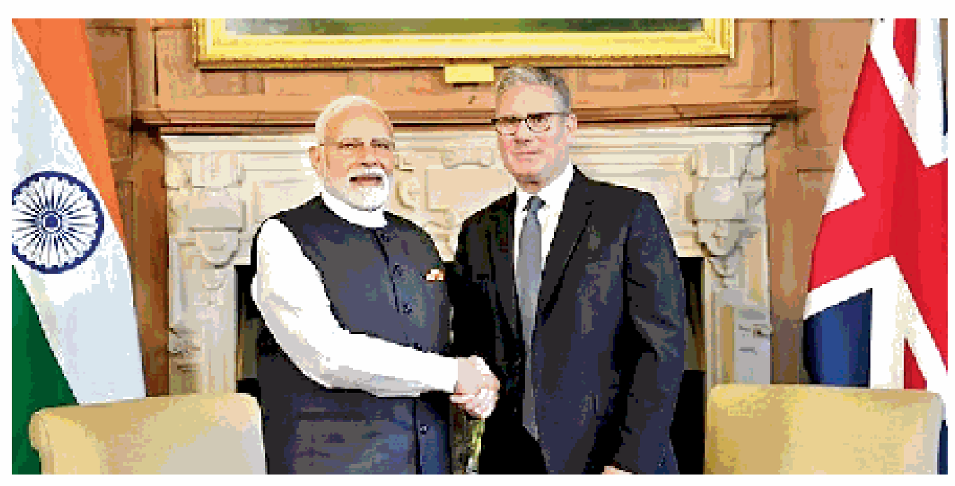

और करीब आते भारत-ब्रिटेन। फाइल

अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने कुछ वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की थी कि भारत जल्द ही विश्व के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक बनेगा। यह स्पष्ट है कि जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा, इसकी राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति के साथ वैश्विक प्रभाव में भी बदलाव होगा। हाल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें भारत-ब्रिटेन विजन-2035 जारी किया गया और व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को औपचारिक रूप दिया गया। यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा, जिससे व्यापार, नवाचार, रक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न होंगे। वर्तमान में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार का आकार लगभग 56 अरब डालर है। ब्रिटेन यह जानता है कि मुक्त व्यापार के माध्यम से इसे 2030 तक दोगुना किया जा सकता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त व्यापार लगभग 120 बिलियन डालर तक पहुंच जाएगा। इस समझौते से वर्ष 2040 तक भारत के ब्रिटेन के निर्यात में भी 60 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है। इससे रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा, जलवायु एवं स्थायित्व, शिक्षा और कौशल विकास को बल मिलेगा।

हिंद प्रशांत क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी और रक्षा विषयों पर भारत और ब्रिटेन के बीच 2015 में समझौते हो चुके हैं। वर्तमान समझौते के माध्यम से ब्रिटेन हिंद प्रशांत क्षेत्र की विकासशील अर्थव्यवस्था को एक अवसर के रूप में देख सकता है। इस क्षेत्र में दुनिया के 48 देशों की लगभग 65 प्रतिशत आबादी निवास करती है। ब्रिटेन का दृष्टिकोण चीन के प्रति पूरी तरह सख्त नहीं है, पर वह इसे लेकर सतर्क है। ब्रिटेन नहीं चाहेगा कि चीन ऐसे देशों के खनिज संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। कई देशों के बंदरगाहों पर कब्जा करना चीन की सामरिक नीति रही है। क्वाड के माध्यम से अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और भारत ने इस पर नकेल कसने का प्रयास किया है। यदि ब्रिटेन अपने बाजार और व्यापार समेत आर्थिक नीतियों को भारत के साथ साझा करता है, तो यह न केवल द्विपक्षीय लाभ को बढ़ावा देगा, बल्कि चीन को भी संतुलित करने में मदद करेगा।

मुक्त व्यापार समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99 प्रतिशत शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जिससे हमारे वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन तथा आटो पार्ट्स जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। भारत 90 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क में कटौती करेगा या उसे समाप्त करेगा, जिसमें ब्रिटेन से आयातित 92 प्रतिशत वस्तुएं शामिल हैं, जैसे कार, शराब आदि। भारत समझौते के छठे वर्ष में ब्रिटेन के इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ समाप्त कर देगा और 40 हजार ब्रिटिश पाउंड से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई शुल्क नहीं लेगा। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय पेशेवरों और कंपनियों को वित्तीय सेवाएं, शिक्षा आदि क्षेत्रों में पहुंच प्राप्त होगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग, वास्तुकला जैसे क्षेत्रों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा योगदान से तीन वर्षों के लिए छूट मिलेगी, जिससे भारतीय प्रतिभा की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। समावेशी विकास के मामले में यह समझौता महिलाओं, युवाओं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों और नवप्रवर्तकों की भागीदारी को बढ़ावा देगा। कृषि लाभ की दृष्टि से भी यह समझौता उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि भारत के कृषि उत्पादों जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल और समुद्री खाद्य पदार्थों पर शुल्क में कटौती की जाएगी।

भारत और ब्रिटेन के बीच जो प्रमुख समझौते हुए हैं, उनमें साल 2022 में ब्रिटेन द्वारा नए लड़ाकू विमानों की प्रौद्योगिकी और नव वाहन प्रौद्योगिकी पर भारत के साथ सहयोग की प्रतिबद्धता शामिल है। भारत की असल चिंता चीन है। भारत की समस्या यह है कि सीमा पर तनाव के बावजूद व्यापार में चीन पर निर्भरता कम नहीं हो रही। भारत इस असंतुलन से निपटना चाहता है और मेक इन इंडिया में ब्रिटिश निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। ब्रिटेन की भूमिका भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसका लाभ कैसे उठाया जाएगा, यह विचार करने का विषय है। 1990 के बाद पश्चिमी देशों के साथ भारत के जो रिश्ते बने हैं, वे आज परवान चढ़ रहे हैं। ये रिश्ते न केवल आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि चीन को संतुलित करने में भी सहायक हो सकते हैं।

****

पूरा सब्सक्राइब हुआ आदित्य इन्फोटेक का आइपीओ

नई दिल्ली : सीपी प्लस नाम से वीडियो सिक्युरिटी और सर्विलांस उत्पाद बेचने वाली कंपनी आदित्य इन्फोटेक का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) पहले दिन कुछ ही घंटों में पूरा सब्सक्राइब हो गया। इस आइपीओ में 1,12,23,759 शेयर बिक्री के लिए पेश किए गए हैं। इसके सापेक्ष दोपहर एक बजकर 36 मिनट तक 1,18,12,438 शेयरों के लिए आवेदन मिल गए थे। (प्रेट्र)

आयात शुल्क में कटौती के बाद 2025 में हम भारत को 50 लाख टन पाम तेल निर्यात का आंकड़ा पार कर लेंगे। 2024 में 48 लाख टन तेल का निर्यात किया था।
—एडी मार्टोनो, चेयरमैन, इंडोनेशिया पाम आयल काउंसिल

सेंसेक्स	81,337.95	▲ 446.93
निफ्टी	24,821.10	▲ 140.20
सोना प्रति दस ग्राम	₹97,820	▼ ₹200
चांदी प्रति किलोग्राम	₹1,13,000	बदलाव नहीं
डालर	₹86.91	▲ ₹0.21
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$70.48	

एक नजर में

लेंसकार्ट ने सेबी के पास जमा किए आइपीओ दस्तावेज

नई दिल्ली: चश्मा बेचने वाली कंपनी लेंसकार्ट ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) के लिए सेबी के पास मसौदा दस्तावेज जमा किए हैं। इस आइपीओ में 2,150 करोड़ रुपये के नए शेयर और 13.22 करोड़ प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। नए शेयरों की बिक्री से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल कंपनी कारोबार विस्तार पर करेगी। उधर, सीपी प्लस नाम से वीडियो सिक्युरिटी और सर्विलांस उत्पाद बेचने वाली कंपनी आदित्य इन्फोटेक का आइपीओ पहले दिन कुछ ही घंटों में पूरा सब्सक्राइब हो गया। (प्रेट्र)

रिलायंस जियो ने शुरू की क्लाउड पीसी सेवा

नई दिल्ली: दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने सब्सक्रिप्शन आधारित क्लाउड पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) सेवा की शुरुआत की है। इसके माध्यम से सब्सक्राइबर सेट-टाप बाक्स की सहायता से अपने टेलीविजन का उपयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर के रूप में कर सकेंगे। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, जियोपीसी सब्सक्रिप्शन 599 रुपये प्रति माह से शुरू होता है। इसकी वार्षिक कीमत 4,599 रुपये है। (प्रेट्र)

व्यापार वार्ता के लिए अमेरिकी दल 25 अगस्त को आएगा

नई दिल्ली: भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी दल 25 अगस्त को भारत आएगा। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने आगे कहा कि एक अगस्त की समयसीमा नजदीक आने के साथ ही दोनों पक्ष एक व्यापार समझौते पर बातचीत जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत (26%) सहित दर्जनों देशों पर लगाए गए शुल्क की निलंबन अवधि एक अगस्त को समाप्त हो रही है। (प्रेट्र)

ब्राडबैंड ग्राहकों की संख्या बढ़कर 97.91 करोड़ हुई

नई दिल्ली: ब्राडबैंड ग्राहकों की कुल संख्या जून में बढ़कर 97.91 करोड़ हो गई है। मई में इस तरह के ग्राहकों की संख्या 97.48 करोड़ थी। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार, जून महीने में 1.35 करोड़ ग्राहकों ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए अनुरोध किया। भारत में कुल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मई के अंत में 120.70 करोड़ से बढ़कर जून के अंत में 121.93 करोड़ हो गई है। कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या मई के अंत में 116.10 करोड़ से बढ़कर जून के अंत में 116.30 करोड़ हो गई। (आइएएनएस)

चार सालों में दोगुना हुआ रियल्टी क्षेत्र को बैंक कर्ज

नई दिल्ली: बीते चार वित्त वर्षों में भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र को बैंकों का कर्ज वितरण दोगुना हो गया है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कोलियर्स इंडिया के अनुसार, मार्च 2025 के अंत तक रियल्टी क्षेत्र को कुल बैंक कर्ज 35.4 लाख करोड़ रुपये रहा है। कोलियर्स ने आरबीआइ के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कुल बैंक ऋण 109.5 लाख करोड़ रुपये था जो मार्च 2025 के अंत में समाप्त वित्त वर्ष में बढ़कर 182.4 लाख करोड़ रुपये हो गया है। (प्रेट्र)

एक अगस्त से प्रत्येक सफल यूपीआइ पेमेंट के बाद दिखेगा बैलेंस

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) ने यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआइ से लेनदेन को आसान व सुरक्षित बनाने और सिस्टम पर लोड कम करने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी बैंकों और पेमेंट एप्स सहित यूपीआइ इकोसिस्टम से जुड़े सभी सदस्यों को 31 जुलाई तक इनको लागू करना होगा। यानी एक अगस्त से नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप यूपीआइ की सेवाएं मिलेंगी। आइए जानते हैं कि इन दिशा-निर्देशों से क्या-क्या बदलाव होंगे...

एक एप से रोजाना 50 बार देख सकेंगे बैलेंस

एक अगस्त से उपयोगकर्ता एक यूपीआइ एप पर 24 घंटे में केवल 50 बार अपने खाते का बैलेंस जांच सकेंगे। हालांकि, उपयोगकर्ता प्रत्येक एप पर अलग-अलग इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इसका मतलब यह है कि पेटीएम, फोनपे, गूगलपे जैसे प्रत्येक एप पर अलग-अलग प्रतिदिन 50 बार खाते का बैलेंस जांचा जा सकेगा। बैलेंस जांचने के लिए उपयोगकर्ता को हर बार आग्रह करना होगा और एप स्वत: बैलेंस नहीं दिखा सकेंगे।

यूपीआइ से जुड़े खाते देखने की सीमा तय

एनपीसीआइ ने अब उपयोगकर्ता के यूपीआइ एप से जुड़े खाते देखने की सीमा भी तय कर दी है। एक अगस्त से उपयोगकर्ता 24 घंटे में अपने यूपीआइ एप से जुड़े बैंक खातों को केवल 25 बार देख सकेगा।

भुगतान से पहले दिखेगा बैंक में पंजीकृत नाम

धोखाधड़ी और भुगतान संबंधी गलतियों को रोकने के लिए यूपीआइ एप अब लेनदेन पूरा होने से पहले प्राप्तकर्ता के पंजीकृत बैंक का नाम प्रदर्शित करेंगे। इससे उपयोगकर्ताओं को यह सत्यापित करने में मदद मिलेगी कि वे सही व्यक्ति या व्यवसाय को पैसे भेज रहे हैं।

एनपीसीआइ ने नियम लागू नहीं करने पर दी कार्रवाई की चेतावनी

एनपीसीआइ ने चेतावनी दी है कि इन नियमों को लागू नहीं करने पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसमें जुर्माना, नए ग्राहक को शामिल करने पर रोक, या यूपीआइ सेवाओं के लिए एपीआइ पहुंच पर प्रतिबंध भी शामिल है। इन दिशा-निर्देशों को जारी करने का उद्देश्य यूपीआइ के जरिये होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है।

विशेष समय पर होगा स्वतः भुगतान

एनपीसीआइ ने आटोमैटिक या स्वत: होने वाले भुगतान के लिए विशिष्ट समय अवधि तय की है। अधिसूचित भुगतान सुबह 10 बजे से पहले तक, दोपहर में एक से शाम पांच बजे तक और रात को 9.30 के बाद हो सकेंगे। एनपीसीआइ ने यूपीआइ भुगतान के लिहाज से सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक और शाम पांच से रात 9.30 बजे तक के समय को काफी व्यस्त माना है।

बैंकों को दिखाना होगा बैलेंस

बैंकों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक सफल यूपीआइ भुगतान के बाद उनको उपयोगकर्ता को उसके बैंक खाते का बैलेंस दिखाना होगा।

केवल 10 बार भुगतान वापसी आग्रह

अब उपयोगकर्ता भुगतान वापसी के लिए एक महीने में केवल 10 बार आग्रह कर सकेगा। एक भुगतान प्राप्तकर्ता से केवल पांच बार पैसा वापसी का आग्रह किया जा सकेगा।

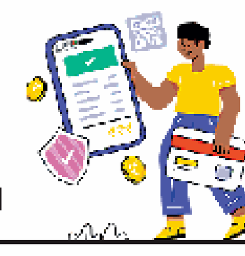

लंबित लेनदेन की जांच केवल तीन बार

उपयोगकर्ता अपने लंबित लेनदेन के भुगतान की जांच के लिए केवल तीन प्रयास कर सकेंगे। प्रत्येक प्रयास के बीच 90 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए। (स्रोत: आइएएनएस)

भारत की विकास दर का पूर्वानुमान बढ़ाया

वाशिंगटन, रायटर: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने अनुकूल वैश्विक आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए भारत के लिए 2025 और 2026 के अपने आर्थिक विकास पूर्वानुमानों को बढ़ाया है। आइएमफ ने दक्षिण एशियाई देश के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 2025 और 2026 दोनों के लिए संशोधित कर 6.4 प्रतिशत कर दिया है। अप्रैल में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी ने 6.2 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया था। आइएमएफ ने अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि भारत का विकास दृष्टिकोण ''अप्रैल के पूर्वानुमान की तुलना में अधिक सौम्य बाहरी वातावरण'' को दर्शाता है। संगठन ने इस वर्ष उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास के अपने दृष्टिकोण को 3.7% से बढ़ाकर 4.1% कर दिया, जो चीन पर अधिक आशावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है।

जीएसटी स्लैब व रिफंड नियमों में होंगे बदलाव

बड़े सुधारों को लेकर सक्रिय हुआ वित्त मंत्रालय, अगस्त या सितंबर में हो सकती है काउंसिल की बैठक

- कच्चे माल और उनसे बनने वाले तैयार माल की जीएसटी दर को समान करने पर विचार
- जीएसटी स्लैब पर सहमति बनाने के लिए राज्यों के साथ चल रहा विचार-विमर्श

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय में इन दिनों जीएसटी प्रणाली को अगले चरण में ले जाने की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। जीएसटी के स्लैब में बदलाव को लेकर राज्यों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। एक ही प्रकार की वस्तु के अलग-अलग मूल्य होने पर जीएसटी की अलग-अलग दरों को भी एक समान करने पर विचार हो रहा है। कच्चे माल और उनसे बनने वाले तैयार माल की जीएसटी दर को समान करने पर चर्चा हो रही है तो जीएसटी रिफंड को इनकम टैक्स रिफंड की तरह सरल बनाने की कोशिश की जा रही है। सभी राज्यों के एकमत होने पर ही जीएसटी से जुड़ा कोई भी बदलाव लाया जा सकता है और यह बदलाव जीएसटी काउंसिल की बैठक में ही संभव है। इसलिए जीएसटी की अगली बैठक से पहले राज्यों के बीच सहमति बनाने की कोशिश है।

वित्त मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि काउंसिल की बैठक भले ही नहीं बुलाई गई है, लेकिन जीएसटी में बड़े बदलाव की तैयारी पर काम चल रहा है। राज्यों के साथ इस संबंध में कई बैठकें भी हुई हैं। आठ साल पहले वर्ष 2017 की जुलाई में जीएसटी प्रणाली की शुरुआत के बाद से ही जीएसटी स्लैब को कम करने की चर्चा चल पड़ी थी, लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। अब जीएसटी संग्रह भी मासिक रूप से दो लाख करोड़ से अधिक होने लगा है, इसलिए अब उपभोक्ता और कारोबारी दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए बदलाव की तैयारी हो रही है।

मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि विकसित देशों में जीएसटी का एक ही स्लैब है, लेकिन भारत में यह संभव नहीं है। अभी जीएसटी स्लैब मुख्य रूप से पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत का है। सोने पर तीन प्रतिशत जीएसटी है।

सूत्रों का कहना है कि 12 और 18 की जगह एक नया स्लैब लाया जा सकता है। 12 प्रतिशत के स्लैब को समाप्त कर उस स्लैब में शामिल वस्तुओं को पांच और 18 प्रतिशत के स्लैब में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में, वर्तमान में 12 प्रतिशत में शामिल जिन वस्तुओं को 18 प्रतिशत के स्लैब में शामिल किया जाएगा, वे महंगी हो जाएंगी और जिन्हें पांच प्रतिशत में डाला जाएगा, वे सस्ती हो जाएंगी। ऐसे में महंगी होने वाली वस्तु की बिक्री प्रभावित हो सकती है। राज्यों के बीच इन्हीं सब चीजों को लेकर सहमति बनानी है।

बता दें कि पिछले सात महीनों से जीएसटी काउंसिल की बैठक नहीं बुलाई गई है, जबकि चलन के मुताबिक हर तीसरे महीने काउंसिल की बैठक बुलाई जाती है। अब संसद सत्र के खत्म होने के बाद अगस्त आखिर या सितंबर शुरू में ही काउंसिल की बैठक संभव है।

आम लोगों से जुड़ी चीजों की दर में लाई जा सकती है कमी

अभी गारमेंट से लेकर फुटवियर तक में 1000 रुपये से अधिक और कम कीमत पर अलग-अलग जीएसटी दरें हैं। इस प्रकार की असमानता को खत्म किया जा सकता है। गारमेंट से जुड़े कच्चे माल पर जीएसटी की दर अलग है तो तैयार माल पर अलग। इसे भी एक समान करने की तैयारी हो रही है। इससे कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) लेने में दिक्कत होती है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक आम लोगों से जुड़ी चीजों की जीएसटी दर में कमी लाई जा सकती है। इससे इन वस्तुओं की खपत बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। जीएसटी कम करने से बिक्री अधिक होगी और इससे राजस्व भी प्रभावित नहीं होगा।

अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र: अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले स्मार्टफोन के मामले में भारत ने कैलेंडर वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में चीन को पीछे छोड़ दिया है। कैनालिस के शोध से पता चला है कि अप्रैल-जून की अवधि में चीन में असेंबल किए गए स्मार्टफोन निर्यात की हिस्सेदारी एक साल पहले के 61 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत रह गई है। बता दें कि टैरिफ संबंधी चिंताओं के बीच विक्रेताओं के इन्वेंट्री आगे बढ़ाने के कारण दूसरी तिमाही में अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कैनालिस (अब ओमडिया का हिस्सा) ने कहा, 'चीन की हिस्सेदारी में गिरावट का अधिकांश फायदा भारत को हुआ है। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन की कुल मात्रा में साल-दर-साल 240 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अब अमेरिका में आयातित स्मार्टफोन में उसकी हिस्सेदारी 44 प्रतिशत हो गई है। 2024 की दूसरी तिमाही में अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में भारत की हिस्सेदारी केवल 13 प्रतिशत थी।'' कैनालिस के अनुसार, दूसरी तिमाही में आइफोन का निर्यात साल-दर-साल 11 प्रतिशत घटकर 1.33 करोड़ यूनिट रहा है। सैमसंग का निर्यात साल-दर-साल 38 प्रतिशत बढ़कर 83 लाख यूनिट हो गया। मोटोरोला का अमेरिका को निर्यात दो प्रतिशत बढ़कर 32 लाख यूनिट हो गया। गूगल और टीसीएल शीर्ष पांच में शामिल रहे। गूगल का निर्यात 13 प्रतिशत बढ़कर आठ लाख यूनिट हो गया, वहीं टीसीएल का निर्यात 23 प्रतिशत घटकर सात लाख यूनिट रह गई। एपल ने भारत में आइफोन 16 सीरीज के प्रो माडल की मैन्यूफैक्चरिंग और असेंबलिंग शुरू कर दी है। हालांकि, अमेरिका में प्रो माडल की आवश्यक आपूर्ति के लिए वह अभी भी चीन में स्थापित विनिर्माण केंद्रों पर निर्भर है।

44 प्रतिशत रही भारत की हिस्सेदारी अमेरिका के कुल स्मार्टफोन आयात में दूसरी तिमाही के दौरान, चीन की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी रही

सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने नियमों में किया बदलाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: पिछले चार वर्षों से भारत सोलर ऊर्जा परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाले सौर पीवी माड्यूल के निर्माण में चीन पर निर्भरता खत्म कर आत्मनिर्भर होने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। सरकारी डाटा बताता है कि इसमें सफलता मिली है लेकिन चीन निर्मित सौर उपकरणों पर निर्भरता खत्म नहीं हुई है। अब सोमवार को नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) माड्यूल व सेल्स के लिए माडल और निर्माताओं की स्वीकृत सूची (एएलएमएम) में एक बार फिर संशोधन किया है। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह ना सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि घरेलू सौर मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल होगा। यह संशोधन एमएनआरई की तरफ से दो जनवरी, वर्ष 2019 को जारी आदेश में किया गया है, जिसके तहत सरकार देश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले गुणवत्तापूर्ण उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है।

एएलएमम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सिर्फ वो निर्माता और माडल ही सरकारी की नवीकरणीय परियोजनाओं या योजनाओं में उपयोग किए जाएं, जो मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हों। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि नए संशोधन का उद्देश्य भारत में सौर पीवी सेल्स और माड्यूल के उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना है। सरकार का कहना है कि यह कदम भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा और आयात पर निर्भरता को कम करेगा। वर्ष 2024-25 में भारत ने 4.5 अरब के सौर ऊर्जा उपकरणों का आयात किया था। इसमें 83 प्रतिशत चीन से आया था। ताजे आंकड़े बताते हैं कि अब चीन से सौर ऊर्जा आयात में कमी आने लगी है। असलियत में घरेलू स्तर पर जितनी तेजी से सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार हो रहा है, उसकी आपूर्ति घरेलू निर्माण से पूरी होना मुश्किल है। सरकार का मानना है कि एएलएमएम में संशोधन के बाद देश में सौर पीवी माड्यूल और सेल्स का निर्माण क्षमता में तेजी से विस्तार होगा।

सौर पीवी माड्यूल व सेल्स निर्माण के लिए जरूरी माडल व निर्माताओं की स्वीकृत सूची में किया गया संशोधन

बैंक आफ बड़ौदा ने मनाया स्थापना दिवस

नई दिल्ली, वि.: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आफ बड़ौदा ने अपने 118वें पर विश्वास, नवाचार और स्थायित्वपूर्ण वृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस स्थापना दिवस की थीम 'भरोसे का सशक्त आधारः नवाचार' रखी गई है, जो वर्षों से ग्राहकों के भरोसे को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए भविष्य की बैंकिंग को आकार देने के बैंक के सोच को दर्शाता है। समारोह में वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव एम. नागराजू भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर बैंक ने ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करते हुए बैंकिंग पहुंच को बढ़ाने और स्थायित्वपूर्ण वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से डिजिटल और तकनीक, संवहनीय बैंकिंग और ग्रीन फाइनेंस के क्षेत्र में कई नवोन्मेषी उत्पादों और पहलों की घोषणा की। इसमें एमएसएमई, व्यापारियों और कारपोरेट ग्राहकों के लिए एक नए मोबाइल बैंकिंग एप बाब वर्ल्ड बिजनेस की लांचिंग और बाब इनसाइट ब्रेल डेबिट कार्ड प्रमुख हैं।

भारतवंशी शैलेश बने पीएंडजी के नए सीईओ

शैलेश जेजुरिकर ● फाइल फोटो

- आइआइएम लखनऊ के छात्र रहे जेजुरिकर एक जनवरी, 2026 को पद संभालेंगे
- छह सालों से कंपनी के सीओओ हैं शैलेश, ओटिस के बोर्ड में भी हैं शामिल

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत में जन्मे और आइआइएम लखनऊ के छात्र रहे शैलेश जेजुरिकर अमेरिकी एफएमसीजी कंपनी प्राक्टर एंड गैंबल (पीएंडजी) के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होंगे। 1989 में कंपनी में सहायक ब्रांड प्रबंधक के तौर पर शामिल हुए 58 वर्षीय जेजुरिकर एक जनवरी, 2026 को जान मोलर की जगह लेंगे। कंपनी द्वारा जारी बयान के अनुसार, वह पिछले छह सालों से कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में काम कर रहे हैं। वह लिफ्ट निर्माता ओटिस एलिवेटर के बोर्ड में भी शामिल हैं।

कंपनी के बोर्ड ने अक्टूबर 2025 में होने वाली वार्षिक शेयरधारक बैठक में निदेशक के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए जेजुरिकर को नामित किया है। उन्होंने उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों में वैश्विक फैब्रिक केयर और होम केयर सहित कंपनी के कई प्रमुख व्यवसायों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सप्लाई चेन, सूचना प्रौद्योगिकी और वैश्विक व्यावसायिक सेवाओं में कंपनी की नई रणनीतियों और परिचालन परिणामों के विकास का नेतृत्व करने में भी मदद की है। पीएंडजी भारतीय बाजार में एक अग्रणी एफएमसीजी कंपनी है, जो एरियल, टाइड, व्हिस्पर, ओले, जिलेट, एंबीपुर, पैम्पर्स, पैंटीन, ओरल-बी, हेड एंड शोल्डर और विक्स जैसे ब्रांड बेचती है। किसी भारतवंशी के वैश्विक कंपनी के सीईओ के तौर पर काम करने वाले लोगों के क्लब में जेजुरिकर भी शामिल हो गए हैं।

इसी महीने सबीह बने थे एपल के सीओओ

इस महीने की शुरुआत में मुरादाबाद में जन्मे सबीह खान को आइफोन निर्माता कंपनी एपल के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के तौर पर नामित किया गया था। एपल के सीईओ टिम कुक के नेतृत्व में काम करने वाले सबीह खान इस महीने के अंत में जेफ विलियम्स का स्थान लेंगे। सबीह 2019 में एपल के आपरेशंस में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने थे।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

राष्ट्रीय फलक

सरकार के कदमों से हुई कई किसानों की आय दोगुनी : शिवराज चौहान

> कृषि मंत्री ने संसद में कहा-केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की रिकार्ड खरीद की

नई दिल्ली, प्रेट्र : कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से कई किसानों की आय दोगुनी हो गई है। लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए, चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की रिकार्ड खरीद की है, रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराए हैं और 1.83 लाख करोड़ रुपये के बीमा दावों का निपटान किया है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के आश्वासन पर कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर के प्रश्न के उत्तर में चौहान ने कहा, 'मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कई किसानों की आय दोगुनी से भी अधिक हो गई है।''

कृषि मंत्री ने किसानों द्वारा वहन की गई उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने संबंधी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए पिछली यूपीए सरकार की आलोचना की। चौहान ने कहा, मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और अब किसानों की उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर कृषि उपज का एमएसपी तय किया जाता है। पिछली यूपीए सरकार ने दावा किया था कि सिफारिशों को लागू करने से बाजार असमानता आ जाएगी।

नए आयकर विधेयक में कर दरों में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं

> आयकर विभाग ने कहा, इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल बनाना और अनावश्यक प्रविधानों को हटाना

नई दिल्ली, आइएएनएस : आयकर विभाग ने मंगलवार को प्रस्तावित आयकर विधेयक 2025 पर एक स्पष्टीकरण जारी किया। विभाग ने कहा कि नए आयकर विधेयक का मकसद सिर्फ भाषा को सरल बनाना और अनावश्यक व पुराने प्रविधानों को हटाना है। यह विधेयक कर दरों में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है।

दरअसल, विभाग की तरफ से यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्टों और इंटरनेट मीडिया पोस्ट के बाद आया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि नया विधेयक कुछ श्रेणियों के करदाताओं के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर दरों में बदलाव करेगा। कुछ रिपोर्टों में यह कहा गया है कि नए विधेयक में इक्विटी निवेश पर मौजूदा कर छूट को हटाया जा सकता है।

विभाग ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट में कहा, ''विभिन्न मीडिया प्लेटफार्म पर ऐसे समाचार प्रसारित हो रहे हैं कि नया आयकर विधेयक, 2025 कुछ श्रेणियों के करदाताओं के लिए एलटीसीजी पर कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव करता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आयकर विधेयक, 2025 का उद्देश्य भाषा को सरल बनाना और अनावश्यक/अप्रचलित प्रविधानों को हटाना है।'' विभाग ने आगे कहा, 'इसका उद्देश्य करों की किसी भी दर में बदलाव नहीं करना है। इस संबंध में किसी भी अस्पष्टता का विधेयक पारित होने के दौरान उचित समाधान किया जाएगा।''

बयान में स्पष्ट किया गया है कि नया विधेयक मौजूदा कर ढांचे में कोई बदलाव किए बिना, कानून को समझने में आसान बनाने और मौजूदा प्रविधानों को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है। नया आयकर विधेयक इस वर्ष फरवरी में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद, इसे लोकसभा की प्रवर समिति के पास भेजा दिया गया था, जिसने हाल में अपनी रिपोर्ट दी है।

अंडमान क्षेत्र में मिले तेल भंडार से मजबूत होगी देश की ऊर्जा सुरक्षा

संसद प्रश्नोत्तर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारत के पेट्रोलियम मानचित्र में एक नया क्षेत्र उभरकर सामने आ रहा है, जिसको लेकर समूचे हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में उत्साह है। यह क्षेत्र अंडमान निकोबार के समुद्री क्षेत्र में स्थित है। इसके बारे में मंगलवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने राज्यसभा में विस्तृत जानकारी दी।

पुरी ने पहले भी कहा है कि जिस तरह से कैरेबियन सागर में स्थित देश गुयाना में नए तेल भंडारों की खोज ने पूरी तस्वीर बदल दी है, वैसा ही अंडमान क्षेत्र में होने वाला है जो भारत के पेट्रोलियम सेक्टर को पूरी तरह से बदल देगा। बता दें कि भारत का कच्चा तेल उत्पादन स्थिर है। 2024-25 में घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन 2.8 करोड़ टन रहा, जबकि ईंधन की मांग लगातार बढ़ रही है। पिछले एक दशक में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर भारत की निर्भरता 75 प्रतिशत से बढ़कर 86 प्रतिशत हो चुकी है। पुरी ने बताया कि वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने नीतियों में बदलाव कर दस लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल खोज व उत्खनन करने का रास्ता साफ किया था। इसकी वजह से ही अंडमान निकोबार आफशोर बेसिन के गहरे समुद्र में पेट्रोलियम भंडार की संभावना बनी है। यह बेसिन बंगाल-अराकान तलछट का हिस्सा है। यह बेसिन भारत-म्यांमार टेक्टोनिक प्लेट्स का हिस्सा है, जिसके बारे में माना जाता है कि वहां काफी पेट्रोलियम भंडार हो सकते हैं।

****

2024 में दुनियाभर में भूखे लोगों की संख्या में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट आई, जो कोविड संकट के समय की तुलना में काफी कम है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के अधिकांश हिस्सों में कुपोषण और गहरा गया है।

बांग्लादेश में भीड़ ने की हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़

आपत्तिजनक पोस्ट के बाद दो दर्जन घरों में भीड़ का उपद्रव, पोस्ट करने वाला किशोर गिरफ्तार कर पुनर्वास केंद्र भेजा गया

22 प्रभावित हिंदू परिवारों में से 19 के पुरुष सदस्य घरों में रह रहे हैं, स्थिति को सेना ने नियंत्रित किया

बांग्लादेश के रंगपुर जिले के गंगाचारा में हिंसक भीड़ ने हिंदू परिवारों पर हमला कर लूटपाट कर तोड़फोड़ की। आइएएनएस

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में शनिवार को एक हिंसक भीड़ ने हिंदू समुदाय के लोगों के करीब दो दर्जन घरों को तहस-नहस किया है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने रंगपुर के गंगाचारा उपजिला में हुई हिंसा में क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के आदेश जारी किए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह हिंसा तब भड़की जब एक 17 वर्षीय हिंदू युवक ने फेसबुक पर पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। पुलिस ने इस किशोर को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक निजी पालीटेक्निक संस्थान का तीसरे सेमेस्टर का छात्र है। गंगाचारा पुलिस स्टेशन के अधिकारी अल इमरान ने कहा कि पुलिस ने जब आरोप सही पाए तो उसे शनिवार को रात 8:30 बजे के आसपास हिरासत में लिया गया और पुलिस स्टेशन लाया गया। उसे अदालत के आदेश के बाद एक किशोर पुनर्वास केंद्र भेजा गया। इस घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने शनिवार रात और फिर रविवार दोपहर को हिंदू समुदाय के कई घरों पर हमला किया और उन्हें नुकसान पहुंचाया। फिर स्थिति को सेना ने नियंत्रित किया। यूनुस के कार्यालय ने कहा कि हिंसा में 12 हिंदू परिवारों को नुकसान पहुंचा है। पीड़ित पड़ोसी गांव में अपने रिश्तेदारों के घर रह रहे हैं।" जबकि रंगपुर के उप आयुक्त मोहम्मद रबियुल फैसल ने बताया कि 22 प्रभावित हिंदू परिवारों में से 19 के पुरुष सदस्य अब अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन महिला सदस्य अन्यत्र रह रही हैं क्योंकि उनके घरों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय अधिकारी हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भारत विरोधी गतिविधियों के लिए पाक खुफिया एजेंसी आइएसआइ की नजर अब नेपाल पर

- भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नेपाल को 'अड्डा' बनाने की फिराक में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेपाल में पाकिस्तानियों की संख्या बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही

पाक खुफिया एजेंसी आइएसआइ। फाइल

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारत विरोधी गतिविधियों के लिए बांग्लादेश को अपना 'अड्डा' बनाने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ अब नेपाल पर भी नजरें गड़ाए हुए है। नेपाल में रहने वाले पाकिस्तानियों की संख्या बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है और उन्हें ऐसे स्लीपर सेल में बदलने की बड़ी साजिश है जो भारत में आतंकी हमलों का अंजाम दे सकें।

बांग्लादेश के स्थानीय समाचार पत्र 'पुरबोकोन' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अलहाज शम्सुल हक फाउंडेशन नामक एक संगठन, जिसे ऐश फाउंडेशन के नाम से भी जाना जाता है, ने नेपाल में सुनसरी जिले के विराटनगर के पास इनारवा क्षेत्र में एक मस्जिद की आधारशिला रखी है। 'रूजाक मस्जिद' नामक इस मस्जिद को यह फाउंडेशन स्थानीय मुस्लिम आबादी का धार्मिक केंद्र बताता है। इसका शिलान्यास समारोह ऐश फाउंडेशन के अध्यक्ष इंजीनियर मुहम्मद नासिरुद्दीन ने इसी वर्ष 18 जुलाई को किया था।

उन्होंने कहा कि यह मस्जिद न केवल मुसलमानों के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगी, बल्कि नेपाल की 95 प्रतिशत गैर-मुस्लिम आबादी के बीच इस्लामी जागरण या धर्मांतरण का केंद्र भी बनेगी। ऐश फाउंडेशन ने एक बयान में कहा, 'रूजाक मस्जिद सुनसरी में मुसलमानों के लिए एक आध्यात्मिक और सांप्रदायिक केंद्र बनने की उम्मीद है। साथ ही, यह नेपाल में अंतर-सामुदायिक सहयोग और विकास का एक उदाहरण भी बनेगी। समूचे दक्षिण एशिया में वंचित समुदायों के लिए यह फाउंडेशन धार्मिक और शैक्षिक बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।'' भारतीय एजेंसियों को संदेह है कि आइएसआइ इस पहल का गुप्त रूप से समर्थन कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पहल को कुछ खाड़ी देशों और तुर्किये का भी समर्थन प्राप्त है। आगे चलकर यह मस्जिद न केवल एक धार्मिक केंद्र के रूप में, बल्कि आइएसआइ समर्थित आतंकवादी समूहों के लिए एक लाजिस्टिक्स सेंटर के रूप में भी काम कर सकती है।

गौरतलब है कि ऐश फाउंडेशन की शुरुआत 2018 में हुई थी और इसे 2022 में बांग्लादेश में एक एनजीओ के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह फाउंडेशन एक ज्वाइंट स्टाक कंपनी के रूप में काम करता था। बहरहाल, 18 जुलाई को इस फाउंडेशन ने मस्जिद के निर्माण के लिए और नेपाल तथा अन्य पड़ोसी देशों में इसी तरह की परियोजनाओं के विस्तार के लिए दान देने का आह्वान किया था। शेख हसीना शासन के पतन के बाद आइएसआइ ने भारत की सीमा से लगे देशों में 'अड्डे' स्थापित करने का लाभ उठाया है।

इजरायल-हमास युद्ध में 60 हजार से अधिक फलस्तीनी मारे गए

- गाजा पट्टी के 90 प्रतिशत आबादी को विस्थापित होना पड़ा
- भयावह मानवीय संकट, विशेषज्ञों ने दी अकाल की चेतावनी

गाजा पट्टी, एपी : इजरायल और हमास के बीच 21 महीने से जारी युद्ध में 60 हजार से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सात अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद से मृतकों की संख्या 60,034 हो गई है तथा 145,870 लोग घायल हुए हैं। उसने यह नहीं बताया कि इन मृतकों में कितने आम नागरिक या आतंकवादी हैं।

मंत्रालय ने बताया कि मृतकों में करीब आधी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य स्वतंत्र विशेषज्ञ इसके आंकड़ों को हताहतों की सबसे विश्वसनीय संख्या मानते हैं। इजरायल के आक्रमण ने गाजा के विशाल क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है, लगभग 90 प्रतिशत आबादी को विस्थापित होना पड़ा है और गाजा में भयावह मानवीय संकट पैदा हो गया है, जिसके कारण विशेषज्ञों ने अकाल की चेतावनी दी है।

इस बीच खाद्य संकटों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण ने कहा कि इस समय गाजा पट्टी में भुखमरी की सबसे खराब स्थिति उत्पन्न हो रही है और यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो इससे बड़ी संख्या में लोगों के जान गंवाने की आशंका है। गाजा से कुपोषित बच्चों की तस्वीरें सामने आने और वहां भुखमरी से जुड़ी घटनाओं की खबरों के बीच इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन ने मंगलवार को यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह चेतावनी एक खतरे की घंटी है। इजरायल ने हाल के दिनों में गाजा में खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई नए कदमों की घोषणा की है। हालांकि, सहायता समूहों का कहना है कि इन उपायों का तत्काल कोई खास असर नहीं हुआ है।

गाजा पट्टी में जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही

गाजा में सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। भूखे फलस्तीनियों तक सुरक्षित रूप से भोजन पहुंचाना लगभग असंभव हो गया है। वहां पहुंचने वाली सीमित सहायता की कालाबाजारी शुरू हो गई है। व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की जा रही है और खाद्य सामग्रियों को अत्यधिक कीमतों पर बेचा जा रहा है। यहां एक किलो आटे की कीमत 60 डालर और एक किलो दाल की कीमत 35 डालर तक पहुंच गई है। यह उस इलाके के ज्यादातर निवासियों की पहुंच से बाहर है, जिसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि वहां अकाल का खतरा मंडरा रहा है। अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण इस सप्ताह के अंत में इजरायल द्वारा अधिक सहायता पहुंचाने के निर्णय से कीमतों में कुछ कमी आई है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है।

यूक्रेन पर रूसी हमले में गई 17 कैदियों समेत 22 की जान

- डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद रूस ने किया हमला
- यूक्रेन के जेल और अस्पताल पर दागे बैलिस्टिक मिसाइल

रूसी हमले के बाद यूक्रेन के जापोरिज्जिया क्षेत्र के विलेंके में विलेंकिव्स्का सुधार कालोनी की एक नष्ट हुई इमारत को दिखाया गया है। एएफपी

कीव, एपी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद रूस यूक्रेन में तबाही मचाने से पीछे नहीं हट रहा है। बीती रात रूस ने एक जेल और अस्पताल पर ग्लाइड बम और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के जपोरिज्जिया इलाके में एक जेल पर रूस ने ग्लाइड बमों से हमला किया। यहां 17 कैदियों की मौत हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि मध्य यूक्रेन के नीपर क्षेत्र में रूसी मिसाइलों ने एक तीन मंजिला इमारत को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया और एक प्रसूति अस्पताल और एक अस्पताल वार्ड सहित आसपास की चिकित्सा सुविधाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले में चार लोग मारे गए और आठ घायल हुए हैं, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है जिसकी हालत गंभीर है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की कहा कि रूस ने 73 शहरों, गांवों और कस्बों पर हमले किए जिनमें 22 लोगों की जान गई है। सोमवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस की 50 दिनों की समय सीमा खत्म हो रही है। अगले 10 से 12 दिनों में पुतिन को युद्धविराम करना होगा। बीते दिनों स्काटलैंड दौरे के वक्त ट्रंप ने कहा था कि वह पुतिन की ओर से निराश हैं। वहीं ट्रंप की डेडलाइन वाले कदम की जेलेंस्की ने तारीफ की। हालांकि, पुतिन के एक शीर्ष सहयोगी ने ट्रंप को रूस के साथ अल्टीमेटम गेम खेलने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि रूस इजरायल या ईरान नहीं है।

इटली में वाल्मीकि की प्रतिमा का अनावरण

रोम, आइएएनएस : इटली के कैंपोरोटोंडो में संस्कृत में महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की एक प्रतिमा का अनावरण इटली में भारत की राजदूत वाणी राव और मेयर मास्सिमिलियानो मिकुच्ची ने किया है। यह प्रतिमा भारत सरकार की ओर से भेंट की गई है।

भारत के दूतावास ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'भारत सरकार की ओर से भेंट की गई महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा को समारोह में भेंट किया गया जिसमें इटली के उप मिशन प्रमुख (डीसीएम) अमराराम गुर्जर समेत वाल्मीकि समुदाय के लोग भी शामिल थे। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने 'रामायण के माध्यम से दुनिया को जोड़ने' की पहल का समर्थन किया है।'' भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पहल 'रामायण के माध्यम से दुनिया को जोड़ना' के तहत कहा गया कि रामायण सीमाओं को पार करती है और दुनिया भर के लोगों को एकजुट करती है। परिषद ने कहा कि भारत व इटली प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनका समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है।

भारत में सहकारी संस्थाएं अब नवाचार और आत्मनिर्भरता का माध्यम : अमित शाह

- केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का संयुक्त राष्ट्र को संदेश
- कहा-भारत में सहकारिता जीवंत व सामुदायिक-प्रेरित प्रणाली

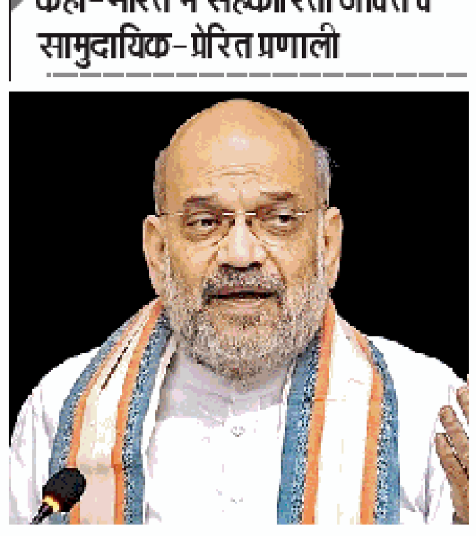

अमित शाह। फाइल

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में सहकारी संस्थाएं अपनी पारंपरिक सीमाओं से परे बढ़ चुकी हैं और अब डिजिटल सेवाओं, ऊर्जा और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में नवाचार और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन गई हैं।

शाह ने सोमवार को 'सहकारी और सतत विकासः गति बनाए रखना और नए रास्तों की खोज' विषय पर एक विशेष स्मारक कार्यक्रम में पूर्व-रिकार्डेड वीडियो संदेश में कहा, 'भारत में सहकारिता एक जीवंत और सामुदायिक-प्रेरित प्रणाली है जो कृषि से लेकर वित्त, उपभोग से लेकर निर्माण और ग्रामीण सशक्तिकरण से लेकर डिजिटल समावेशन तक आपसी सहयोग और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से हर क्षेत्र को समाहित करती है। इसकी अनूठी ताकत इस तथ्य में निहित है कि यह स्थानीय स्तर पर लाभ प्रदान करती है, जबकि ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में सम्मानजनक आजीविका प्रदान करने का एक शक्तिशाली माध्यम बन जाती है।'

शाह ने कहा कि कार्यक्रम का विषय यह दर्शाता है कि सहकारिता का विचार न केवल आज की आधुनिक दुनिया में प्रासंगिक है, बल्कि सतत और समावेशी विकास के लिए आवश्यक भी है।

भारत में सहकारी संस्थाएं अब अपनी पारंपरिक सीमाओं से परे बढ़ चुकी हैं व डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, ऊर्जा, जैविक खेती व वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में नवाचार और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन गई हैं। तकनीकी नवाचार आज सहकारी संस्थाओं को अधिक समावेशी बना रहा है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना जुलाई, 2021 में की गई थी और अमित शाह देश के पहले सहकारिता मंत्री बने। उसके बाद इसका विस्तार होता गया।

देश-दुनिया की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

ब्रिटेन की उड़ान में हंगामा करने पर भारतीय मूल के व्यक्ति पर मामला दर्ज

लंदन, प्रेट्र: लंदन के ल्यूटन हवाई अड्डे से ग्लासगो जाने वाली उड़ान में हंगामा करने और विमान की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में भारतीय मूल के 41 वर्षीय एक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपित अभय देवदास नायक को रविवार सुबह ग्लासगो में ईजीजेट की उड़ान के उतरने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को पेस्ली शेरिफ कोर्ट में पेश होने के दौरान आरोपित ने न तो दोषी और न ही निर्दोष होने की कोई दलील दी।

देवदास नायक लंदन के निकट बेडफोर्डशायर के लूटन का निवासी है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में आरोपित को ''अमेरिका को मौत, ट्रंप को मौत'' और ''अल्लाहु अकबर'' चिल्लाते हुए दिखाया गया है।

इस मामले में स्काटलैंड पुलिस ने कहा कि इसमें कोई और शामिल नहीं था। आनलाइन प्रसारित वीडियो की आतंकवाद निरोधक अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।

चीन में भारी बारिश व बाढ़ से 38 की मौत

चीन के बीजिंग के मियुन जिले में मंगलवार को भारी बारिश के बाद जलमग्न गांव के घरों और अन्य इमारतों का ड्रोन से लिया गया दृश्य। रायटर

बीजिंग, आइएएनएस: चीन में मूसलाधार बारिश ने भीषण तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश के कारण 80 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इन 38 मृतकों में से अकेले बीजिंग में 30 लोगों की मौत हुई है, जबकि हेबेई प्रांत में भूस्खलन की चपेट में आने से आठ लोगों की जान चली गई। इलाके में दर्जनों सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और 136 गांवों की बिजली काट दी गई है।

मंगलवार को बारिश की रफ्तार कम होने की वजह से रेड अलर्ट को वापस ले लिया गया है। हालांकि, मौसम विभाग ने दोपहर और शाम के समय फिर से बारिश की संभावना जताई है। साथ ही, मेंटौगौ जिले में मंगलवार सुबह 8 बजे तक 15,195 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि यहां के सभी 19 पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया है। पिंगगू जिले में 12,800 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। यहां 40 आपातकालीन शेल्टर बनाए गए हैं, जिनमें स्कूल, जिम, होटल और पंचायत भवन शामिल हैं।

रूस ने यूक्रेनी ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद किया

न्यूयार्क टाइम्स से

- पिछले महीने से अधिकारी देश के विभिन्न हिस्सों में बंद कर रहे नेटवर्क

मास्को : कात्या के फोन ने अचानक सेंट पीटर्सबर्ग से मास्को जाने के दौरान जरूरी चीजे मुहैया कराने से इन्कार कर दिया। मैप, बैंकिंग, टोल भुगतान और ईंधन खरीदने जैसी चीजों के लिए उनके एप बंद हो गए थे। इसको लेकर कोई चेतावनी नहीं थी। कोई संकेत नहीं था कि यह रुकावट कितने लोगों को प्रभावित कर रही थी। कोई अंदाजा नहीं था कि यह स्थिति कब तक रहेगी? लेकिन, यह कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी। यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण रूस के मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क में बार-बार ब्लैकआउट हो रहा है। पिछले महीने से अधिकारी देश के विभिन्न हिस्सों में हर दिन घंटों तक इन नेटवर्कों को बंद कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यूक्रेनी ड्रोनों के हमलों को विफल करना है, जिनके बारे में विश्लेषकों का कहना है कि उन्होंने नेविगेशन के लिए मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। यह उस देश में एक बड़ा बदलाव है, जहां स्मार्ट फोन ही एकमात्र आनलाइन पहुंच प्रदान करते हैं। सरकार टैक्स रिटर्न दाखिल करने और नौकरियों के लिए आवेदन करने सहित कई आनलाइन सेवाओं का प्रचार करती है। पुतिन ने दावा किया था कि रूस आनलाइन सेवा में कई अन्य देशों से एक कदम आगे है।

न्यूयार्क की इमारत में गोलीबारी से पांच की मौत

- हमलावर ने चार लोगों को गोलीमार कर खुद की भी जान ली
- मरने वालों में बांग्लादेशी आव्रजक पुलिस अफसर भी शामिल

इटली के कैंपोरोटोंडो में महर्षि वाल्मीकि की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। इंटरनेट मीडिया

न्यूयार्क, एपी : अमेरिका के न्यूयार्क सिटी में मैनहटन के बीचोंबीच स्थित एक 44 मंजिला इमारत की 33वीं मंजिल पर स्थित एक कार्यालय में एक हमलावर ने अंधाधुंध गोलीबारी की। उसने इस हमले में एक पुलिस अफसर समेत चार लोगों की हत्या कर दी और फिर खुद भी सीने में गोली मारकर अपनी जान दे दी। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात वाली इमारत में कई बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं।

सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि बंदूकधारी संदिग्ध हमलावर की पहचान नेवादा के शेन तामुरा के रूप में की गई है। पुलिस अधिकारियों को उसके कपड़ों से लास वेगास का एक परमिट मिला है। पुलिस का कहना है कि हमलावर शेन तामुरा एम4 रायफल लेकर लिफ्ट से सीधे 33वीं मंजिल पर गया और वहां की लाबी में उसने बांग्लादेशी मूल के पुलिस अफसर दारुल इस्लाम को गोली मारी और फिर एक महिला पर गोली चलाई। इसके बाद रियल इस्टेट कंपनी के दफ्तर में अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए खुद को भी गोली मार ली। न्यूयार्क के फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि आपातकालीन दल को पार्क एवेन्यू कार्यालय भवन में शाम 6:30 बजे किसी के गोली लगने की सूचना पर बुलाया गया। इस बिल्डिंग में 11.5 खरब डालर की संपत्ति की देखरेख करने वाली कंपनी ब्लैकस्टोन और आयरलैंड के महावाणिज्य दूतावास के कार्यालय समेत अमेरिका की कुछ प्रमुख वित्तीय कंपनियों और नेशनल फुटबाल लीग का आफिस है। यह बहुमंजिली इमारत मिडटाउन के एक व्यस्त क्षेत्र में है, जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल से थोड़ी दूरी पर है। न्यूयार्क के मेयर एरिक एडम्स ने बताया कि बांग्लादेशी मूल के पुलिस अफसर दारुल इस्लाम (36) ने लोगों को बचाते हुए अपनी जान दे दी। उनके दो बच्चे हैं और पत्नी मौजूदा समय में गर्भवती हैं।

हस्तकलाओं की पहचान

पेरिस फैशन वीक में चर्चा में रहा 1.73 करोड़ रुपये का लखनवी मुकैश कढ़ाई वाला कोट, लखनऊ के कारीगारों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही

कारीगर 'गुमनाम', दुनिया में मुकैश कढ़ाई का नाम

महेन्द्र पाण्डेय ● जागरण

लखनऊ: चिकनकारी, जरदोजी हो या फिर मुकैश कढ़ाई, लखनऊ की इन हस्तकलाओं की पहचान पूरी दुनिया में है। पिछले वर्ष हजरतगंज में बनी चिकन की एक साड़ी दुबई में 21 लाख रुपये में बिकी थी। हाल ही में पेरिस फैशन वीक में लखनवी मुकैश कढ़ाई वाला कोट दो लाख डालर (लगभग 1.73 करोड़) में बिका। इस कोट को बनाने वाले लखनऊ के कारीगारों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही, लेकिन वे 'गुमनाम' ही रहे। उन्हें इसका श्रेय नहीं दिया गया। हाथ से बुने इस कोट का इतना मूल्य मिलेगा, कारीगरों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा।

मुकैश कढ़ाई चिकनकारी की तरह मुगलों के समय लखनऊ में पनपी। उस दौर में धातुओं के तारों से कपड़ों पर फूल-पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी। नवाब विशेष रूप से सोने और चांदी के तारों से की गई मुकैश कढ़ाई वाले परिधान पहनते थे। यह कला पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती गई। सोना-चांदी महंगा हुआ तो उसकी जगह स्टील का उपयोग किया जाने लगा। मुकैश के जानकार राजीव महेंद्रू बताते हैं कि यह कढ़ाई आज भी चिकनकारी की तरह की जाती है। इसकी डिजाइन में छोटे-छोटे बिंदु बनाए जाते हैं, जिन्हें फर्दी कहते हैं। इसमें जाली, टीकी, फर्दी-कानदानी, बादला वर्क, उरमा और रिंग भी बनाई जाती है। खाली मुकैश की डिजाइन तो की ही जाती है। इसमें फ्यूजन भी किया जाता है।

मुकैश वर्क की हो रही चर्चा।

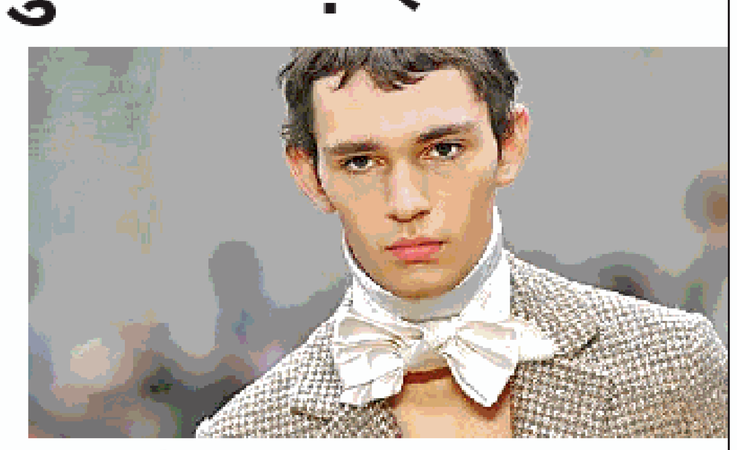

पेरिस फैशन वीक में मुकैश कढ़ाई वाला यह कोट दो लाख डालर (लगभग 1.73 करोड़ रुपये) प्रदर्शित किया गया। इंटरनेट मीडिया

सलवार-कमीज से लेकर कोट तक पर मुकैश कढ़ाई

मुकैश कढ़ाई में पतले धातु के धागों को घुमाकर पूरे कपड़े पर पैटर्न बनाया जाता है। सबसे आम पैटर्न डाट्स का होता है। इस प्रकार की कढ़ाई साड़ी और सलवार-कमीज से लेकर शर्ट, कुर्ती और कोट आदि पर की जाती है। पहले जहां शुद्ध मुकैश वर्क वाली साड़ियां विशिष्ट मानी जाती थीं, वहीं अब मुकैश को चिकनकारी का पूरक माना जाता है। चिकनकारी वाले परिधान की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस कढ़ाई का इस्तेमाल पहले भी किया जाता रहा है और आज भी किया जाता है। अक्सर भारी कढ़ाई वाले चिकन परिधानों में मुकैश वर्क किया जाता है।

> मुकैश के कारीगर को कढ़ाई का सीधे फायदा नहीं होता, क्योंकि उन्हें काम किसी और के द्वारा मिलता है। वह बस काम करके मेहनताना ले लेते हैं। कारीगर इसलिए भी गुमनाम रहते हैं, क्योंकि हम अपनी कला को ठीक से भुना नहीं पा रहे हैं। हमें मुकैश सहित अन्य हस्तशिल्प के प्रति देश-विदेश में जागरुकता रैली निकाली जानी चाहिए। कारीगरों के काम की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। **-राजीव महेंद्रू, उपाध्यक्ष, लखनऊ चिकन एंड हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन**

****

राष्ट्रीय फलक

जम्मू में बुजुर्ग को थार से रौंदने वाले छात्र के पास नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस

- यातायात विभाग ने थार की आरसी निलंबित और वाहन को किया ब्लैकलिस्ट

जागरण संवाददाता, जम्मू

शहर के गांधीनगर क्षेत्र में बुजुर्ग को थार से कुचलने का आरोपित इंजीनियरिंग छात्र मनन आनंद अभी फरार है। जांच में यह सामने आया है कि आरोपित के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। वहीं, यातायात विभाग ने जम्मू पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आरोपित की थार कार की आरसी (पंजीकरण प्रमाणपत्र) को निलंबित कर वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। थार आरोपित के पिता राजेंद्र आनंद के नाम पर है। वह ठेकेदारी का कार्य करते हैं। आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह ने पुष्टि की कि वाहन चालक के पास लाइसेंस नहीं था।

रविवार को र थार ने वाहनों को ओवरटेक करते हुए बुजुर्ग स्कूटी सवार को टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद थार सवार और भड़क उठा और उसने वाहन को बैक गियर में तेजी से लाकर संभलने का प्रयास कर बुजुर्ग को कुचल मार दी। सीसीटीवी में दिखा कि टक्कर मारने के बाद थार सवार वाहन से बाहर निकला और सड़क पर गिरे बुजुर्ग को गालियां निकालनी आरंभ कर दीं। उसके बाद वह थार लेकर फरार हो गया।

> घटना में शामिल थार गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। थार के मालिक से पूछताछ की जा रही है, जबकि चालक अभी फरार है। - अजय शर्मा, एसपी साउथ

आखिरी टेस्ट से पहले ओवल में मचा बवाल

ज्यादा हस्तक्षेप करने पर ओवल के मुख्य मैदानकर्मी फोर्टिस को भारतीय कोच गंभीर ने लगाई लताड़

गंभीर पिच देखने पहुंचे तो मैदान कर्मी फोर्टिस ने खराब व्यवहार किया ● एक्स

वहीं मुख्य मैदान कर्मी ली फोर्टिस पिच पर खड़े होकर बात करते नजर आए ● जागरण

अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच से पहले मंगलवार को भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने ओवल स्टेडियम के मुख्य मैदान कर्मी ली फोर्टिस को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि आप मैदानकर्मी हैं, हमें ये मत बताएं कि हमें क्या करना है। सीरीज में 1-2 से पीछे चल रही भारतीय टीम को गुरुवार से यहां पर इंग्लैंड के विरुद्ध आखिरी मुकाबला खेलना है। भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज 2-2 से ड्रा करा सकती है।

मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट ड्रा कराने के बाद सीरीज को बचाए रखने के लिए लंदन पहुंची भारतीय टीम मंगलवार को यहां वैकल्पिक अभ्यास करने पहुंची थी। इंग्लैंड टीम के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम और भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर व बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक लगभग एक समय ही पिच देखने पहुंचे। ली मैकुलम को तो आराम से पिच दिखा रहे थे लेकिन भारतीय कोच को लेकर उनका व्यवहार ठीक नहीं था। इसके बाद भारतीय टीम मैदान में ही स्क्वायर (मुख्य पिच के आसपास का एरिया) के पास बनी अभ्यास पिच में नेट प्रेक्टिस करने लगी। फोर्टिस ने तब जाकर भारतीय खिलाड़ियों से कहा कि स्क्वायर से ढाई मीटर दूर रहें।

भारत के सहयोगी स्टाफ ने ली को कहा कि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराई गई तीन अभ्यास पिचों के आसपास के क्षेत्र से दूर रहना मुश्किल है। यही नहीं इसके बाद जब सहयोगी स्टाफ भारतीय टीम के लिए पानी और एनर्जी ड्रिंके से भरा कूलिंग बाक्स लेकर आ रहा था तो फिर ली उनको कहने लगे कि ये इधर से मत ले जाओ जबकि उसको ले जाने के लिए यही रास्ता था। इस पर गंभीर भड़क गए। गंभीर ने सीधे फोर्टिस को अंगुली दिखाते हुए कहा कि यह कोई एंटीक नहीं है। यह सिर्फ एक क्रिकेट पिच है। आप सिर्फ मैदानकर्मी हैं और हमें यह मत बताएं कि हमें अभ्यास कैसे करना है। जब इस बारे में फोर्टिस से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने गंभीर को लेकर कहा कि क्या ये छोटी-छोटी बात पर चिढ़ जाने वाले व्यक्ति हैं? क्या वह सही आदमी हैं? मैं इससे पहले कभी गंभीर से मिला नहीं। बड़ा मैच होने वाला है, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप उनसे पता कीजिए कि यहां क्या हुआ? आप लोगों ने देखा है कि यहां क्या हुआ है?

इसके बाद प्रेस कांफ्रेंस करने आए भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा कि उन्हें पिच से एक निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाना अजीब लगा जबकि हमने स्पाइक्स नहीं पहने थे। जब गंभीर और मैं पिच को देखने गए, तो ग्राउंड स्टाफ के एक सदस्य ने कहा कि कम से कम 2.5 मीटर दूर रहो, जो थोड़ा आश्चर्यजनक था क्योंकि यह पिच है। एक दिन बाद इसमें मैच शुरू होगा। यह पांच दिवसीय टेस्ट होगा, और हम अपने जागर्स पहनकर खड़े थे, इसलिए हमें थोड़ा अजीब लगा। ग्राउंड्समैन ने कहा कि हम साइड पिच (जहां पर शार्ट लेग खड़ा होता है) पर घास बड़ी करना चाहते हैं, अब पता नहीं वह एक दिन में कितनी घास उगा लेते। हम बस उस विकेट को देख रहे थे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

कोटक ने संकेत दिया कि फोर्टिस के बातचीत के लहजे की वजह से गुस्सा भड़क गया होगा। यह एक क्रिकेट पिच है। यह कोई 200 साल पुरानी नहीं है जो इसे तोड़ा नहीं जा सकता। फोर्टिस द्वारा गंभीर को चिड़चिड़ा और बदमिजाज कहने पर कोटक ने कहा कि मैं वास्तव में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि यह उनकी राय है और इस दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है। लेकिन मुझे लगता है कि वहां टेस्ट मैच के ठीक एक दिन बाद रबर स्पाइक वाले विकेट को देखकर कुछ भी गलत नहीं है। क्यूरेटर को भी यह समझने की जरूरत है कि वह जिनसे बात कर रहे हैं, वे बेहद कुशल और बुद्धिमान लोग हैं। अगर आप अभी उस मैदान पर जाएं, जहां हमने अभ्यास किया था, तो आपको आउटफील्ड में किसी गेंदबाज के स्पाइक्स के निशान भी नहीं दिखाई देंगे। हम स्प्रे करते रहते हैं। मुख्य कोच की तरफ से कहा जाता है कि हम कोशिश करें कि मैदान को नुकसान न पहुंचे इसलिए जब आप बहुत बुद्धिमान और उच्च कुशल लोगों के साथ काम कर रहे हों तो आप सुरक्षात्मक हो सकते हैं लेकिन आपको घमंडी नहीं लगना चाहिए।

मैकुलम और इंग्लैंड पुरुष टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर राब की के पिच को देखने पर क्या फोर्टिस ने इसी तरह का व्यवहार किया था, पर कोटक ने कहा कि हमारे सामने उन्होंने उन लोगों को कुछ नहीं कहा था। कोई आधिकारिक शिकायत करने पर उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। जब हमारा सहयोगी स्टाफ कूलिंग बाक्स लेकर आ रहा था तो रोलर पर बैठे फोर्टिस ने चिल्लाकर कहा कि इसे वहां न ले जाएं। अब मेरे हिसाब से उस कूलिंग बाक्स का वजन 10 किलो होगा। वहां पर 70-80 किलो के खिलाड़ी टहल रहे तब कुछ नहीं हो रहा तो उस बाक्स से क्या होगा। सारा सहयोगी स्टाफ मुख्य कोच के अधीन आता है। इसके बाद गंभीर को बोलने पर मजबूर होना पड़ा। गंभीर ने कहा कि सहयोगी स्टाफ से इस तरह बात मत करें। पिच के लिए पजेसिव व प्रोटेक्टिव होना अच्छा है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। सच बताऊं तो ओवल आने से पहले ही टीम के ज्यादातर लोग जानते थे कि इन क्यूरेटर के साथ काम करना आसान नहीं होगा। मुझे यकीन है कि आप भी इस बात से वाकिफ होंगे।

फोर्टिस पहले भी कर चुके हैं ऐसा व्यवहार : मालूम हो कि जब भारतीय महिला टीम हाल में ओवल में मैच खेलने आई थी तो उनके साथ भी फोर्टिस ने इसी तरह का व्यवहार किया था। हालांकि यह वही फोर्टिस हैं जिन्हें इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड से पिछले तीन साल से सर्वश्रेष्ठ बहुदिनी पिच (टेस्ट व काउंटी) बनाने का अवार्ड मिल रहा है।

दो मैचों में इंग्लैंड के 20 विकेट नहीं ले पाए हैं भारत के गेंदबाज

आलराउंडर और मुख्य गेंदबाज के बीच में झूलती भारतीय टीम

अभिषेक त्रिपाठी ● जागरण

मैनचेस्टर: भारतीय टीम ने पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में अधिकतर मैचों में बल्लेबाजी लाइनअप को लंबा करने के लिए आलराउंडरों पर भरोसा जताया है लेकिन सीरीज का रिजल्ट फिलहाल उसके पक्ष में नहीं है। भारतीय टीम लीड्स और मैनचेस्टर में 20-20 विकेट नहीं ले सकी। उसे दोनों टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा। इसका मुख्य कारण उसका रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर जैसे आलराउंडरों पर भरोसा जताना है। इन चारों ने मिलकर इस सीरीज में कुल 19 विकेट लिए हैं जिसमें जडेजा ने चार मैच में सात, वाशिंगटन ने तीन मैच में सात, नीतीश ने दो मैच में तीन और शार्दुल ने दो मैच में दो विकेट लिए हैं। इन चारों ने अब तक गेंद से मैच जिताऊ प्रदर्शन नहीं किया है। जडेजा और वाशिंगटन ने भले ही बल्ले से पिछला मैच बचाया हो लेकिन भारतीय टीम प्रबंधन को यह सोचना पड़ेगा कि 650 से ज्यादा रन अगर विपक्षी टीम बना लेगी तो वह मैच नहीं जीत पाएंगे।

अब देखना है कि भारतीय टीम इस मैच को जीतने के लिए 20 विकेट लेने पर फोकस करती है या अपनी पुरानी रणनीति पर चलती है। हालांकि अगर मंगलवार को हुए अभ्यास सत्र, वर्कलोड और टीम संयोजन को देखें तो आकाश दीप, कुलदीप और अर्शदीप में से दो या तीनों गेंदबाजों गुरुवार से ओवल स्टेडियम में शुरू होने वाले पांचवें टेस्ट मैच में मौका देना चाहिए। पिच पर घास भी दिखाई दे रही है। भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा कि मैनचेस्टर को छोड़कर बाकी तीनों जगह लीड्स, लाड्र्स और बर्मिंघम के विकेट में घास थी। यहां पर भी घास है। पिच में थोड़ी नमी है।

कुलदीप यादव ● प्रेट्र

बुमराह को विश्राम, ध्रुव खेलेंगे: जसप्रीत बुमराह ओवल टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। बीसीसीआइ की मेडिकल टीम के अनुसार, बुमराह के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि यह पहले से ही तय था कि बुमराह पांच में से किन्हीं तीन टेस्ट मैचों में खेलेंगे। पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच में विश्राम दिया गया था, लेकिन लाड्र्स में हार के बाद टीम प्रबंधन ने उन्हें मैनचेस्टर में चौथे मैच में उतारा था। वहीं, बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लगातार चार टेस्ट मैच खेलने को लेकर उन्होंने कहा कि सिर्फ एक नहीं, सभी गेंदबाजों का कार्यभार प्रबंधन किया जाता है। अगर मैं आपको जल्दी से बताऊं तो टेस्ट सीरीज से पहले अगर कोई गेंदबाज हर हफ्ते एक निश्चित संख्या में ओवर डालता है और टेस्ट में वह उससे ज्यादा ओवर डालता है तो फिर उसके कार्यभार को देखने वाले डेटा में उछाल आएगा। अगर कोई गेंदबाज हर हफ्ते 30 ओवर डाल रहा है और अचानक पहली पारी में वह 35 ओवर डाल देता है, तो यह उसके कार्यभार के आंकड़ों में उछाल आएगा। सिराज जितने ओवर अभ्यास के समय करते हों, जरूरी नहीं कि मैच में वह उससे ज्यादा डाल रहे हों। अगर सिराज को उनका शरीर थका हुआ लगता है तो वह या फिजियो खुद इस बारे में बताएंगे। वहीं यह तय है कि चोटिल विकेटकीपर रिषभ पंत की जगह ध्रुव जुरैल खेलेंगे। कोटक ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि ध्रुव एक असाधारण प्रतिभा है। वह बहुत अच्छे विकेटकीपर हैं जो अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं। जडेजा, सुंदर के अलावा कुलदीप को खिलाने को लेकर कोटक ने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि उन्होंने आलराउंडरों पर फोकस के कारण 20 विकेट नहीं ले पाने के सवाल का जवाब देते हुए कोटक ने कहा कि आपको मैच जीतने के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों का संतुलन देखना होता है। जैसे 20 विकेट लेने की जरूरत है, उसी तरह 550-600 रन बनाना भी जरूरी है। हमने बर्मिंघम टेस्ट इसलिए जीता क्योंकि हमने उतने रन बनाए थे। तो। अगर हम गेंदबाजी पर ज्यादा ध्यान दें और बल्लेबाजी कम करें तो आलराउंडर भी हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विकेट कैसा दिखता है। कप्तान, कोच और टीम प्रबंधन को लगेगा कि गेंदबाज बढ़ाना फायदेमंद है तो गेंदबाज जरूर बढ़ेंगे। अगर बल्लेबाज की संख्या बढ़ाना फायदेमंद है, तो वह भी हो सकता है। लेकिन एक बात है जब आप पांच गेंदबाजों के साथ खेलते हैं, तो सभी गेंदबाज कम गेंदबाजी करते हैं।

खेल डायरी

दिव्या मानसिक दृढ़ता से बनीं विजेता : पोल्गर

नई दिल्ली, प्रेट्र : महान शतरंज खिलाड़ी सुसैन पोल्गर ने कहा है कि दिव्या देशमुख को मानसिक दृढ़ता और जीत की ललक के कारण विश्व कप खिताब जीतने में मदद मिली। 19 वर्ष की दिव्या ने कोनेरू हंपी को हराकर खिताब जीता। की 88वीं ग्रैंडमास्टर भी बन गई। सुसैन ने कहा कि दिव्या को ऐतिहासिक जीत पर बधाई। शानदार प्रदर्शन। टूर्नामेंट से पहले वह खिताब की प्रबल दावेदार नहीं थी लेकिन उसने मानसिक दृढ़ता और जीतने की ललक से यह किया।

कई मुकाबलों में वह संकट में भी थी और बढत का फायदा नहीं उठा सकी लेकिन उसने जुझारूपन नहीं छोड़ा और इसी दृढता से जीत तक पहुंची।

स्टीपलचेज खिलाड़ी साबले की हुई सर्जरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता 3000 मीटर स्टीपलचेज धावक अविनाश साबले की एसीएल (एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट) सर्जरी हुई है। उन्हें यह चोट इस महीने की शुरुआत में मोनाको डायमंड लीग के दौरान लगी थी। यह भारतीय खिलाड़ी अब सितंबर में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप से बाहर हो गया है। मौजूदा एशियाई चैंपियन और 2023 के हांगझोऊ एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता 30 वर्षीय साबले का मुंबई के एक अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। यह ऑपरेशन जाने-माने सर्जन डा. दिनशा पारदीवाला की देखरेख में किया गया। एसीएल सर्जरी को ठीक होने में आमतौर पर कम से कम छह महीने लगते हैं।

महिला एशियाई कप में भारत को कठिन ड्रा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत को अगले साल आस्ट्रेलिया में होने वाले एएफसी महिला एशियाई कप फुटबाल टूर्नामेंट के ग्रुप सी में जापान, पूर्व चैंपियन चीनी ताइपे और वियतनाम के साथ रखा गया है। एक से 21 मार्च 2026 तक चलने वाले 12 टीमों के इस टूर्नामेंट के लिए ड्रा मंगलवार को सिड्नी टाउन हाल में आयोजित किए गए, जिसमें भारतीय मिडफील्डर संगीता बासफोर तीन ड्रा सहायकों में से एक थीं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली 12 टीमों को चार-चार टीमों के तीन ग्रुप में बांटा गया है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत चार मार्च 2026 को वियतनाम से, सात मार्च को जापान से और फिर 10 मार्च को चीनी ताइपे से भिड़ेगा।

वानखेड़े से लाखों की आइपीएल जर्सियां चोरी

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के 43 वर्षीय सुरक्षा प्रबंधक को आइपीएल की जर्सी चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपित फारूक असलम खान ने बीसीसीआइ के स्टोर से 6.52 लाख रुपये कीमत की 261 जर्सियां चुराई थीं। असलम को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और अब वह जमानत पर है। असलम ने स्टेडियम में बीसीसीआइ के अधिकारिक मर्चेंडाइज स्टोर से इन जर्सियों को चुराकर आनलाइन पर बेचा था। आडिट में इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद 17 जुलाई को बीसीसीआइ अधिकारियों ने मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।

जिंबाब्वे के विरुद्ध टेस्ट कप्तान होंगे सेंटनर

आकलैंड, एएनआइ : मिशेल सेंटनर को जिंबाब्वे के विरुद्ध पहले टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड की पुरुष टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। यह निर्णय नियमित कप्तान टाम लाथम के कंधे की चोट के कारण लिया गया है, जो घरेलू टी20 मैच के दौरान लगी थी। लाथम को एकादश में शामिल होने के लिए फिट नहीं माना गया है, लेकिन वह टीम के साथ बने रहेंगे। उम्मीद है कि वह दूसरे टेस्ट से पहले पूरी फिटनेस हासिल कर लेंगे।

केटी लेडेकी का 1500 मीटर फ्रीस्टाइल में दबदबा कायम

सिंगापुर, प्रेट्र: अमेरिका की केटी लेडेकी ने महिलाओं की 1,500 मीटर फ्रीस्टाइल में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए मंगलवार को विश्व तैराकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। लेडेकी ने 15 मिनट 26.44 सेकेंड का समय लेकर फिर से साबित कर दिया कि महिलाओं की 1500 मीटर फ्रीस्टाइल में उनका कोई सानी नहीं है। इटली की सिमोना क्वाडरेला ने 15:31.79 मिनट के यूरोपीय रिकार्ड के साथ रजत पदक, जबकि आस्ट्रेलिया की लानी पैलिस्टर ने 15:41.18 मिनट के साथ कांस्य पदक जीता।

लेडेकी ने कहा, मुझे यह स्पर्धा बहुत पसंद है। मैंने 2013 में इसी स्पर्धा में अपना पहला विश्व रिकार्ड बनाया था। महिलाओं के 1,500 मीटर के इतिहास में 26 सर्वश्रेष्ठ समय में से 25 लेडेकी के नाम पर दर्ज हैं। मंगलवार को उन्होंने पांचवा सबसे तेज समय निकाला जो 2018 में बनाए गए उनके 15:20.48 के विश्व रिकार्ड से ज्यादा दूर नहीं था। यह विश्व चैंपियनशिप में उनका 22वां स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 28वां पदक था। उन्होंने ओलिंपिक खेलों में नौ स्वर्ण सहित कुल 14 पदक जीते हैं। इस तरह से वह ओलिंपिक और विश्व चैंपियनशिप में कुल मिलाकर 42 पदक जीत चुकी हैं जिनमें 31 स्वर्ण पदक शामिल हैं।

जीत के बाद केटी लेडेकी ● एएफपी

भारतीय तैराकों ने किया निराश: भारतीय तैराकों का निराशाजनक प्रदर्शन मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा, जब कोई भी तैराक अपनी हीट से आगे नहीं बढ़ पाया। साजन प्रकाश 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में 24वें स्थान पर रहे और सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गए। प्रकाश ने 1:59.33 सेकंड का समय लिया। पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल में आर्यन नेहरा 8:21.30 सेकेंड के सामान्य से कम समय के साथ 23वें स्थान पर रहे।

विंडीज दौरे पर अजेय रहा आस्ट्रेलिया

आस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को टेस्ट में 3-0 से हराने के बाद टी-20 में भी 5-0 से हराया, जंपा ने अपने 100वें टी-20 मैच में चटकाए विकेट

सेंट किट्स, एपी: आस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध तीन विकेट से जीत हासिल कर टी-20 सीरीज क्लीन स्वीप किया और अपने वेस्टइंडीज दौरे को 8-0 के रिकार्ड के साथ समाप्त किया। आस्ट्रेलिया ने इस दौरे में 3-0 से टेस्ट सीरीज जीतने के साथ-साथ पहले चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी जीत हासिल की थी। लगातार आठवीं बार टास जीतने के बाद आस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और मेजबान टीम को 20 ओवर पूरे होने से दो गेंद पहले 170 रनों पर आलआउट कर दिया। शिमरोन हेटमायर ने 31 गेंदों में 52 रन और शेरफेन रदरफोर्ड ने 17 गेंदों में 35 रन बनाकर पारी को संभाला, लेकिन यह स्कोर आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था।

बेन ड्वारशुइस ने 41 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि नाथन एलिस ने 32 रन देकर दो और स्पिनर एडम जंपा ने अपने 100वें टी20 अंतरराष्ट्रीय में 20 रन देकर एक विकेट लिया। आस्ट्रेलिया ने 18 गेंद शेष रहते सात विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। मिशेल ओवेन (37) और कैमरून ग्रीन (32) के बीच 63 रनों की साझेदारी ने पारी को स्थिरता दी। एरोन हार्डी 28 रन बनाकर नाबाद रहे। वेस्टइंडीज ने पावरप्ले में आस्ट्रेलिया को संकट में डाल दिया था, जब जेसन होल्डर और अल्जारी जोसेफ ने दो-दो विकेट चटकाए। होल्डर ने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को शून्य पर आउट कर दिया, जब मैक्सवेल ने बाहर जाती गेंद को खेलने की कोशिश की और शार्ट थर्ड मैन पर जेडियाह ब्लेड्स ने कैच लपका। होल्डर ने इसी ओवर में जोश इंग्लिस (10) को भी आउट किया।

जोसेफ ने कप्तान मिशेल मार्श (14 रन) को क्लीन बोल्ड किया, जिससे आस्ट्रेलिया 2.2 ओवर में 29/3 पर पहुंच गया। इसके बाद, छक्कों की बरसात हुई और उन्होंने टिम डेविड (30) को डीप में कैच करवा कर पांचवें ओवर में आस्ट्रेलिया को 60/4 पर पहुंचा दिया।

ट्राफी के साथ आस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी ● एएफपी

8-0 के रिकार्ड के साथ आस्ट्रेलिया ने अपना वेस्टइंडीज दौरा खत्म किया

केकेआर से अलग हुए कोच चंद्रकांत पंडित

नई दिल्ली, जेएनएन : आइपीएल में तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइटराइडर्स ने तीन सत्र बाद मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित से नाता तोड़ लिया है। पंडित 2022 में केकेआर के मुख्य कोच बने थे और उनकी देखरेख में टीम 2024 में चैंपियन बनी थी। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को कहा, चंद्रकांत पंडित ने नए अवसरों की तलाश करने का फैसला किया है और केकेआर मुख्य कोच के रूप में आगे नहीं बढ़ेंगे। हम उनके अमूल्य योगदान के लिए आभारी हैं, जिसमें केकेआर को 2024 में टाटा आइपीएल चैंपियन बनाना शामिल है। उनके नेतृत्व और अनुशासन ने टीम पर अमिट छाप छोड़ी है। हम उन्हें भविष्य के लिए शुभकामना देते हैं। पंडित के नेतृत्व में केकेआर ने तीन सीजन में 42 में से 22 मैच जीते और 18 हारे और दो मैच बेनतीजा रहे। हालांकि पिछले सत्र में टीम 14 लीग मैचों में से केवल पांच जीतकर आठवें स्थान पर रही थी। केकेआर ने अभी तक पंडित के प्रतिस्थापन की घोषणा नहीं की है।

चंद्रकांत पंडित

टेनिस डायरी

जिनी बुचार्ड ● एपी

बुचार्ड ने टाली विदाई, राडुकानू और ओसाका भी बढ़ीं आगे

मांट्रियल, एपी : कनाडा की टेनिस स्टार जिनी बुचार्ड ने अपने करियर को कम से कम एक और मुकाबले तक बढ़ा दिया है। सोमवार को मांट्रियल में हुए नेशनल बैंक ओपन के पहले दौर में उन्होंने कोलंबिया की एमिलियाना अरांगो को 6-4, 2-6, 6-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। यह उनकी 2023 के बाद पहली डब्ल्यूटीए टूर जीत भी रही और करियर की 300वीं जीत। 31 वर्षीय बुचार्ड ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह अपने होमटाउन टूर्नामेंट के बाद टेनिस से संन्यास लेंगी। लेकिन जीत के बाद उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, 'मैंने अपने परिवार से कहा था कि अगर मैं जीतूंगी, तो संन्यास लेने का फैसला टाल दूंगी। आज कोर्ट पर मैं खुद को फिर से वही 'पुरानी जिनी' महसूस कर रही थी।'

बुचार्ड का अगला मुकाबला 17वीं वरीय बेलिंडा बेंकिक से होगा। वर्तमान में बुचार्ड रैंकिंग में नीचे हैं और वह इस सीजन केवल एक मैच खेल पाई थीं। वह अब ज्यादातर पिकलबाल खेलती हैं। वहीं, एमा राडुकानू ने वाशिंगटन में सेमीफाइनल हारने के दो दिन बाद ही दमदार वापसी करते हुए एलेना गैब्रिएला रुसे को 6-2, 6-4 से हराया। नाओमी ओसाका ने एरियाना आर्सेनो को 6-4, 6-2 से पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया।

सुमित नागल दूसरे दौर में

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल स्पेन के कार्लोस सांचेज जोवर को सीधे सेटों में हराकर मंगलवार को जर्मनी के हेगन में प्लात्जमैन ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए। विश्व रैंकिंग में 307 वें स्थान पर काबिज इस खिलाड़ी ने क्ले कोर्ट पर खेले जा रहे टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में अपने से बेहतर रैंकिंग वाले खिलाड़ी को 6-2, 6-2 से मात दी। नागल के सामने अब बुधवार को एटीपी चैलेंजर स्तर के इस टूर्नामेंट के अंतिम 16 में जर्मनी के साल के नील्स मैकडानल्ड की चुनौती होगी।

भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को सिर्फ 36 मिनट में हराया

सात्विक-चिराग मकाऊ ओपन के दूसरे दौर में

मकाऊ, प्रेट्र: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार भारतीय जोड़ी ने मंगलवार को मलेशिया के लो हैंग यी और एनजी इंग चियोंग पर सीधे गेम में जीत दर्ज करके मकाऊ ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में प्रवेश किया। सात्विक और चिराग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशियाई जोड़ी को केवल 36 मिनट में 21-13, 21-15 से हराया। महिला सिंगल्स में अनमोल खरब और तस्नीम मीर मुख्य ड्रा में पहुंच गईं। अनमोल ने अजरबैजान की कीशा फातिमा अजाहरा को 21-11, 21-13 से, जबकि तस्नीम ने थाईलैंड की टिडाप्रोन क्लेबीसुन को 21-14, 13-21, 21-17 से हराया। त्रीसा जाली और गायत्री गोपीचंद की शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला डबल्स जोड़ी चीनी ताइपे की लिन जियाओ मिन और पेंग यू वेई की जोड़ी से एक घंटे में 21-16, 20-22, 15-21 से हारकर पहले दौर में ही बाहर हो गई। अपूर्वा और साक्षी महिला डबल्स में मलेशिया की गो पेई की और तेओह मेई जिंग से हार गईं।

मैच के दौरान सात्विकसाइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ● बैडमिंटन फोटो

सात्विक-चिराग बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में शीर्ष दस में लौटे

नई दिल्ली, प्रेट्र : एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सात्विकसाइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी बीडब्ल्यूएफ पुरूष डबल्स विश्व रैंकिंग में फिर शीर्ष दस में पहुंच गए। पुरूष सिंगल्स में भारत के शीर्ष खिलाड़ी लक्ष्य सेन 17वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि एचएस प्रणय दो पायदान चढकर 33वें स्थान पर हैं। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा करियर की सर्वश्रेष्ठ 31वीं रैंकिंग पर पहुंच गई। सिंधू 15वें स्थान पर बनी हुई हैं। महिला डबल्स में त्रिसा जाली और गायत्री गोपीचंद 11वें नंबर पर बने हुए हैं, जबकि तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा दो पायदान चढकर 45वें स्थान पर आ गए।

क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

****

बोन-हेल्थ

लगभग 25 वर्ष की उम्र तक हड्डियां विकसित और मजबूत होती हैं। अब बचपन में ही हाथों-पैरों और जोड़ों में दर्द की शिकायत आने लगी है। ऐसे में हड्डियों को कम उम्र से ही स्वस्थ रखने और आगे चलकर आस्टियोपोरोसिस जैसी परेशानियों से बचाने का क्या है तरीका, आइए जानते हैं...

क्यों कमजोर होने लगीं बच्चों की हड्डियां

फोटो : फ्रीपिक

माना जाता है कि जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में जकड़न या कमजोरी की समस्या बढ़ती उम्र में होती है, पर आज स्कूली बच्चों में भी ऐसी समस्याएं देखी जा रही हैं। हाथ-पांव, गर्दन और कमर में दर्द हो या क्रैंप की शिकायतें, बच्चों और किशोरों में भी देखने को मिल रही हैं। बच्चों में ये समस्याएं खराब खानपान, निष्क्रियता और अनियमितता भरी जीवनशैली के कारण हो रही हैं।

डा. दीपक जोशी
निदेशक, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

बचपन से ही सजगता क्यों जरूरी : इसका एक कारण यह है कि बढ़ती उम्र में कैल्शियम, मिनरल्स के साथ विटामिंस की आवश्यकता बढ़ती है। वास्तव में बच्चे स्वस्थ आहार की अपनी कुल जरूरत का 10 प्रतिशत भी नहीं ले पाते। स्क्रीन टाइम का बढ़ना, इनडोर यानी घर या स्कूल के अंदर अधिक समय बिताने के कारण विटामिन-डी की कमी हो रही है। वहीं, खानपान में जंक फूड के बढ़ते चलन के कारण कैल्शियम और विटामिन की भरपाई नहीं हो पाती। यही बच्चे जब वयस्क होते हैं, तो ज्यादातर की आदतें नहीं बदल पातीं। ये आदतें वयस्कों और आगे चलकर 60 की उम्र के बाद गंभीर समस्याओं का कारण बन जाती हैं।

कैल्शियम की उचित मात्रा : बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों से लेकर मांसपेशियां और शरीर के सभी अंगों का विकास हो रहा होता है। ऐसे में शरीर को उचित मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए कैल्शियम एक जरूरी तत्व है, पर क्या हम इस जरूरी तत्व के बारे में सजग हैं? यह सबसे अहम सवाल है। आमतौर पर एक से तीन वर्ष की उम्र तक के बच्चों को रोजाना 700 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, जबकि चार से आठ वर्ष की उम्र के बच्चों को 1000 मिलीग्राम और नौ से 18 साल की उम्र के बच्चों को एक दिन में 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। साथ ही बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि विटामिन डी उचित मात्रा में मिले। यह कैल्शियम अवशोषण के लिए यह बेहद जरूरी है।

केवल दूध से नहीं बनेगी बात : बच्चों को आप पर्याप्त दूध दे भी रहे हैं, तो यह ध्यान रहे कि केवल दूध बच्चों में कैल्शियम की भरपाई नहीं कर सकता। उन्हें कैल्शियम युक्त आहार भी खिलाएं, ताकि उनकी लंबाई अच्छे ढंग से बढ़े। कैल्शियम के लिए बच्चों को बादाम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, बींस, ब्रोकली, टोफू, सूखे अंजीर, संतरा आदि के सेवन के लिए प्रेरित करें।

कैल्शियम की कमी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चिकित्सक की सलाह पर बच्चों को सप्लीमेंट्स भी दिया जा सकता है।

इन बातों का रहे ध्यान

- पढ़ाई या किसी कारण से लंबी सिटिंग के बाद उठकर स्ट्रेचिंग की आदत विकसित करनी चाहिए।
- ज्यादा देर तक गर्दन-कंधे झुकाकर या आधा लेटकर टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर देखने से बचना चाहिए।
- शरीर को डिहाइड्रेट ना होने दें। कम से कम ढाई लीटर पानी का सेवन अवश्य करें।
- डिहाइड्रेट रहने के कारण मांसपेशियों के चोटिल होने की आशंका अधिक रहती है। उनमें क्रैंप व जोड़ों में दर्द की शिकायतें अधिक होती हैं।
- जंक फूड, अस्वस्थ खाद्य के नुकसान के बारे में बच्चों को बताएं, ताकि कैल्शियम और मिनरल्स के सेवन के प्रति वे सचेत हो सकें।
- सोडा, प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ व स्नैक्स का अधिक सेवन ना करें। ये कैल्शियम अवशोषण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
- छोटे बच्चों यानी तीन से पांच साल तक बच्चों में कैल्शियम की कमी है तो चिकित्सक की सलाह पर उन्हें पूरक दवाएं दें।
- 11-16 वर्ष में प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरत बढ़ जाती है। ध्यान नहीं देने पर आगे चलकर अनेक समस्याएं शुरू हो जाती हैं।

बातचीत : सीमा झा

जितनी सक्रियता, उतनी सेहत

आप जितना या जिस रूप में सक्रिय रहते हैं, उसी अनुपात में आपके हड्डियों और मांसपेशियों की सेहत बेहतर होती है। सक्रिय रहकर हड्डियों और मांसपेशियों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो शरीर विटामिन और मिनरल्स खोने लगता है। आप भले पूरक दवाइयां लेकर इनकी भरपाई करना चाहें, पर सक्रियता की कमी से होने वाले नुकसान की भरपाई बहुत मुश्किल है।

कैल्शियम की कमी के लक्षण

- हड्डियों का दर्द और फ्रैक्चर होने की आशंका।
- बच्चों का धीमा विकास।
- दांतों की सड़न, दांत देर से निकलना।
- मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी।
- मूड में उतार-चढ़ाव होना, चिड़चिड़ापन और लगातार थकान रहना।
- रिकेट्स या आस्टियोपोरोसिस की आशंका।

संतुलित आहार का रहे ध्यान

- दूध, पनीर और दही
- ब्रोकली, केल, टोफू, बादाम और विटामिन डी युक्त खाद्य या पौधे-आधारित कैल्शियम
- अंडे, मछली और अन्य विटामिन डी युक्त उत्पादों का सेवन

काम की बात

- हड्डियों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए बचपन से लेकर उम्र के हर पड़ाव पर हड्डियों की मजबूती पर ध्यान देना जरूरी है। हमारा शरीर पुरानी की जगह नई हड्डियों का निर्माण करता रहता है। इसे रीमाडलिंग कहते हैं।
- बचपन, किशोरावस्था से लेकर 20 वर्ष की आयु के मध्य तक हड्डियों का निर्माण तेजी से होता है। इस उम्र तक यदि नियमित कसरत करें तो अधिकतम अस्थि द्रव्यमान (अधिकतम अस्थि घनत्व और शक्ति) प्राप्त कर सकते हैं।
- ज्यादातर हड्डियों का द्रव्यमान 35 साल की उम्र के आसपास अपने चरम पर होता है। इसके बाद हड्डियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। नियमित व्यायाम, पैदल चलने की आदत से हड्डियों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

जीवनशैली

हाथों-पैरों में दर्द का समझें संकेत

अगर हाथ या पैर के किसी हिस्से में लंबे समय से दर्द हो रहा है, तो यह रक्त संचार के अवरुद्ध होने या बैक्टीरिया संक्रमण के कारण हो सकता है। जानते हैं इसके लक्षण और बचाव के जरूरी उपायों के बारे में...

शरीर के किसी भी हिस्से में रक्त संचार का बाधित होना जीवन के लिए जोखिम भरा हो सकता है। दिल की दीवारों में रक्त की सप्लाई कम हो जाने से एंजाइना हो सकता है, उसी तरह हाथों-पैरों में भी एंजाइना होता है। दिल के एंजाइना से हार्ट अटैक की आशंका रहती है, जबकि हाथों-पैरों के एंजाइना में शरीर का वह हिस्सा लगभग मृतप्राय हो जाता है, जिसे सामान्य भाषा में गैंगरीन कहते हैं। ऐसी स्थिति में उसे अलग करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा मरीज की हालत गंभीर हो सकती है।

डा. केके पाण्डेय
वरिष्ठ वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर सर्जन, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली

हाथों-पैरों के दर्द को ना करें नजरअंदाज: धमनियों में रुकावट के कारण अंगों में खून के जरिये पहुंचने वाले आक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे चलने-फिरने या व्यायाम करने से दिल, हाथ या पैर में दर्द महसूस होने लगता है। यह एंजाइना का शुरुआती चरण होता है। दर्द सीने में महसूस हो या हाथों-पैरों में उसकी तुरंत जांच करानी चाहिए।

क्यों होता है दर्द: रक्त वाहिकाओं में रुकावट के कारण एंजाइना का दर्द होता है। इसके पीछे चर्बी, खून का थक्का या कैल्शियम का जमाव हो सकता है। आमतौर पर मधुमेह के चलते धमनियों में चर्बी और कैल्शियम जमा होने की आशंका अधिक होती है। वहीं, धूमपान या तंबाकू के अत्यधिक सेवन से इसका खतरा मंडराता है। सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू में पाया जाने वाला 'निकोटिन' धमनियों की दीवारों में सिकुड़न पैदा करता है। इससे हाथों-पैरों को शुद्ध रक्त की सप्लाई कम हो जाती है और एंजाइना का दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए, मधुमेहग्रस्त और धूमपान करने वालों को एंजाइना की समस्या को लेकर विशेष रूप में सावधान रहना चाहिए। जैसे ही हाथ या पैर में दर्द या झनझनाहट शुरू हो, तो तुरंत किसी डाक्टर से परामर्श करना चाहिए।

कैसे पहचानें एंजाइना के लक्षण

- अगर लिखते समय या कोई काम करते समय हाथों में दर्द अचानक बढ़ जाता हो, तो यह एंजाइना का संकेत हो सकता है।
- चलते हुए दोनों पैरों में दर्द हो और बैठने पर दर्द शांत हो जाए तो यह एंजाइना का सूचक है।
- हाथों-पैरों में लगातार दर्द है और आप धूमपान व तंबाकू के आदी हैं तो समझ जाएं एंजाइना ने अटैक का रूप ले लिया है।
- मधुमेह ग्रस्त हैं और महीनों तक कमर और जांघों में दर्द रहे, तो एंजाइना हो सकता है।
- अगर बैठे रहने या बिस्तर पर आराम करने के बावजूद भी पैरों या टांग में तेज दर्द बना रहता है, तो यह आक्सीजन की कमी और अपर्याप्त रक्त संचार का संकेतक है।
- अगर दर्द के साथ पैर का रंग पीला या हल्का नीला पड़ने लगे, तो यह इंगित करता है कि खून की नलियां बंद हो चुकी हैं। तुरंत इलाज कराना चाहिए।

हाथों-पैरों के दर्द का क्या है उपाय

अगर आपके हाथ और पैर के एंजाइना की समस्या है तो जनरल सर्जन या अस्थि विशेषज्ञ की बजाय वैस्क्युलर या कार्डियोवैस्क्युलर सर्जन से परामर्श लेना बेहतर होता है। सही उपचार नहीं मिलने पर समस्या नियंत्रण से बाहर चली जाएगी। हमेशा ऐसे अस्पताल में जाएं जहां डाप्लर स्टडी, इको कार्डियोग्राम और एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध हो।

एक बात हमेशा याद रखें

धमनियों में अवरोध होने पर एंजियोप्लास्टी कराएं या बाइपास सर्जरी, अगर आपने दिनचर्या नहीं बदली, तो उपचार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाथों-पैरों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए प्रतिदिन पांच से छह किलोमीटर चलना जरूरी है। धूमपान और तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन बंद कर देना चाहिए। वजन और मधुमेह को नियंत्रित रखना चाहिए।

स्त्री स्वास्थ्य

महिलाओं के पैरों का दर्द

रसोई में या लंबे समय तक खड़े रहने से अक्सर पैरों और एड़ियों में दर्द होता है। कई बार सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता। क्या है कारण, कैसे दूर होगा पैरों का दर्द, आइए जानते हैं...

अक्सर कामकाजी महिलाएं पैरों के दर्द की शिकायत लेकर आती हैं। किसी के पैरों के नीचे, तो किसी के टखनों में दर्द रहता है। इसके पीछे कई वजहें होती हैं, जैसे मोटापा, हार्मोंस में बदलाव, मांसपेशियों में खिंचाव, मानसिक तनाव, चोट या पोषक तत्वों की कमी के कारण समस्या हो सकती है।

डा. आकांक्षा रस्तोगी
कंसल्टेंट, इंटरनल मेडिसिन, मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम

क्यों होता है पैरों का दर्द

टेंडोनाइटिस : मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। चोट या सूजन आने से टेंडोनाइटिस हो जाता है। इसकी वजह से पैरों के कई हिस्सों में दर्द रहता है।

साइटिका : तंत्रिका के मार्ग के साथ-साथ फैलते हुए दर्द को साइटिका कहते हैं। जब रीढ़ की हड्डी में हर्निएटेड डिस्क पर दबाव पड़ता है। यह दर्द आमतौर पर साइटिक नर्व के दबने से या प्रभावित होने के कारण होता है।

फाइब्रोमाइलजिया : शरीर के कुछ हिस्सों पर छूने से ही करेंट जैसा दर्द महसूस होता है उसे फाइब्रोमाइलजिया कहते हैं। इसके कुछ टेंडर प्वाइंट्स होते हैं, जिसमें एड़ी और पिंडलियां।

न्यूरोलाजिकल या मस्कुलर पेन : रक्तप्रवाह में कमी के अलावा तनाव भी मांसपेशियों के खिंचाव का कारण है। जब भी आप तनाव में रहती हैं तो आपकी नसें खिंचने लगती हैं। तनाव से बढ़ने वाले कोर्टिसोल और अन्य तनाव हार्मोन पैरों और टखनों से रक्त प्रवाह को दूसरे अंगों तक ले जाते हैं। इससे पैरों और टखनों में आक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं होती और दर्द बढ़ जाता है।

समझें दर्द के कारण

हार्मोनल बदलाव : महिलाओं के शरीर में हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर मासिक धर्म, प्रेग्नेंसी और मेनोपाज के दौरान काफी बदलता है। ये बदलाव नसों और मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं, जिससे पैरों में सूजन, भारीपन और दर्द महसूस होता है। पीरियड्स के पहले या बाद में उनके पैरों में ऐंठन और थकान होती है।

नसों की समस्या (वेरिकोज वेन्स) : कई महिलाओं की नसें उभरकर दिखने लगती हैं, खासकर पिंडलियों के पास। इसे वैरिकोज वेन्स कहते हैं। इसमें नसों में खून जमा होने लगता है जिससे सूजन और दर्द होता है।

पोषक तत्वों की कमी : विटामिन, आयरन और पोटैशियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं। शरीर में खून की मात्रा कम होने लगती है।

स्वास्थ्य की ना हो अनदेखी: महिलाएं हमेशा से ही स्वास्थ्य की अनदेखी करती हैं, जिससे आगे चलकर आस्टियोपोरोसिस हो सकता है। महिलाओं में 20 से 40 वर्ष में रिप्रोडक्टिव क्रियाएं ज्यादा होती हैं, इस दौरान शरीर में काफी बदलाव होते हैं। इसलिए खानपान पर ध्यान देना आवश्यक है।

बातचीत : सुमन अग्रवाल

क्या है समाधान

- पैर, पिंडलियां और टखनों के दर्द से राहत के लिए नमक-पानी में पैर डालकर सिंकाई कर सकती हैं।
- पैरों की अंगुलियों के पीछे एक्युप्रेशर के प्वाइंट्स होते हैं, जिन्हें दबाने से दर्द में आराम मिलता है।
- बाडी स्ट्रेचिंग करने से दर्द कम होता है। सुबह की धूप जरूर लेने का प्रयास करें।
- शरीर को हाइड्रेट रखें। रसीले फल खाएं और पोटैशियम की कमी न होने दें।
- आयरन के स्तर की जांच कराएं और हरी सब्जियां जरूर खाएं।

इस पेज के बारे में अपनी राय और सुझाव भेजें - feature@jagran.com

आज का भविष्यफल : 30 जुलाई, 2025 बुधवार

पं. के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : श्रावण मास शुक्ल पक्ष षष्ठी का राशिफल।
आज का राहुकाल : दोपहर 12 बजे से 01 बजकर 30 मिनट तक।
आज का दिशाशूल : उत्तर
कल का पर्व एवं त्योहार : कल्कि जयंती, शीतला षष्ठी

कल 31 जुलाई, 2025 का पंचांग

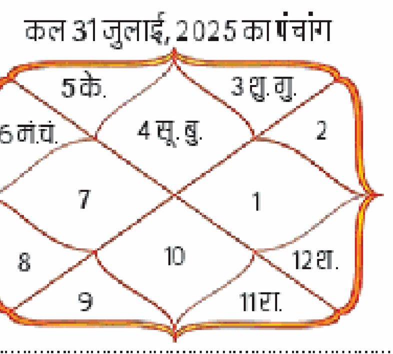

कल का दिशाशूल : दक्षिण
विशेष : गोस्वामी श्री तुलसीदास जयंती
विक्रम संवत 2082 शके 1947 दक्षिणायण, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु श्रावण मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी 28 घंटे 59 मिनट तक तत्पश्चात अष्टमी, चित्रा नक्षत्र 24 घंटे 42 मिनट तक तत्पश्चात स्वाति नक्षत्र, साध्य योग 28 घंटे 32 मिनट तक तत्पश्चात शुभ योग, कन्या में चंद्रमा 11 घंटे 16 मिनट तक तत्पश्चात तुला में।

मेष : रुपये-पैसे के लेनदेन में सावधानी बरतें। धनहानि की आशंका है। आर्थिक मामलों जोखिम न उठाएं।

वृष : पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी।

मिथुन : निजी सुख में व्यवधान आएगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी।

कर्क : पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपके हित में न हो।

सिंह : जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं। झगड़ा विवाद से बचें। चल या अचल संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी।

कन्या : अपनों से तनाव मिल सकता है। वाणी पर संयम का रखें। महिला अधिकारी या पिता का सहयोग मिलेगा।

तुला : शासनसत्ता का सहयोग रहेगा। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। जीविका के क्षेत्र में प्रयास सार्थक होगा।

वृश्चिक : पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। रिश्तों में निकटता आएगी।

धनु : व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। पारिवारिक, कुछ व्यावसायिक समस्या तनाव का कारण रहेगी।

मकर : आर्थिक सुधार होगा। संतान या भाई के कारण कष्ट मिल सकता है लेकिन पिता या मां का सहयोग मिलेगा।

कुंभ : संतान या किसी रिश्तेदार के कारण तनाव मिल सकता है। आर्थिक प्रगति होगी। जीवन सुखमय होगा।

मीन : व्यावसायिक प्रगति होगी। धन, सम्मान यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी।

वर्ग पहेली-3059

■	1	2		■	3	4			■
5	■		■	■	6		■	■	7
	■	8		9		■	10		
11	12	■	■		■			■	
13		14	■	15	16			■	■
■	■	17				■	18	19	20
21	■		■	■		■	■	22	
23			■	24			25	■	
	■	■	26		■	■		■	
■	27				■	28			■

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं :
1 थरथराना, कंप (3)। 3 नाश करना, निर्जन करना (4)। 6 सम्मति, राय, वोट (2)। 8 परित्यक्त (4)। 10 सौगंध (3)। 11 हार, श्रेणी, पंक्ति (2)। 13 रहने का भाव (3)। 15 धीरे-धीरे हाथ फेरना (4)। 17 सिंदूर, एक प्रकार का रत्न (4)। 18 शिव, महादेव (3)। 22 अधिकार (2)। 23 सुख, चैन (3)। 24 बुरा आचरण (4)। 26 आदेश (2)। 27 निबटारा, (4)। 28 गिरफ्त (3)।

ऊपर से नीचे :
2 प्रथम, प्रधान (3)। 3 जो गर्मी पानी नहीं बरसने से पड़ती है (3)। 4 उत्पन्न, बिरादरी (2)। 5 जिसके अंग कोमल हों (4)। 7 जो न थके (3)। 9 राज्य, अमीरी (4)। 10 एक वाद्ययंत्र (4)। 12 लाख, चमड़ा (2)। 14 उपदेश, शिक्षा, सीख (4)। 16 रुक-रुक कर बोलना (4)। 19 नृप, राजा, सम्राट (2)। 20 रूखे स्वभाव का (4)। 21 विशाल, भव्य (3)। 24 बिना ज्ञान का (3)। 25 रक्षा करने वाला (3)। 26 दो बराबर भागों में एक (2)।

कल का हल

1 पा	ग	ल	2 प	न	■	3 गु	म	ना	4 म
ठ	■	■	ल्ला	■	■	■	■	■	दि
शा	■	5 अ	छू	त	■	■	6 पा	■	रा
ला	■	■	ट	■	7 वि	न	य	शी	ल
■	■	■	8 ना	9 जु	क	■	ल	■	य
10 स	■	11 वि	■	12 का	ट	13 ना	■	■	■
14 म	हा	न	त	म	■	म	■	■	15 ग
र	■	ती	■	■	16 पं	डू	क	■	म
भू	■	■	■	■	■	ब	■	■	खा
मिं	मि	या	ना	■	18 खी	ना	क	मा	ना

जागरण सुडोकू-3059

7	1		9		4		8	5
9				3				6
				7	8			
		3	8			7		4
5	7			2	6	1		3
	2		3				6	
			7	4				2
2					3			9
8	4		5	1		6	3	

कल का हल

4	5	6	9	8	1	2	7	3
8	3	1	2	7	4	6	5	9
2	9	7	3	6	5	8	4	1
7	8	3	4	2	6	9	1	5
1	4	9	5	3	8	7	6	2
5	6	2	7	1	9	3	8	4
9	7	5	6	4	3	1	2	8
3	2	8	1	5	7	4	9	6
6	1	4	8	9	2	5	3	7

राष्ट्रीय फलक

चंदौली में मजार के नीचे मिली खंडित मूर्ति, प्रशासन ने कब्जे में लिया

जागरण संवाददाता, चंदौली : बाबा लतीफशाह की मजार के नीचे मिली पत्थर की खंडित मूर्ति को मंगलवार को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों ने इसे सोमवार देर शाम देखा था और प्रशासन को जानकारी दी थी। मूर्ति को कोतवाली परिसर में स्थित मंदिर में रखवा दिया गया है। विधायक कैलाश आचार्य, भाजपा जिलाध्यक्ष काशीनाथ सिंह व नगर चेयरमैन गौरव श्रीवास्तव ने कोतवाली पहुंच कर मूर्ति को देखा।

प्रशासन ने बीएचयू के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में मूर्ति की तस्वीर भेजी। वहां के असिस्टेंट प्रोफेसर स्वतंत्र सिंह ने बताया कि मूर्ति भगवान सूर्य की है। यह गुप्त काल व उत्तर गुप्त काल की प्रतीत हो रही है। उस समय मंदिर के अष्ट दिगपाल की मूर्तियां बलुआ पत्थरों से निर्मित होती थीं। प्राप्त मूर्ति भी इन्हीं दिगपालों में भगवान सूर्य की है। एसडीएम ने बताया कि मजार के नीचे मूर्ति किस तरह पहुंची, इसकी जांच की जा रही है।

2021 से अब तक 50% से ज्यादा बाघों की मौत अभयारण्यों के बाहर हुई

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार, चार वर्ष में हुई 667 बाघों की मौत
- इस अवधि के दौरान 341 यानी 51 प्रतिशत मौतें बाघ अभयारण्यों के बाहर हुईं

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत में 2021 से 2025 तक 50 प्रतिशत से ज्यादा बाघों की मौत संरक्षित अभयारण्यों के बाहर हुई हैं। इनमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के अनुसार, इस अवधि के दौरान 667 बाघों की मौत हुई और इनमें से 341 यानी 51 प्रतिशत मौतें अभयारण्यों के बाहर हुईं।

वर्षवार सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2021 में 129 बाघों की मौत, 2022 में 122, 2023 में 182, 2024 में 126 और 2025 में अब तक 108 बाघों की मौत हुई है। 2021 में अभयारण्यों के बाहर बाघों की मौत की संख्या 64, 2022 में 52, 2023 में 100, 2024 में 65 और 2025 में अब तक 60 थी। महाराष्ट्र में अभयारण्यों के बाहर बाघों की सबसे अधिक 111 मौतें हुईं, उसके बाद मध्य प्रदेश में 90 मौतें हुईं। एनटीसीए के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि 2012 और 2024 के बीच 1,519 बाघों की मृत्यु हुई, और इनमें से 634, यानी 42 प्रतिशत, बाघ अभयारण्यों के बाहर मारे गए।

मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं और नए आंकड़ों में यह संख्या और बढ़ने की संभावना है। लेकिन, बाघों की मौत की दर भी चिंताजनक है। 2025 के पहले छह महीनों में 29 बाघों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में भारत के अनुमानित 3,682 बाघों में से लगभग 30 प्रतिशत अधिसूचित बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 24 देश अंतरराष्ट्रीय बाघ गठबंधन (आइबीसीए) में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। यह गठबंधन भारत के नेतृत्व में बाघों की सात प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक पहल है। इस गठबंधन में वर्तमान में 12 देश - भारत, आर्मेनिया, भूटान, कंबोडिया, इथियोपिया, इस्वातिनी, गिनी, लाइबेरिया, निकारागुआ, रवांडा, सोमालिया और सूरीनाम - सदस्य हैं।

यादव ने कहा कि भारत में बाघ अभयारण्यों की संख्या 2014 में 46 से बढ़कर वर्तमान में 58 हो गई है, जो राष्ट्रीय पशु बाघ संरक्षण के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत सभी बाघ अभयारण्यों में एक लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे।

बठिंडा में बच्चों से भीख मंगवा रहे थे माता-पिता, दो दंपतियों पर केस

जागरण संवाददाता, बठिंडा : पंजाब को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने के लिए शुरू किए गए अभियान जीवनजोत-2 के तहत मंगलवार को राज्य के 20 जिलों में छापेमारी के दौरान पांच बच्चों को बचाया गया। पुलिस ने बठिंडा में अपने बच्चों से भीख मंगवा रहे दो दंपतियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब तक इस अभियान के तहत राज्य में 208 बच्चों को बचाया जा चुका है।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि छापेमारी में फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, रूपनगर, संगरूर और श्री मुक्तसर साहिब में एक-एक बच्चा भीख मांगता पाया गया। तीन बच्चों के माता-पिता की काउंसलिंग की गई और सख्त चेतावनी दी गई कि वे भविष्य में अपने बच्चों से भीख नहीं मंगवाएंगे। दो बच्चों को बाल गृह भेजा गया। भीख मांगने वाले जिन बच्चों को छोड़ा गया है उनके लिए स्कूलों में दाखिला लेना अनिवार्य किया गया है।

'भगवान शंकर' की नगर निगम में अर्जी, वैध है मेरा मंदिर

- मंदिर प्रबंधक के जरिए हिसार नगर निगम में दाखिल किया गया जवाब

पवन सिरोवा • जागरण

हिसार : सावन में लाखों श्रद्धालुओं की स्तुति से मग्न महादेव आजकल नगर निगम की कार्रवाई से रुष्ट हैं। मामला ऐसा है कि हरियाणा के हिसार में महादेव के इंद्रप्रस्थ कालोनी स्थित मंदिर को अवैध बता नगर निगम ने नोटिस चस्पा दिया। जवाब में स्वयं महादेव के नाम पर मंदिर प्रबंधक के जरिए नगर निगम में जवाब दाखिल किया गया। जवाब में दावा प्रस्तुत किया कि मंदिर के कागजात कानूनी हैं और वैध है। अतिक्रमण के नाम पर गैर कानूनी कार्रवाई न की जाए।

दरअसल, इंद्रप्रस्थ कालोनी के एक पार्क में 37 साल पहले 1988 में शिव मंदिर का निर्माण हुआ। 17 जुलाई 2025 को नगर निगम ने मंदिर को अवैध बताते हुए उस पर नोटिस चस्पा दिया। सात दिन में उसे तोड़ने के निर्देश दिए। नोटिस के जवाब में मंगलवार को एडवोकेट विनोद कुमार गुप्ता ने महादेव (भगवान शंकर की मूर्ति) के नाम पर प्रबंधक की ओर से नगर निगम को नोटिस का जवाब दिया। उनके साथ पूर्व पार्षद अनिल जैन, प्रेम खेड़ावाला और सहित ट्रस्टी प्रवीण मौजूद रहे। उन्होंने निगम एमई सुनील लांबा से मंदिर के वैध होने का दावा किया। साथ ही बताया कि एक अप्रैल 1988 को निगम के चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर ने मंदिर के नक्शे के तहत निर्माण को स्वीकृति प्रदान की थी। ऐसे में मंदिर वैध है। निगम इंजीनियर ने कहा कि मंदिर की संभाल करने वालों की ओर से जवाब आया है उस पर संज्ञान लिया जाएगा। इसी प्रकार शहर में दिए गए 14 अन्य नोटिस के जवाब में धार्मिक संस्थानों के प्रबंधक भी जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के 29 सितंबर 2009 को पारित एक आदेश के आधार पर ये नोटिस जारी किए हैं।

****

'यूएसएस इंडियानापोलिस' के डूबने से गई 900 की जान

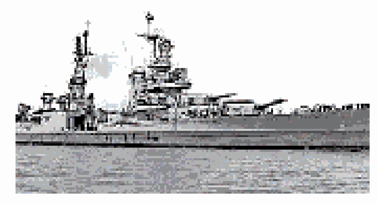

टिनियन द्वीप पर परमाणु बम लिटिल ब्वाय के कुछ हिस्सों को पहुंचाने का गुप्त मिशन पूरा कर लौट रहे यूएसएस इंडियानापोलिस जहाज को 1945 में आज ही फिलीपीन सागर में जापानी पनडुब्बी आइ-58 ने टारपीडो से उड़ा दिया था। इससे 900 लोग मारे गए थे।

उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर जीता पहला फुटबाल विश्व कप

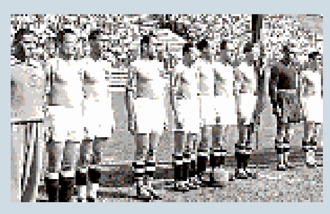

1930 में आज ही उरुग्वे में पहले फुटबाल विश्व कप फीफा का फाइनल खेला गया था। इसमें मेजबान देश उरुग्वे, अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर विश्व चैंपियन बना था। टूर्नामेंट 13 जुलाई को शुरू हुआ था। इसमें कुल 13 टीमों ने हिस्सा लिया था।

भारत की प्रथम महिला विधायक थीं मुथुलक्ष्मी रेड्डी

मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म 1886 में आज ही वर्तमान तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई में हुआ था। काफी संघर्षों के बाद पुरुषों के लिए आरक्षित महाराजा कालेज में प्रवेश लिया। स्नातक के बाद मद्रास मेडिकल कालेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला बनीं। इसके बाद तत्कालीन मद्रास के सरकारी प्रसूति एवं नेत्र चिकित्सालय में हाउस सर्जन का जिम्मा संभाला। 1926 में मद्रास विधान परिषद की सदस्य चुनी गईं। इसी के साथ ब्रिटिश भारत की पहली महिला विधायक बनने का गौरव हासिल किया। देवदासी समुदाय की लड़कियों की शिक्षा के लिए कई कदम उठाए। 1956 में पद्मभूषण से सम्मानित हुईं।

गर्मी और सर्दी को खुद नियंत्रित करेंगे स्मार्ट ग्लास

अध्ययन ▸ हल्के से विद्युत प्रवाह के जरिये बदल सकता है अपनी पारदर्शिता और रंग, बिजली की भी होगी बचत

आइआइटी इंदौर में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर किया जा रहा शोध

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर

प्रोफेसर सुमन

प्रोफेसर राजेश

आइआइटी इंदौर। फाइल

आइआइटी इंदौर के शोधकर्ताओं ने नए प्रकार का स्मार्ट ग्लास (कांच या शीशा) विकसित करने का दावा किया है। यह घरों और कार्यालयों में खिड़कियों के उपयोग के तरीके को बदल सकता है। यह स्मार्ट ग्लास रोशनी और गर्मी को स्वयं नियंत्रित भी कर सकता है। इससे पर्दों की जरूरत धीरे-धीरे खत्म हो सकती है। यह कांच एक खास किस्म की कोटिंग से तैयार किया गया है जो हल्के से विद्युत प्रवाह के जरिये अपनी पारदर्शिता और रंग बदल सकता है। जब सूरज की रोशनी तेज हो तो यह स्वयं गहरा हो जाता है ताकि कम रोशनी और गर्मी अंदर आए। वहीं बाहर ठंड हो या कम रोशनी होने यह ग्लास फिर से हल्का (पारदर्शी) हो जाता है ताकि रोशनी और गर्मी अंदर आ सके।

शोधकर्ताओं के अनुसार, इस स्मार्ट ग्लास को वायलोजन-बेस्ड पारास आर्गेनिक पालिमर (पीओपी) की मदद से तैयार किया गया है। यह नया पदार्थ टिकाऊ है और बहुत तेजी से बिजली के संकेत पर प्रतिक्रिया भी करता है। इसे कांच की सतह पर स्प्रे कोटिंग या डिप कोटिंग तकनीक से लगाया जाता है। इससे यह अच्छी तरह चिपकता है और लंबे समय तक चलता है और प्रभाव बरकरार रहता है। इसके बाद इसे दो पारदर्शी इलेक्ट्रोड के बीच रखा जाता है जो हल्के से विद्युत संकेत पर रंग बदलने लगते हैं। इस तकनीक को फिलहाल प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक जांचा गया है। अब छोटे-छोटे कांच के नमूनों पर यह देखा जा रहा है कि ये कितनी तेजी से रंग बदलते हैं। कितने साफ दिखते हैं और गर्मी व रोशनी के बीच कैसे काम करते हैं। यह शोध प्रोजेक्ट रसायन विज्ञान विभाग की प्रो. सुमन मुखोपाध्याय और भौतिकी विभाग के प्रो. राजेश कुमार के मार्गदर्शन में चल रहा है। इसे डा. सायंतन सरकार ट्रांसलेशनल रिसर्च फैलोशिप योजना के तहत विकसित किया जा रहा है।

भविष्य में उपयोग : आइआइटी इंदौर का यह शोध जल्द ही स्मार्ट होम्स, ग्रीन बिल्डिंग्स और ऊर्जा बचत वाले आफिसों में उपयोग किया जा सकता है। लोगों की आर्थिक समस्याओं को इससे बल मिलेगा। साथ ही पर्यावरण के लिए भी यह वरदान साबित हो सकता है। इससे बिजली की खपत भी कम होगी। निदेशक प्रो. सुहास एस. जोशी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि शोधकर्ता समाज के लिए कैसे उपयोगी तकनीक विकसित कर रहे हैं, वहीं प्रो. मुखोपाध्याय और राजेश कुमार ने भी इसे भविष्य की जरूरत के लिए एक मजबूत कदम बताया।

जानें खासियत

- स्मार्ट ग्लास रोशनी और गर्मी को नियंत्रित कर ऊर्जा की बचत करता है क्योंकि इससे एयर कंडीशनर और बिजली का कम इस्तेमाल होता है।
- यह गोपनीयता (प्राइवेसी) और आराम दोनों देता है।
- सामान्य पर्दों और विंडो फिल्म की तरह नहीं है बल्कि यह पर्यावरण के अनुसार खुद को अनुकूलित करता है।
- इसे बड़ी आसानी से मौजूदा फैक्ट्रियों में बनाया जा सकता है। यानी उत्पादन शुरू करना आसान होगा।

आसमान में उड़ते 'सपने'

फ्रांस के हैजविल में शामब्ले बूसिएर हवाई अड्डे के ऊपर पहला 'एनवोल' हाट एयर बैलून फेस्टिवल आयोजित किया गया। जोकर-कार्टून समेत विभिन्न आकृतियों वाले रंग-बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ते हुए मानों सपनों को पंख देते दिख रहे थे। एएफपी

इधर-उधर की

अपनी बैट्रियां खुद बदल लेता है मानवरूपी रोबोट

बीजिंग, एजेंसी: चीन में बना वाकर एस2 मानवरूपी रोबोट अपनी बैट्रियों को खुद बदलने की क्षमता के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें, पारंपरिक रोबोटों को बैट्री बदलने या प्लग इन करने की आवश्यकता होती है जिससे उनका कार्य बाधित होता है। इसके विपरीत, वाकर एस2 की जब बैट्री खत्म होने लगती है तो यह रिचार्ज करने के लिए पास के एक स्वैप स्टेशन पर चला जाता है। फिर अपना धड़ घुमाता है, अपनी भुजाओं पर लगे उपकरणों का इस्तेमाल करके खत्म हो चुकी बैट्री निकाल देता है। फिर एक नई बैट्री उठाता है, उसे प्लग इन करता है। यह विशेषता इसे साल के 365 दिन, 24 घंटे काम करने में सक्षम बनाती है।

24 घंटे काम कर सकता है ये रोबोट। इंटरनेट मीडिया

पौधों के लिए अनुकूल हैं कुछ फंगस

- ईआरएम और एमएफआरई पौधों के साथ बनाते हैं लाभकारी संबंध
- यूनिवर्सिटी आफ शेफील्ड ने माइकोरिजल फंगस के उपयोगिता का लगाया पता
- कहा, पौधों को मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करने में मदद करने में करते हैं मदद

प्रतीकात्मक

लंदन, प्रेट्र : फंगस को आमतौर पर पौधों के लिए हानिकारक माना सकता है लेकिन कुछ फंगस पौधों के लिए फायदेमंद भी होते हैं। इन्हीं में से एक है माइकोरिजल। यह तथ्य हाल ही में यूनिवर्सिटी आफ शेफील्ड द्वारा किए गए एक अध्ययन के दौरान सामने आया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, माइकोरिजल फंगस जड़ के सिरे के चारों ओर बढ़ते हैं और जड़ कोशिकाओं के बीच जाल बनाते हैं या जड़ कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं फिर उनके अंदर संरचनाएं बनाते हैं। ये मिट्टी से फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों को इकट्ठा करते हैं और इसके बदले में पौधों से कार्बन प्राप्त करते हैं। इन अज्ञात फंगस के निशान अक्सर मिट्टी के डीएनए में पाए जाते हैं।

शोधकर्ताओं ने कहा कि ऐसा ही एक फंगस है जिसे फ्लाई एगारिक कहते हैं जो लाल और सफेद धब्बेदार टोस्टूल का उत्पादन करता है। यह आमतौर पर बर्च, पाइन और स्प्रूस के साथ जुड़ता है, विशेष रूप से ठंडे जलवायु में, जिससे पेड़ों को पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी में जीवित रहने में मदद मिलती है। इसके अलावा शोध में ईआरएम और एमएफआरई की विशेषताओं के बारे में बताया गया। ये पौधों की जड़ों के क्षेत्र को बढ़ाते हैं जिससे वे मिट्टी से अधिक पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाते हैं।

खास है ईआरएम और एमएफआरई

ईआरएम (एरिकाइड माइकोरिजल फंगस) कई एरिकेशियस झाड़ियों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं जिसमें हीथर, क्रैनबेरी और रोडोडेंड्रन शामिल हैं। ये दुनिया के कुछ सबसे कठोर परिदृश्यों में प्रमुख होते हैं जिसमें आर्कटिक टुंड्रा, बोरियल वन (जिसे बर्फ का जंगल भी कहा जाता है), दलदल और पहाड़ शामिल हैं। वहीं एमएफआरई (म्यूकोरोमायकोटिना फाइन रूट एंडोफाइट्स) भी ऐसा रहस्यमय फंगस समूह है जो पौधों के साथ लाभकारी संबंध बनाते हैं। ये पौधों को मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करने में मदद करने में महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं।

कुत्तों की टीवी देखने की आदत बता सकती हैं उनका व्यवहार

नई दिल्ली, प्रेट्र: कुत्तों की टीवी देखने की आदतों से उनके स्वभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह दावा अमेरिका के आबर्न विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की ओर से किए गए एक सर्वेक्षण के बाद किया गया। साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में सामने आया कि एक चिंतित कुत्ता कार या दरवाजे की घंटी की आवाज पर अधिक प्रतिक्रिया कर सकता है जबकि एक उत्साही कुत्ता स्क्रीन पर वस्तुओं का अधिक अनुसरण करने की संभावना रखता है।

इस दौरान लगभग 650 कुत्तों के मालिकों ने अपने कुत्तों की टीवी देखने की आदतों का अवलोकन करने के बाद सर्वेक्षणों का उत्तर दिया। लेखकों ने लिखा, 'जो कुत्ते अधिक डरपोक प्रवृत्ति के थे, वे गैर-जानवर उत्तेजनाओं (जैसे, कार, दरवाजे की घंटी) पर अधिक प्रतिक्रिया कर रहे थे।

मोटापे पर ध्यान देकर रोक सकते हैं लिवर कैंसर के कई मामले

अनुसंधान

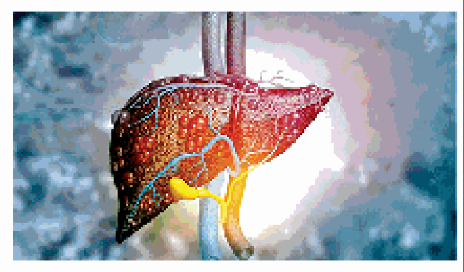

प्रतीकात्मक

जनसंख्या और बढ़ते जोखिम कारकों से वैश्विक स्तर पर लिवर कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। लैंसेट के अध्ययन में आशंका जताई गई है कि 2040 तक ऐसे मामलों में 55 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। शोध में कहा गया है कि दुनिया में हर पांच में से तीन लिवर कैंसर के मामलों को वायरल हेपेटाइटिस, मोटापे और शराब की लत जैसे जोखिम कारकों को लक्षित करके रोका जा सकता है।

लैंसेट की इस रिपोर्ट को हांगकांग कैंसर संस्थान, फुदान विश्वविद्यालय और चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और यूरोप के अन्य शोधकर्ताओं ने लिखा है। शोध दल ने पाया कि एक गंभीर रूप के मेटाबालिक डिसफंक्शन से संबंधित स्टीटोहेपेटाइटिस के कारण लिवर कैंसर के मामलों में वृद्धि हो सकती है, यह स्थिति लिवर में अतिरिक्त वसा के कारण होती है। जर्नल आफ हेपेटोलाजी में प्रकाशित एक अध्ययन पाया गया कि लिवर कैंसर 46 देशों में कैंसर से होने वाली मौतों के शीर्ष तीन प्रकारों में से एक है।

चाइनीज यूनिवर्सिटी आफ हांगकांग में क्लीनिकल आंकोलाजी विभाग के प्रोफेसर व शोध के पहले लेखक स्टीफन चान ने कहा कि अमेरिका, यूरोप और एशिया में डायबिटीज और मोटापे से ग्रस्त लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए फैटी लिवर स्थितियों के बढ़ते जोखिम के बारे में सार्वजनिक, चिकित्सा और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। (प्रेट्र)

स्क्रीन शाट

टाइम मशीन मिले तो यहां जाना चाहेंगी प्रियंका

जो समय बीत गया, वह लौट कर नहीं आ सकता है। फिर भी सितारों से कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिससे उनके दिल में छुपी हुई बातें सामने आ जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ, जब एक फोटो शूट के दौरान उनसे पूछा गया कि अगर उनके पास होती टाइम मशीन तो वह किस दौर में जाना चाहतीं? इस सवाल के जवाब में प्रियंका कहती हैं कि मैं अपने डैड के साथ घूमना-फिरना चाहूंगी। मैं उन्हें बहुत याद करती हूं। वह बहुत ही मजेदार व्यक्ति थे। साल 2000 के मध्य में जाना चाहूंगी। उस दौरान वह बहुत खुश रहा करते थे। 15 साल बाद प्रियंका क्या करना चाहेंगी? इस पर वह हंसते हुए कहती हैं कि मैं जिंदा और स्वस्थ रहना चाहती हूं। खुश और संतुष्ट रहना चाहती हूं। बढ़ती उम्र के साथ प्रियंका खुद में क्या बदलाव करना चाहेंगी? इस पर वह कहती हैं कि मैं कई बार निर्णय लेने के बाद सोचती हूं जो अच्छी बात नहीं है। दो दिन बाद सोचती हूं ये ऐसे करना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए था। बढ़ती उम्र के साथ अहसास हो रहा है कि कहीं कूदने से पहले सोचना चाहिए। प्रियंका को किस बात से डर लगता है? इस सवाल पर वह कहती हैं कि परिवार को खोने के अहसास से डर लगता है।

प्रियंका को लगा रहता है परिवार को खोने का डर। फाइल

...इस झूठ के लिए आमिर ने मांगी माफी

« आमिर टाकिज के जरिये हर हिंदुस्तानी तक अपनी फिल्में पहुंचाना चाहते हैं आमिर ● मिडडे आर्काइव

अभिनेता आमिर खान अपनी फिल्मों के लिए नया बिजनेस माडल लेकर आए हैं। कई दिनों से चर्चा थी कि आमिर अपनी फिल्म सितारे जमीन पर को यूट्यूब पर लेकर आएंगे। इस खबर को पहले आमिर ने गलत बताया था। अब उन्होंने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। साथ ही पहले खबर को गलत बताने की वजह भी बताई। एक अगस्त को सितारे जमीन पर फिल्म आमिर के यूट्यूब चैनल आमिर टाकीज पर पे पर व्यू के तहत सौ रुपये में 38 देशों में देखी जा सकेगी। हालांकि हर देश के लिए दाम अलग होंगे। आमिर का कहना है कि वह सिनेमा को किफायती दाम में दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं।

फिल्म को डिजिटल प्लेटफार्म पर देने के लिए अच्छे पैसे आफर हुए थे

ओटीटी के बजाय इस फिल्म को यूट्यूब पर लाने का कारण बताते हुए आमिर ने कहा, '15 साल पहले मेरे सामने एक आंकड़ा आया था कि 140 करोड़ की आबादी में जो सबसे बड़ी हिट थी, उसे भी केवल तीन से साढ़े तीन करोड़ लोगों ने ही देखा था। यानी आबादी के ढाई से तीन प्रतिशत लोग ही थिएटर में आते हैं। सवाल आया कि बाकी 97 प्रतिशत तक हम कैसे पहुंचेंगे। मुझे ओटीटी से बैर नहीं है लेकिन उसका समय मुझे सूट नहीं करता है इसलिए मैं हट गया हूं। यह बात सही है कि मुझे इस फिल्म को डिजिटल पर देने के लिए अच्छे पैसे आफर हुए थे। मुझे 125 करोड़ रुपये नहीं चाहिए। मुझे अपने दर्शकों से सौ रुपये चाहिए। मुझे अपने दर्शकों और अपने काम पर भरोसा है। इससे सिनेमा को नुकसान हो रहा है। जिस चीज से इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है लेकिन मेरे अकेले का फायदा हो रहा है तो वो डील मुझे करनी नहीं आती है।'

थिएटर का बिजनेस बचाना था

जब सितारे जमीन पर फिल्म सिनेमाघरों में थी तब आमिर ने यूट्यूब पर पे व्यू के तहत फिल्म लाने से इन्कार किया था। अब उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, 'मुझे थिएटर का बिजनेस बचाना था। मेरी शुरुआत सिनेमा से ही हुई है। मुझे झूठ कहना पड़ा था वरना मेरा सपना वहीं खत्म हो जाता।'

ऐसे तय हुआ सौ रुपये का दाम : सौ रुपये दाम रखने को लेकर आमिर ने कहा, 'ये कीमत फिल्म के बजट और दर्शकों के लिए किफायती बनाने को लेकर रखी है। पहले सिनेमा को मास मीडियम कहा जाता था लेकिन अब कई दर्शक इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। मैं सिनेमा को दोबारा मास मीडियम बनाना चाह रहा हूं।'

...ऐसी फिल्मों को अपने चैनल पर डालेंगे

आमिर अपने प्रोडक्शन हाउस तले बनीं अन्य फिल्में भी आमिर टाकीज पर डालेंगे। वह कहते हैं, 'यह वो जगह है, जहां आप आमिर खान प्रोडक्शन की सारी फिल्में देख पाएंगे। सौ रुपये देकर फिल्म को रेंट कर सकते हैं। 30 दिनों तक वह फिल्म आपके पास रहेगी। एक अगस्त को केवल सितारे जमीन पर आएगी, उसके एक हफ्ते बाद और फिल्में शामिल करेंगे। मेरे पिता ताहिर हुसैन की कई फिल्में करवां, अनामिका भी वहां देखी जा सकेंगी। कई कंटेंट मुफ्त में होंगे, जिसमें मेरा शो सत्यमेव जयते शामिल होगा। इसके अलावा नई प्रतिभाओं को भी अपने प्लेटफार्म देंगे। अगर हमें किसी युवा की बनाई फिल्म पसंद आती है, जिन्हें प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है, तो हम अपने चैनल पर उसे भी डालेंगे। ताकि वह लोगों तक पहुंच सके। जो पैसे पे विव्यू से मिलेंगे, उसका ज्यादातर हिस्सा उसके कलाकारों, निर्माता, निर्देशक को मिलेगा।'

इस तरह फिल्म पूरी होने के बाद रमता जोगी.. गाना बना ताल का हिस्सा

साल 1999 में प्रदर्शित फिल्म ताल का गाना रमता जोगी.. बड़ा हिट हुआ था। हालांकि, संगीतकार ए आर रहमान द्वारा संगीतबद्ध यह गाना पहले ताल फिल्म का हिस्सा ही नहीं था। इस गाना को सुभाष घई के निर्देशन में बनी इस फिल्म को पूरी होने के बाद शामिल किया गया था। ये बातें गाने के गायक सुखविंदर सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में साझा किया। उन्होंने गाने बारे में बताया कि पहले रमता जोगी फिल्म ताल का हिस्सा नहीं था। ए आर रहमान को सुभाष घई साहब बोला करते थे कि ये रमता है। फिर एक दिन रहमान ने पूछ लिया कि ये रमता का मतलब क्या होता है? फिर मैंने उन्हें समझाना शुरू कर दिया कि ये होता है रमता। जैसे आप हवा को मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते हैं लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं। वैसे ही रमता, एक मलंग इंसान है जिसे आप कहीं रोक कर नहीं रख सकते हैं। किसी तरह से मैंने उन्हें रमता का मतलब समझाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो इस पर एक गाना बनाते हैं। तब तक ताल फिल्म के सारे गाने हो चुके थे, फिल्म पूरी हो चुकी थी। तब वो गाना बना। सुभाष जी को यह गाना पसंद आया तो उन्होंने शूट करके इस गाने को फिल्म में शामिल किया।'

कई हिट गाने गा चुके हैं सुखविंदर। इंस्टाग्राम (@sukhwindersinghofficial)

इसलिए सानविका ने किया था इनसाइडर के संघर्ष वाला पोस्ट

वेब सीरीज पंचायत में रिंकी की भूमिका से खूब लोकप्रियता बटोरने वाली अभिनेत्री सानविका ने कुछ सप्ताह पहले इंस्टाग्राम पर साझा की अपनी एक स्टोरी से खूब चर्चा बटोरी थी। यह स्टोरी इनसाइडर्स (सिनेमाई पृष्ठभूमि से जुड़े परिवारों से आए) और आउटसाइडर्स को लेकर थी। सानविका ने लिखा था कि कभी-कभी मैं सोचती हूं कि काश मैं भी कोई इनसाइडर होती या किसी ताकतवर पृष्ठभूमि से जुड़ी होती तो चीजें बहुत आसान होतीं (शायद, पता नहीं)। जैसे बराबरी का सम्मान और व्यवहार जैसी बुनियादी चीजें भी मिलतीं। संघर्ष कम होता।' अब सानविका ने अपनी इस पोस्ट के बारे में बताया कि उन्होंने आहत हो कर इसे लिखा था। वह बताती हैं, 'मैंने यह किसी दूसरे संदर्भ में बोला था। फिर सभी ने उसके बारे में अपने-अपने हिसाब से लिखा। उसके बारे में और ज्यादा बोलकर मैं उसे बढ़ावा नहीं देना चाहती हूं। मैं बस इतना कहूंगी कि उस समय मैं किसी बात से आहत थी। तब मुझे वह बातें बोलनी थी तो मैंने बोल दी। हालांकि, ऐसा नहीं है कि मुझे काम नहीं मिल रहा है या मुझे किसी स्टारकिड या इनसाइडर से समस्या है। मुझे किसी से कोई समस्या नहीं है।' पंचायत के अलावा आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर सानविका बताती हैं कि अगले साल लोग मुझे एक नए शो में तथा अगले एक-डेढ़ साल में अपने करीबी सिनेमाघरों में एक फिल्म में देखेंगे।

पंचायत 4 में फिर नजर आएंगी सानविका। फाइल

फिर रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में आई सारा अली खान

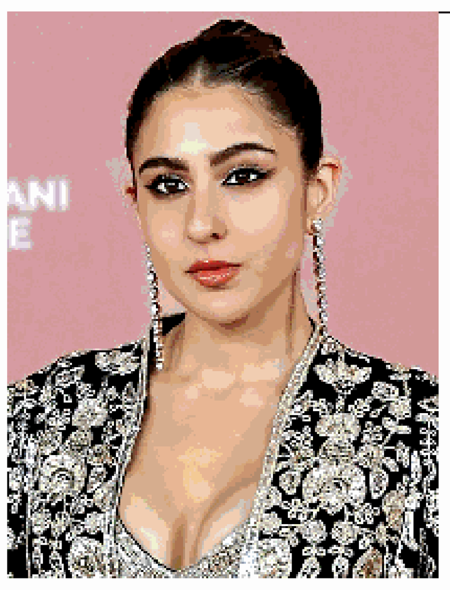

आगामी दिनों में फिल्म वन में नजर आएंगी सारा। फाइल

कलाकारों की पेशेवर और व्यक्तिगत जिंदगी में क्या हो रहा है, उनके प्रशंसक हर चीज जानना चाहते हैं। तभी तो एक के बाद एक कड़ियां जोड़ते हुए उन बातों तक भी पहुंच जाते हैं, जिनके बारे में सितारे ने कभी चर्चा भी नहीं की होती है। अभिनेत्री सारा अली खान पिछली कुछ छुट्टियों की तस्वीरों में एक व्यक्ति अक्सर दिखाई दिया। वह है अर्जुन प्रताप बाजवा। ऐसे में सारा और अर्जुन के रिलेशनशिप की खबरों के कयास लगाए गए। इन खबरों को और हवा मिली तब, जब हाल ही में सारा और अर्जुन दिल्ली के एक गुरुद्वारे में मत्था टेकने एक साथ पहुंचे। दोनों में से किसी ने भी अभी तक इस रिश्ते के बारे में आधिकारिक तौर पर बोला तो नहीं है लेकिन दोनों के रिलेशनशिप की खबरें फिलहाल खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। राजनीतिक परिवार से आने वाले अर्जुन राजनीति, सिनेमा और संगीत तीनों क्षेत्रों से जुड़ाव रखते हैं। साल 2018 में वह पंजाब जिला परिषद के सबसे युवा सदस्य बने थे। उसके बाद उन्होंने सिनेमा और माडलिंग में दिलचस्पी दिखाई और कुछ जगहों पर माडलिंग करने के बाद फिल्म सिंह इज ब्लिंग में निर्देशक प्रभु देवा को असिस्ट किया। फिर उन्होंने फिल्म बैंड आफ महाराजास से अभिनय में कदम रखा और इन दिनों बतौर संगीतकार इंडिपेंडेंट गानों पर काम कर रहे हैं। वहीं सारा आगामी दिनों में फिल्म वन : फोर्स आफ फारेस्ट में नजर आएंगी।

दोबारा सीन शूट करने से अनुराग ने किया इन्कार

फिल्म की 40 प्रतिशत शूटिंग हो चुकी है। अगस्त-सितंबर में कार्तिक के साथ अगले शेड्यूल की शूटिंग शुरू होगी जिसमें कार्तिक क्लीन शेव में होंगे।

मिडडे आर्काइव

मोहित सूरी के निर्देशन में बनी सैयारा की सफलता का प्रभाव इन दिनों दूसरी फिल्मों पर भी दिख रहा है। सैयारा फिल्म एक राकस्टार लड़के और अल्जाइमर्स (भूलने की बीमारी) से पीड़ित एक लड़की की प्रेम कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्मकार अनुराग बासु के निर्देशन में बन रही कार्तिक आर्यन अभिनीत फिल्म भी एक राकस्टार की प्रेम कहानी है। दोनों में समानताओं को देखते हुए कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सैयारा की सफलता के बाद निर्माताओं ने कार्तिक की इस फिल्म के कुछ सीन पर दोबारा लिखे जाने और शूट किए जाने का निर्णय लिया है। हालांकि, अब अनुराग ने ऐसी किसी भी संभावना से इन्कार किया है। इस बारे में हाल ही में उन्होंने कहा, 'हम दोनों की फिल्म सिर्फ यही समानता है कि दोनों का नायक राकस्टार है। मेरी फिल्म में लड़की को कोई बीमारी नहीं है। हम फिल्म को दोबारा लिख या शूट नहीं कर रहे हैं। मुझे सैयारा रिलीज होने से पहले ही पता था कि उसमें लड़की को अल्जाइमर है, तो मैं अपनी फिल्म में भला वही क्यों लिखूंगा। फिल्म की 40 प्रतिशत शूटिंग हो चुकी है। अगस्त-सितंबर में अगले शेड्यूल की शूटिंग शुरू होगी।'

मनोरंजन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

****